Haryana Vidhan Sabha

Debates

15th February, 1971

Vol. I-No. 7

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 15th February, 1971

	Page
Starred Question and Answers	(7)1
Written Answers to Starred Questions laid on the Table under Rules 45	(7)24
Message from the Governor	(7)25
Ruling given by the Speaker	(7)25
Call Attention Notices	(7)26
General Discussion on the Budget for the year 1971-72	(7)26
Variation in the allocation of Time Order	(7)79
General Discussion on the Budget for the year 1971-72 (Resumption)	(7)79-81

HARYANA VIDHAN SABHA

Monday, the 15th February, 1971

The Vidhan Sabha Met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhawan, Sector-1, Chandigarh, at 2.00 P.M. of the Clock. Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Agricultural Land with the Panchayats

***1116. Sh. Daya Krishan**: Will the Minister for Development be pleased to State –

(a) the total area of agricultural land with the Panchayats on the 1st January, 1971;

(b) whether it is a fact that the land referred to in the part (a0 above is not being properly managed by the Panchayats and the Government is considering a proposal to take over the management of the said land;

(c) if so, the details of the said proposal together with the time within which it is likely to be finalised; and

(d) whether it is a fact that non-Harijans outbid that Harijans in open auction of the land specified in part (a) above, if so, the steps, if any, proposed to be taken by the Government of ensuring that the said land is given to Harijans proportionately?

Development Minister (Sh. Sarup Singh): (a) 204173 acres.

(b) This is not correct in every case, but in certain cases the shamilat lands are not properly managed by the Panchayats.

The Government has decided to take over management of shamilat lands of Panchayats where there are not managed properly.

(c) A Bill, enabling the Government to take over management of shamilat lands for a period not exceeding 20 years, is being introduced in the current session of the Vidhan Sabha.

(d) One-third area of cultivable shamilat land is reserved for lease to scheduled castes only and the non-harijans cannot offer bid in the auction of such reserved area. In case of the remaining two-third, every body is entitled to participate in the auction and the highest bidder is given the land under the rules.

श्री दया कृष्ण: क्या वजीर साहब बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त पंचायतों को जमीनों से कितनी आमदनी है और अगर गवर्नमैंट उसका मैनेजमैंट अपने हाथ में ले ले तो कितनी आमदनी होने की उम्मीद है?

श्री सरूप सिंह: स्पीकर साहब, 1967–68 और 1968–69 की फिगर्ज मेरे पास हैं। 1967–68 में 1 करोड़, 24 लाख, 71 हजार, 9 सौ 55 और 1968–69 में 1 करोड़, 39 लाख, 84 हजार 20 रूपये की आमदनी हुई है। हमारा ख्याल है कि अगर सरकार पंचायतों की जमीनों का मैनेजमैंट अपने हाथ में ले लेगी तो आमदनी दुगनी जरूर हो जायेगी।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, सवाल के पार्ट 'बी' के जवाब में वजीर साहब ने कहा कि कुछ पंचायतों के फार्मज का जो

मैनेजमैंट है, वह गवर्नमैंट अपने हाथ में लेगी, क्या मैं जान सकती हूं कि किस कानून या एक्ट के तहत गवर्नमैंट पंचायतों की जमीनों का मैनेजमैंट अपने हाथ में ले सकती है?

श्री सरूप सिंह: स्पीकर साहब, एक हम नया मैनेजमैंट ला इसी सैशन में ला रहे है, उके तहत सरकार पंचायतों की जमीनों का मैनेजमैंट अपने हाथ में ले सकेगी।

श्री बनारसी दास गुप्ता: क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि उनके नोटिस में कुछ ऐसी शिकायतें भी आयी हैं कि कुछ पंचायतें जमीन का मिसयूज करती हैं और अपने मिलने वालों या रिश्तेदारों को सस्ते दामों पर जमीन रिलीज कर देती हैं?

श्री सरूप सिंह: स्पीकर साहिब, इसी वजह से हम उनसे मैनेजमैंट ले रहे हैं क्योंकि उनका मैनेजमैंट प्रापर नहीं है।

चौ. दल सिंह: क्या यह दरूस्त नहीं है कि जो जमीन पहले पंचायत अपने आदमियों को देती थी, अब वही जमीन सरकार अपने आदमियों को देगी?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): स्पीकर साहब, ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या वजीर साहब बताएंगे कि जैसे पंच और सरपंच जो अपनी ताकतों का मिसयूज कर रहे हैं, उनके

लिये तो एक्ट ला रहे हैं, अगर कुछ एम.एल.ए. भी अपनी ताकतों का मिसयूज करते हैं तो क्या हमारी भी ताकतों को करने के लिये कोई एक्ट लाने का सरकार का इरादा है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री खुरशीद अहमद): यह तो हाउस को अख्तियार है। (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब, मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं आया।

श्री सरूप सिंह: यह अख्तियार तो स्पीकर साहिब को है क्योंकि स्पीकर साहब हाउस के कस्टोडियन हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: I want to know कि क्या गवर्नमैंट इस तरह का कोइ इनीशियेटिव लेगी?

Mr. Speaker: Your question is not clear.

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब वजीर साहब ने अपने जवाब में यह कहा है कि कुछ पंचायतें मिस–मैजमैंट कर रही हैं और उनके लिये हमारा एक ऐक्ट लाने का इरादा है, क्योंकि बिना एक्ट के तो पंचायतों के फार्मज को यह नहीं ले सकते जिसमें कि पंच और सरपंच अफैक्ट होते हैं इसलिये उनके अधिकारों को, उनकी पावज्र का छीनने के लिये यह एक्ट ला रहे हैं। मैंने वजीर साहब से यह पूछा है कि अगर हम लोग भी पावन का मिसयूज करें तो हमारी

पावर्ज को करटेल करने के लिए सरकार का क्या कोई बिल लाने का इरादा है?

श्री सरूप सिंह: मेरे जवाब से तो यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Mr. Speaker: We have not heard.

श्री सरूप सिंह: स्पीकर साहब, यह जो सप्लीमैन्टरी इन्होंने उठाया है, इसका मेरे जवाब से कोई वास्ता नहीं है।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, यह बताते हैं कि वन–थर्ड जो शामलातदेह की जमीन है, वह हरिजनों के लिये रिजवर्ड हैं कुछ देहातों में यह देखने में आया है कि एग्रीकल्चरिस्ट अपनी तरफ से कुछ हरिजनों को बिड देने के लिये खड़ा कर देते हैं और वह हरिजन बिड दे देते हैं और उसका एक्चुअल बैनीफिशयिरी एग्रीकल्चरिस्ट को होता है। क्या सरकार इस किस्म की चीजों को रोकने के लिये कोई इंतजाम करेगी?

श्री सरूप सिंह: यह प्रैक्टिस कई जगह देखते में आयी थी। इसी वजह से हम यह मैनेजमैंट बिल ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: इसका तो कोई इलाज नहीं मालूम पड़ता है जिससे यह चीज खतम हो सके।

चौ. रणबीर सिंह: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि कितनी पंचायतों के खिलाफ यह शिकायत है कि वह जमीन का इंतजाम सही नहीं कर रही हैं और ऐसी जमीन की एकड़ेज कितनी है?

श्री सरूप सिंह: यह तो अगर सैपरेट नोटिस दें, तो बताया जा सकता है। इस समय मेरे पास यह सूचना नहीं है। स्पीकर साहब, कुछ पंचायतों के मैं नाम बता सकता हूं। फिलहाल 4–5 पंचायतें ऐसी जरूर हैं जिनके खिलाफ शिकायतें हैं। एक तो कोडनी, दूसरी कोडड़ा मनाना करनाल जिले की, मातन सिसाना रोहतक जिले की और रतेड़ा हिसार जिले की।

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, मैंने इनसे पंचायतों के नाम नहीं पूछे थे। मैंने तो यह पूछा था कि कितनी पंचायतों के खिलाफ सरकार के पास शिकायतें आयी हैं कि वह अच्छा इंतजाम नहीं कर रही है और वह एरिया कितने एकड़ेज बनता है जिसका कि ठीक से इंतजाम नहीं हो रहा है?

श्री अध्यक्ष: चौ. साहब वह जबाव दे चुके हैं कि उनके पास यह इन्फार्मेशन नहीं है हालांकि यह इन्फर्मेशन उनके पास हो सकती है लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकार के पास 4–5 गांवों की पंचायतों के बारे में यह शिकायत आयी है। बाकी की इन्फर्मेशन उनके पास नहीं है।

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने तो गांव के नाम बताए हैं, मैंने तो गांव के नाम पूछे ही नहीं हैं। मैंने तो यह

पूछा है कि कितनी पंचायतें ऐसी हैं जिनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। जब सरकार एक बड़ा अहम बिल लाने जा रही है, तो उनके पाास इस बारे में सूचना होनी चाहिए कि कितनी पंचायतों के बारे में शिकायतें हैं और कितना इलाका है जिसका कि ठीक तरीके से इंतजाम नहीं हो रहा है। इन्होंने सवाल के जवाब में यह बताया कि हम इस बारे में कानून बनाने जा रहे है। प्रजातंत्र में हर काम ढंग से करना चाहिए। इनके पास इतना तो ब्योरा हो ही सकता था कि इतनी पंचायतों का काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है और इतने एकड़ वह इलाका है जिसका इंतजाम ठीक से नहीं हो रहा।

श्री अध्यक्ष: आपका सवाल वैसे रैलेवैट है लेकिन उनके पास इन्फर्मेशन नहीं है। 5 गांवों के नाम उन्होंने बता दिये हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मैं वजीर साहब से जान सकती हूं कि मेजौरिटी आफ पंचायतस मिसमैनेजमैंट कर रही हैं या माइनारटी आफ पंचायतस मिसमैनेजमैट कर रही हैं। कितनी फीसदी ऐसी पंचायतें हैं जिनका मैनेजमैंट खराब है।

श्री सरूप सिंह: स्पीकर साहब, जो बिल हम ला रहे हैं यह एक अमैन्डिंग बिल है। इसका मतलब यह नहीं है कि सब पंचायतों की जमीनें लेकर उनका मैनेजमैंट सरकारी तौर पर करेंगे। जहां–जहां से मिसमैनेजमैंट की शिकायत आयेगी, वहां–वहां हम ऐसा करेंगे।

चौ. चन्दा सिंह: स्पीकर साहिब, पंचायतों में जो पंच या सरपंच चुनकर आते हैं, उनको मैनेजमैंट बगैरा करने की कोई खास ट्रेनिंग नहीं होती है। इसलिए यही वे गल्तियां करके भी कोई काम सीखते हैं, तो उनको सीखने देना चाहिए। जिस भाव को लेकर जिला परिषदें वगैरा बनायी गयी हैं कि बड़े अफसर उनको टैक्नीकल गाइडैस दें, उनकी सुपरवीजन करें, उस भाव को कायम रखना चाहिए न कि उनके अधिकारों को समाप्त करके ही अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: क्या आपका यह सुजैशन है?

चौ. चन्दा सिंह: जी हां। इस बिल के पास हो जाने पर यह स्टेट हैडक्वार्टर पर या डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर बैठकर पंचायतों का इंतजाम करेंगे, यह अच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: इसके बारे में यह बिल ला रहे हैं, जब वह आयेगा तब आप कह लेना।

चौधरी दल सिंह: क्या मैं वजीर साहिब से पूछ सकता हूं कि जब गवर्नमैंट पंचायतों की जमीन का मैनेजमैंट अपने हाथ में लेगी तो उससे होने वाली आमदनी कहां जायेगी ?

श्री सरूप सिंह: पंचायत के ग्राम फंड में जमा की जाएगी।

चौधरी दल सिंहः सरकार यह कैसे पता लगाएगी कि पंचायत का मैनेजमैंट ठीक नहीं है और उसमें नुक्स है ?

श्री सरूप सिंहः वह तो साथियों से पता चलेगा।

श्री अध्यक्षः कुछ के बारे में शिकायत आ जाएगी।

चौधरी दल सिंहः जहां सरकार तो कहती है कि पंचायत का मैनेजमैंट ठीक नहीं है और पंचायत कहती है कि इन्तजाम ठीक है, ऐसी हालत में कौन सी बात ठीक होगी ?

श्री सरूप सिंहः पंचायतों के अन्दर बहुत दफा सरपंच इल्लिटरेट होते हैं, उस वजह से कई दफा लीज पर जमीनादि देते हैं तो बाकायदा पब्लिसिटी नहीं करते, कई दफा एक आदमी को जितनी जमीन देनी चाहिए, उससे भी ज्यादा दे देते हैं, कई दफा पंचायत की जमीन पर इल्लीगल कब्जा कर लिया जाता है तो पंचायत कोई दावा नहीं करती। तो इस तरह की चीजें देखकर ही यह फैसला किया जाता है कि पंचायत के मैनेजमैंट में नुक्स है।

चौधरी दल सिंहः गवर्नमैंट रिपोर्ट करती है कि पंचायत का इन्तजाम ठीक नहीं है एक तरफ तो यह बात है और दूसरी तरफ के मेम्बरान यह कहते हैं कि हम ठीक मैनेज करते हैं तो गवर्नमैंट वाली बात ठीक होगी या पंचायत के मेम्बरान वाली ?

श्री सरूप सिंहः पंचायतों के ऊपर ग्राम सभाएं होती हैं और उसकी एक साल में दो मीटिगें होती हैं वहां पर यह फैसला हो जायेगा कि पंचायत का मैनेजमेंट ठीक है या नहीं।

श्री अध्यक्षः परफामैंसिज पर भी दारोमदार होगा।

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के काम–काज को देखने के लिए ग्राम सभाएं होती हैं, गवर्नमैंट के अफसर ब्लाक में लगे होते हैं, पचायतों के एक्सटेनशन अफसर होते हैं, एगरीकल्चर के एक्सटेनशन अफसर होते हैं, पंचायत का सेक्रेटरी होता है, तो फिर भी जहां शिकायत आई है वहां सरकार ने पंचायतों का इन्तजाम ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्री सरूप सिंहः इन्तजाम को ठीक करने के लिए रूल्ज अमेंड किए हैं। जो जमीन लीज पर दी जाती है वह सरपंच के द्वारा दी जाती है, हमने इस बारे में रूल अमेंड किया है। अब जमीन लीज पर तो सरपंच ही देगा लेकिन वह किसी अफसर के रूबरू दी जाएगी। जो जमीनें नाजायज कबजें में हैं उनके लिए नायब तहसीलदार लगा रखे हैं, उनकी यह डयूटी है कि वे हर जगह के केसिज लेकर तैयार करें। रेवेन्यू आफीसर्ज की मीटिंगज होती हैं उनमें डिप्टी कमीशनर्ज को यह कहा गया है कि अगर कोई इस किस्म की रिक्वरी हो तो वे करा लें।

चौ. जय सिंह राठी: मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस वक्त यह एक्ट अमेंड हो जायेगा तो पंचायत की प्रापर्टी जैसे जमीन वगैरा पर कौन सी एजेन्सी का कंट्रोल होगा?

श्री सरूप सिंह: यह बिल हाउस के सामने आ रहा है उस समय इसको बता दिया जाएगा।

चौ. जय सिंह राठी: स्पीकर साहब, मैंने इनमें यह पूछा है कि जब रूल अमेंड हो जाएगा तो क्या उसके इंतजाम के लिए अलग से डिपार्टमैंट बनाया जाएगा?

श्री बंसी लाल: बिल कल आ रहा है आप इस पर कल डिस्कशन कर लेना।

चौ. चान्द राम: क्या इस बात के पेशेनजर कि पंचायतों का इंतजाम ठीक नहीं है और बहुत सी जमीन लोगों ने अपने कब्जे में की हुई है, उसको रिकवर करने के लिए सरकार उनका मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में लेगी?

श्री सरूप सिंह: जिस पंचायत की प्रापर्टी पर इल्लीगल अकूपेशन हो और जो आलरेडी लीज पर है, उसको हम उस वक्त ले सकेंगे जब उसकी मियाद खतम होगी।

चौ. चान्द राम: गवर्नमैंट यह मानती है कि मैजोरिटी आफ दी पंचायतों का इंतजाम ठीक नहीं है .....

वित्तमंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): पांच की बाबत कहा है।

चौ. चान्द रामः यह कहते हैं कि सरकार उनका मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी मेरा विचार है कि उस जमीन को निलाम करके उस पैसे को उस गांव पर ही खर्च करे तो ठीक रहेगा।

Sh. Bansi Lal: The hon. Member can give this suggestion during the discussion on the Bill which is coming up in the House tomorrow.

श्री अध्यक्षः चौ. साहब, कल बिल आ रहा है आप इस मामले में कल अपने विचार रख सकते हैं।

चौ. चान्द रामः मैं यह जानता हूं कि हरिजनों के लिए पंचायत की शामलात जमीन में से कितना हिस्सा रिजर्व रखा है और जो जमीन की निलामी होती है वह रिस्ट्रिक्टिड आक्शन से या ओपन आक्शन से होती है?

श्री सरूप सिंहः पंजाब विलिज कौमनलैंड रेगुलेशन के रूल में लिखा है कि –

"... That 1/3rd of the cultivable land proposed to be leased, shall be reserved for giving it on lease on auction to the Members of the Scheduled Castes only and if on two different dates no such person is forthcoming or the Panchayat Samiti refuses to confirm the auction under clause 2(a)(i), the reservation shall cease to have effect."

चौ. चान्द राम: मेरा सवाल यह था कि क्या यह ठीक है कि हरिजनों के नाम बेनामी बोलियां हुई हैं इस तरह से एक तरफ तो पंचायतों को नुकसान हुआ और दूसरी तरफ हरिजनों को कोई फायदा नहीं हुआ।

Sh. Bansi Lal: If the Harijans come forward, they will get the land, but what can the Government do in such cases?

Mr. Speaker: This question has been answered. Now, let me say something about it. This question was asked and in fact you will agree that it is rather very difficult for anyone to help, if this sort of thing happens. No one can shop it.

श्रीमती चन्द्रावती: ग्राम सभाओं की मीटिंग साल में दो दफा होती है क्या पंचायतों का काम ठीक तरह से चलाने के लिए इनकी मीटिंग साल में पांच बार बुलाई जा सकती है?

श्री सरूप सिंह: एक्ट के अन्दर दो दफा ही बुलाने का प्रोविजन है।

चौ. दलसिंह: हरिजनों के लिए जमीन का 1/3 हिस्सा रिजर्व रखा गया है लेकिन गांव में ऐसे भी लोग हैं जो हरिजन नहीं हैं और उनके पास जमीन बिल्कुल नहीं है क्या सरकार उस एक–तिहाई हिस्से में से उन लोगों को भी जमीन देने के लिए तैयार है?

श्री सरूप सिंह: उनको बाकी दो–तिहाई हिस्से में से ही मिल सकती है।

श्री अध्यक्ष: सवाल तो इनका अच्छा है और इस पर गौर होना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: पंचायत की शामलात जमीन के लिए जमींदार दीवानी अदालत में मुकदमा करते हैं और सरपंच उनके हक में बयान दे देते हैं, इस तरह वह जमीन जमींदारों में तकसीम हो जाती है। क्या गवर्नमैंट के नोटिस मैं है कि ऐसी कितनी जमीन है और गवर्नमैंट इसके लिए क्या कर रही है?

(No reply)

श्री सत्य नारायण सिंगोल: पहले वजीर साहब ने फरमाया था कि एक–तिहाई जमीन हरिजनों के लिए रिजर्व है लेकिन सैक्शन 6 का हवाला देकर बताया है कि अगर दो दफा हरिजन उसकी बोली न दें तो फिर वह जमीन खुली बोली में किसी और को भी दी जा सकती है। इसके अलावा यह भी एग्जेक्टिव इंस्ट्रक्शन्ज हैं कि अगर हरिजनों की बोली 80 फीसदी से कम आए तो फिर वह जमीन उनको नहीं दी जा सकती। तो क्या मैं जान सकता हूं कि इन दोनों मैं से कौन सी बात सही है?

श्री सरूप सिंह: जो रूल मैंने पढ़कर सुनाया है वह सही है।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: कुछ अरसा हुआ हमने अखबार में यह पढ़ा था कि हरियाणा सरकार ने यह एलान किया है कि आयंदा 33 फीसदी की बजाए हरिजनों को 50 फीसदी

जमीन रिजर्व बोली में दी जाएगी। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सी बात दरूस्त है?

श्री बंसी लाल: अखबारों में तो, स्पीकर साहिब, कई बातें आती रहती हैं इसलिए उनको यहां पर कैसे औथेटिक माना जा सकता है। वैसे मैं उनकी इत्तलाह के लिए बता देना चाहता हूं कि हमारा इरादा 50 फीसदी कर देने का है।

चौ. चान्द राम: जब आप का इरादा है उनको 50 फीसदी जमीन देने का तो फिर रूल्ज में तरमीम करने में क्या दिक्कत है?

श्री बंसी लाल: जब फैसला हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकती।

चौ. रणबीर सिंह: विकास मंत्री साहब ने बताया है कि अफसरों के सामने बोली का होना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की मशीनरी उस काम को ठीक ढंग से नहीं चला सकी, इसका क्या कारण है?

श्री सरूप सिंह: मिसमैनेजमैंट के कई आसपैक्ट हैं और जो आप बता रहे हैं यह उनमें से एक है। वैसे तो इसके अन्दर काफी सुधार हो गया है लेकिन बीच में लिहाज, रिश्तेदारियों भी आ जाती हैं, कब्जे नहीं छुडवाए जाते और इस तरह की कई बातें आ जाती है।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, तालाबों में जो मछलियां होती हैं जब पंचायतों वाले उनको बेचते हैं तो वह ठेकेदारों से मिलकर पैसे ज्यादा लेते हैं लेकिन शो कम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस चीज का गवर्नमैंट ने कोई इलाज सोचा है?

गृह मंत्री (श्री के.एल. पीसवाल): सिंगोल साहब आप न खाते हैं न पीते है इस आपने क्या लेना है।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: हम खाते नहीं तो बेचते तो हैं।

(सवाल को कोई जवाब नहीं दिया गया)

Mr. Speaker: I think we have had so many supplementaries on this question. We should now go on to the next question.

श्री दया कृष्ण: साल्टपीटर का ठेका भी पंचायतों वाले डायरैक्ट दे देते हैं और फिर बाद में फरजी दावे करवा के स्टे आर्डर ले लेते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस चीज को रोकने के लिए क्या सरकार कोई तजवीज रखती है?

श्री सरूप सिंह: इसके लिए सैक्शन 14(ए) में अमेंडमैंट हो चुकी है और उसकी रूसे यह काम इन्डस्ट्री वालों के तहत चला गया है और वह उसका ठेका वगैरा देते हैं लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि यह वापिस पंचायतों को दे दिया जाए।

श्री दया कृष्ण: हरिजनों के लिए जो एक–तिहाई अराजी रिजर्व की गई है उसके बेनामी बिड होने की वजह से हरिजनों को उसका उतना फायदा नहीं पहुंचता जितना कि पहुंचना चाहिए। मैं पूछता चाहता हूं कि सरकार उनको पूरा फायदा पहुंचाने के लिए कोई एक्दामात उठाने के लिए तैयार है?

श्री सरूप सिंह: अगर कोई अपने नाम पर किसी को लेकर आगे दे देता है तो वह तो खुद अपना फायदा नहीं चाहता लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक है हमारा 33 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का इरादा है।

श्री दया कृष्ण: जो बेनामी बिड होते हैं उनका क्या इलाज है?

श्री बंसी लाल: बेनामी का इलाज तब हो सकता है जब चौ. चांद राम जी अपने नाम पर जमीन लेकर मित्तल साहिब को न दें वरना तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। (हंसी)

Starred Question No. 1182

Mr. Speaker: Extension has been granted in the case of question No. *1182 standing in the name of Ch. Chand Ram.

चौ. चान्द राम: स्पीकर साहब, आप देखिए यह कितना मासूम सा सवाल है।

Mr. Speaker: Ch. Sahib, it is comming up tomorrow. However, I will mention one thing for the consideration for the hon. Ministers. I find that in the list of questions for today, there are about eight questions and extension has been asked for three questions, and I have given that.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Mr. Speaker, kindly see the questions asked. In one of the questions standing in the anem of Ch. Chand Ram in today's list, the information asked for is-

"(b) whether he has received any letter from any Legislator regarding complaints of non-payments etc., to labourers working on Rohtak-Gohana-Panipat Road; if so, a copy of the letter and action taken thereon be placed on the table of the House".

सड़क बनी को कितने दिन हो गये हैं, अब वहां पर क्या देखना है।

Mr. Speaker: I will draw the attention of the hon. Ministers to the fact that in this session comparatively we had much less number of questions and in some cases the questions were reasonably all right. In some cases, we had sent the notices of questions to the Departments concerned a month ago. (Interruptions) Kindly make a note of those questions which have been postponed beyond seventeenth. They must be answered tomorrow.

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, जहां तब चौ. चान्द राम जी के सवाल का सम्बन्ध है इसमें कोई एक्सटैनशन लेने वाली बात तो मालूम नहीं होती।

श्री बंसी लाल: अगर बात नहीं है तो फिर पूछने का क्या फायदा है। हाउस का टाईम जाया करने का क्या फायदा है।

चौ. रणबीर सिंह: यह सवाल सड़क का नहीं, बल्कि यह सवाल जो वहां पर मजदूरी करते थे उनकी उजरत का है। अगर सड़क बन गई है तो उनको मजबूरी नहीं देंगे आप?

(No reply)

Starred Question No. 1140

Mr. Speaker: Extension has also been asked for in respect of question No. *1140 by Sh. Daya Krishan.

Sh. Daya Krishan: Till tomorrow, Sir.

Mr. Speaker: No. It has been asked for till 26th.

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): स्पीकर साहब, इस 1140 नम्बर के सवाल से पहले भी एक सवाल इसी किसम का आया था और उस पर काफी सप्लीमैंटरी पूछे जा चुके हैं और जवाब दिये जा चुके हैं। वह इसी तरह का सवाल था।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने ही कहा है कि एक्सटेनशन दी जाये।

श्री बंसी लाल: मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं थी। बेहतर होता अगर इन दोनों सवालों को इकट्ठा कर दिया जाता और दोनों पर सप्लीमैंटरी पूछ लिये जाते।

Mr. Speaker: We would have gladly done .....

Sh. Bansi Lal: Now, mostly replies have been given.

विकास मंत्री (श्री सरूप सिंह): इसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं। पार्ट (ए) के बारे में काफी सप्लीमैंटरी हो चुके हैं और जवाब दिये जा चुके हैं। And in part (b) it has been asked –

"the total area of Panchayat land transferred from various Panchayats district-wise to private individuals through decrees or otherwise during the period 1st November, 1966 to 1st January, 1971 ....."

Sh. Bansi Lal: To find out about each case would be impossible.

Sh. Sarup Singh: In part (c), it has been asked –

"the total number of cases pending as on 1st January, 1971, in courts filed by private individuals for tranfer to Panchayat land to them."

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हरेक केस के बारे में सारी स्टेट से मालूम करना बड़ा मुश्किल है।

Sh. Bansi Lal: If these had been combined, it would have been better. However, he can ask supplementaries.

Mr. Speaker: I would also suggest that the question asked shoudl be such that the answer can be reasonably made available.

चौ. रणबीर सिंह: इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बेहतर होगा अगर इस सवाल को अनस्टार्ड ट्रीट कर लिया जाये और जवाब दे दिया जाए।

Mr. Speaker: Taht is up to the hon. Member who has asked the question.

Sh. Daya Krishan: It may be treated as an Unstarred one.

Mr. Speaker: Now, it will automatically become an Unstarred one when its extension has been asked for upton the 26th.

Villages without High Schools for Boys

***1160. Sh. Randhir Singh**: Will the Minister for Education be pleased to state the number of villages in Haryana where there are no Government High Schools for boys?

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): 5,684.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: वजीर साहब ने तीन चार दिन हुये एक सप्लीमैंटरी का जबाव देते हुए बताया था कि जो जो गांव कंडीशनज को पूरा करेंगे वहां स्कूल अपग्रेड कर देंगे। इसके अन्दर बहुत ज्यादा गांव बताये हैं जिनमें हाई स्कूल नहीं हैं। जिला जींद में एक सिंधाना गांव है जो तमाम कंडीशनज को पूरा करता है और उसके तीन मील तक कोई हाई स्कूल नहीं है और

वहां से रीप्रेजैटेशन भी इनके पास आई हुई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस स्कूल को अपग्रेड करेंगे?

श्री माडू सिंह मलिक: एग्जामिन करेंगे।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, एक तरफ तो हाउस में कहते हैं कि अगर कोई सारी कंडीशनज पूरी कर दे तो उसे अपग्रेड कर देंगे लेकिन दूसरी तरफ यह है कि अगर कोई सारी कंडीशनज को पूरा करता हो तो कहते हैं कि सोचेंगे। आखिर बात क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): अगर बहुत सारे स्कूल कंडीशनज को पूरा कर दें और अपग्रेड करने हो सिर्फ पांच तो सारे कैसे हो सकते हैं और इन हालात में सरकार को डिसक्रीशन इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।

चौ. रणबीर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि हरियाणा में लड़कियों के हाई स्कूलों की कितनी तादाद है?

श्री माडू सिंह मलिक: इस बारे में आगे सवाल आ रहा है।

Sh. Bansi Lal: There is a separate question for girls' schools also. It would be better if both these questions are put together. That is a normal convention in the Parliament also. If the hon. Member wants to know something about the other question, both the questions can be combined together.

Mr. Speaker: All right.

Girls High Schools in every village

***1159. Sh. Randhir Singh**: Will the Minister for Education be pleased to state the time by which the State Government shall be able to provide Girls High Schools in all the villages inthe State?

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): No time limit can be indicated.

Mr. Speaker: Now supplementaries on both the questions viz. 1159 and 1160 may be asked.

चौ. रणबीर सिंह: तो अब मैं वह सवाल कर लेता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे हां लड़कियो के कितने हाई स्कूल हैं?

श्री माडू सिंह मलिक: 75 हैं।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: उन्होंने बताया है कि सिर्फ 75 हैं। तो क्या वजीर साहब बतायेंगे कि वह इस किसम का क्राईटेरियन मुकर्रर करेंगे कि इतनी आबादी का कोई अगर गांव या शहर, कसबा हो तो उसमें लड़कियों का स्कूल खोल दिया जायेगा।

श्री माडू सिंह मलिक: सब में हाई स्कूल खोलना मुमकिन नहीं होगा।

चौ. रणबीर सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि इस स्टेट में कुल कितने हाई स्कूल लड़कों के है?

श्री माडू सिंह मलिक: 859 हैं?

चौ. हरकिशन लाल कम्बोज: क्या वजीर साहब जानते हैं कि कई इलाकों में हाई स्कूलों की तादाद ज्यादा है और कई इलाके ऐसे हैं जहां दूसरे इलाकों के मुकाबिला में पांचवा हिस्सा भी नहीं है? क्या वह ऐसा प्रोग्राम बनायेंगे कि जहां पर कमी है वहां ज्यादा अपग्रेड कर दिये जायें ताकि वहां भी लोग तालीम हासिल कर सकें?

श्री माडू सिंह मलिक: बैकवर्ड एरियाज को तरजीह दी जाती है।

चौ. जय सिंह राठी: वजीर साहब ने बताया है कि लड़कों के 859 और लड़कियों के 75 हाई स्कूल हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कोएजुकेशन कितने स्कूलों में है।

श्री माडू सिंह मलिक: लड़कियां लड़कों के स्कूलों में पढ़ सकती हैं कोई मनाही नहीं है।

चौ. दल सिंह: यह देखने में आया है कि एक गवर्नमैंट ने हाई स्कूल में अपग्रेड कर दिया और दूसरी गवर्नमैंट ने डाउनग्रेड कर दिया। ऐसा करने के लिये क्या क्राइटेरिया रखा है? (शोर) मैं बताता चाहता हूं कि जिला जींद में दयोरड़े का स्कूल

अपग्रेड किया गया लेकिन एक महीने के अन्दर अन्दर उसके डाउनग्रेड कर दिया गया।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): यह तो पिछली सरकार ने किया हमने तो नहीं किया।

चौ. दलसिंह: क्या जो स्कूल इस तरह डाउनग्रेड कर दिये गये उनको दोबारा अपग्रेड करेंगे?

श्री बंसी लाल: हमने तो डाउनग्रेड ही नहीं किये।

चौ. दल सिंह: मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जो किसी सरकार ने कर दिये थे .....

श्री बंसी लाल: कौन सी सरकार ने किये उसका नाम बता दो। हमारी सरकार ने नहीं किया।

चौ. दल सिंह: जो पहले अपग्रेड हुए वह महकमा की सिफारिश पर हुए और गवर्नमैंट ने किये लेकिन दूसरी सरकार ने आकर उन्हें डाउनग्रेड कर दिया। उनके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे स्कूलों को फिर आप अपग्रेड करना चाहते हैं?

श्री बंसी लाल: अगर मुनासिब होगा और क्राइटेरिया पर उतरेंगे तो करेंगे लेकिन इसमें बात यह है कि ऐसे अगर बीस स्कूल हों ओर करने पांच हों तो सरकार अपना डिसक्रीशन इस्तेमाल करेगी। जिस सरकार ने उन्हें डाउनग्रेड किया होगा उस वक्त कोई न कोई बात होगी और हो सकता है कि वह सारी

कंडीशनज को पूरा नहीं करते होंगे। फाईव इयर प्लान में टोटल टारगैट 60 होई स्कूल बनाने का था और मिडल स्कूल बनाने का टारगैट 50 का था, लेकिन अब तक 171 मिडल और 172 हाई स्कूल बन चुके हैं। फाइव इयर प्लान के अभी तीन साल बाकी है जिनमें और स्कूल बनेंगे।

चौ. हरकिशन लाल कम्बोज: आप मेरे पहले सवाल का जवाब दें।

श्री बंसी लाल: माननीय मैम्बर ने पूछा था कि जहां स्कूल नहीं है और स्कूलों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, क्या उस इलाके में स्कूलों की कमी को पूरा करेंगे? मैंने कहा ''जी हां''।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहिब, आनरेबल मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि 60 हाई स्कूल बनाने का टारगैट था और 172 स्कूल बनाये गये हैं। क्या बैकवर्ड एरिये में यह टारगैट पूरा हो गया है या नहीं? जहां टारगैट पूरा हो चुका है क्या वहां और स्कूल बनायेंगे?

श्री बंसी लाल: हम स्कूल बनाते जाएंगे जितना मैकिसमम और पौसिबल होगा।

श्री दया कृष्ण: स्पीकर साहब, स्कूलों के लिहाज से सारे हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्अ में स्कूल सबसे कम हैं और

सबसे पिछड़ा हुआ है। क्या मंत्री महोदय जींद डिस्ट्रिक्ट को हरियाणा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बराबर लायेंगे।

श्री बंसी लाल: आप चौ. दल सिंह जी से कहें कि वे पढ़ना शुरू कर दें (हंसी) अगर वे पढ़ेंगे तो हम सब जगह खोल देंगे?

चौ. दल सिंह: अगर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तो आप उन स्कूलों को भी बन्द कर देंगे जो खोले हुए हैं। (हंसी)

P.M's Note on Land Reforms

***1183. Ch. Chand Ram**: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) whether the Prime Minister sent any letter to the Chief Minister regarding Land Reforms during the year 1968-69 or 1969-70; if so, a compy of the same be placed on the table of the House together with the action taken thereon by the State Government; and

(b) whether the Government has issued any consolidated instructions regarding distribution of land to the landless and members of Scheduled Castes?

राजस्व मंत्री (श्री नेकी राम):

(ए) जी हां। पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती हैं यह सारा मामला जिस पर प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया है, भू–सुधार कमेटी के विचारधीन था।

(बी) सरकार के कोई संचित हिदायतें भूमिहीन और अनुसूचित जाति के सदस्यों को भूमि बांटने के लिए जारी नहीं कीं, मगर ऐसी हिदायतें हर किस्म की भूमि के लिए अलैदा अलैदा संबन्धित विभागों ने जारी की हैं। उदाहरणतयिा नजूल (ऐसचीट) लैंड्ज के लिए हिदायतें नजूललैंड (ट्रांस्फर) रूल्ज, 1956 में है। घटिया निष्क्रांत भूमि के लिए हिदायतें संयुक्त पंजाब सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 7841—जे.एी. (4)61/2699, दिनांक 29—8—1961 द्वारा जारी की थीं। ऐक्वायर्ड निष्क्रांत भूमि के नियतन के लिए हिदायतें सरकारी पत्र क्रमांक 2(106) एस—65/443413—34, दिनांक 22—11—65 में दर्ज है।

Copy of D.O. Letter No. 40381TMH/70, dated 1st June, 1970

from the Prime Minister of India to the Chief Minister, Haryana.

I have written to you earlier regarding the implemenation of land reforms. As you are aware, an approapriate and well balanced agrarian policy has been the concer stone and the object of our organisation even from pre-independence days. This is to reiterate the imperative need to ensure implementation of the land reforms within a fixed time limit. We have had further discussions on this matter and it is felt strongely that action should be expedited with reference to the security to tenure, fair rents, strict enforcement of ceilings, distribution of land to the landless and assumption of Government waste lands, suitable for cultivation to the landless labourers, with special reference to Schedule Castes and Scheduled Tribes. These are the minimum steps that are called for in order to bring real benefit to the people

in the country-side. This is the only way to remove social tension and encourage development towards our desired goal.

I should like to draw yhour attention to the Kerala Land Reforms Act, 1966 and the Kerala Land Prevention of Eviction Act, 1966, and the Kerala Land Reforms (Amendment) Act, 1969. Conditions in your State may be quite diffierent. Even so, the Kerala Act may helpyon to draw up your own legislation. While you are looking into various aspects of the matter in details, we feel that immediate action should be taken atleast to provide hom-steads to the landless tenants (called Kudiadappukaran in Malyalam). I hope that you will give this a thought before you come to attend the A.I.C.C. Session in the second week of this month.

चौ. दल सिंह: मिनिस्टर साहब ने जो जवाब पढ़ा है उसमें ''निष्क्रान्त'' शब्द इस्तेमाल किया है। यह शब्द बहुत मुश्किल है। क्या मिनिस्टर साहब इसका मतलब बताएंगे?

श्री नेकी राम: इसका मतलक ''महाजरीन' है।

श्री सत्य नाराण सिंगोल: मिनिस्टर साहब ने 'निष्क्रान्त' शब्द का अर्थ 'महाजरीन' बताया है, इसको रिकार्ड में से खतम करवा दें क्योंकि इसका अर्थ 'महाजरीन' नहीं है। अगर रिकार्ड में रहेगा तो इससे बेइज्जती होगी।

श्री बनारसी दास गुप्ता: 'निष्क्रान्त' शब्द का अर्थ 'महाजरीन' ही है।

चौ. चान्द राम: स्पीकर साहब, मैंने अपने सवाल में पूछा था कि 1968–69 और 1969–70 में कोई ऐसा लैटर आया है।

क्वैश्चन के रिप्लाई में सिर्फ एक लैटर का जिक्र किया गया है जिसकी कापी साथ लगा रखी है। जिस लैटर का मैं जिक्र कर रहा हूं उसके बारे में यह रैफ्रैंस है –

"I have written to you earlier regarding the implementation of Land Reforms."

It shows that the Chief Minister has received another letter also but the copy of the same has not been made available to me.

श्री नेकी राम: रिकार्ड में कोई ऐसी चीज नहीं है।

Ch. Chand Ram: In fact I have received copies of two letters addressed to the Chief Minister by the Prime Minister from eh Planning Commission. The department has supplied copy of one letter in reply to my question and not the second one. The reference of that letter is there is the Prime Minister' letter also.

श्री नेकी राम: रिकार्ड को देखने पर हमें वह चिट्ठी नहीं मिली और न ही उसका जवाब मिला है, इसलिए इसके मुताल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता।

Mr. Speaker: The Leader of the House will clarify the positon whether he has received that letter or not.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): I think there is mistake on the part of the Department. I am sorry that the second copy could not be laid on the Table of the House. But the real matter is dealth with in the second letter, dated 1st June, 1970 in which the Prime Minister has pointed out something particular and the most particular thing which the Prime Minister has emphasized is that the landless people/tenant should be given at least home-stead. In our State this problem is not there because in almost all the

villages land consolidation has taken place and people have been given 5 Marlas hom-stead without charging even a single pie. Only in 30 villages this consolidation work remains to be doone. So that problem is practically not there. Regarding other reforms or other progressive law, the Report of the Agrarian Reforms Committee has just been received. We will look into that after the elections are over and frame new law as soon as we can.

Ch. Chand Ram: May I know whether the Chief Minister had received that letter earlier than the one supplied to me?

Sh. Bansi Lal: Most probably during Rao Birender Singh's time. I think so. I may be wrong but I think so.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहिब, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि "I think so it may be wrong" इसका मतलब क्या है?

श्री बंसी लाल: इनको स्कूल में दाखिल करवा दें, स्कूल में पढ़ेंगी और पता लग जायेगा कि इसका मतलब क्या है। (हंसी)

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। हम इन्फर्मेशन लेना चाहते हैं और जो जवाब कन्फयूज करने वाले होंगे उनकी क्लैरिफिकेशन लेना हमारा अधिकार है और यह स्पीकर साहब की मारफत देते है।

Mr. Speaker: The matter is vey simple, Bahin ji. He said, "it may have been received when Rao Sahib was there (as Chief Minister)". He thinks so. That is all he has said. He is not sure. So ther is nothing objectionable in it.

Sh. Bansi Lal: That is why she needs schooling.

Mr. Speaker: Taht you decide amongst yourself. (Laughter..).

Sh. Bansi Lal: We will decide it through you, Sir ..... (Laughter).

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, हाउस में जो कुछ कहा जाए वह कुरेक्ट कहा जाए। 'परहैप्स', 'शायद' वाले जवाब नहीं होने चाहिए।

Mr. Speaker: Generally speakiing, you are right that there should be definite answers. But there will be occasions when a thing pertains or relates to something which happened two or three years ago. Then one may say, "I think it may have happened when so and so was there. This is my feeling ....." and so on. So, I think that is not objectionable.

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके विचार में ऐसा ही था। क्या मुख्यमंत्री जी अपना रिकार्ड देखकर बाद में सदन को बतायेंगे कि कौन सी बात पक्की है, कौन सी कच्ची है?

श्री बंसी लाल: कौन सी पक्की है या कौन सी कच्ची है, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं है। I have said that the other copy should have been there and we will get it. So, this question does not arise now.

Mr. Speaker: The hon. Member will get the copy and then he will know what is correct.

चौ. दलसिंह: दूसरे लैटर की कापी है, चौधरी साहब के पास ....

चौ. चान्द राम: गवर्नमैंट जारी रहने वाली चीज है। गवर्नमैंट के जो सैक्रेटरीज हैं, डिपार्टमैंट्स है उनका यह काम होता है कि जो भी चीफ मिनिस्टर आए उसके सामने प्राईम मिनिस्टर जैसे के इम्पोरटैन्ट लैटरों को रखे। यह कोई बात थोड़ी है कि जिस कंटरी में नकसलबाड़ी मूवमैंट उपजी उसमें डिपार्टमैंट चीफ मिनिस्टर के नोटिस में प्राईम मिनिस्टर के इस तरह के इम्पोरटैन्ट लैटर को न लाए। इस सवाल के जवाब में इन्होंने लैंड रिफार्म कमेटी का जिक्र किया जिसने दो अढ़ाई साल तक रिपोर्ट नहीं दी .....

श्री बंसी लाल: अब वह कमेटी नहीं है, अब तो रिपोर्ट हो गई। मित्तल साहब से पूछ लो, आप दोनों पास ही बैठे हो।

चौ. चान्द राम: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने एक कमेटी मुकर्रर की जिसने दो अढ़ाई साल के बाद रिपोर्ट दी जबकि सिविल डग्रीज के मातहत कितनी ही ट्रांस्फरें हो चुकी हैं और लैंड सीलिंग का या सिलिंग को लोअर करने का सारा मुद्दा ही खतम हो चुका है। तो इस सवाल के जरिए मेरा पूछने का मुद्दा यह था कि गवर्नमैंट इतने दिनों तक क्यों सोती रही और इसने क्यों एक्शन नहीं लिया?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, गवर्नमैंट बिल्कुल सोती नहीं रही। इन्होंने कहा कि लैंड रिफार्मज कमेटी ने अढाई साल में रिपोर्ट की हैं वह ऐसी बात नहीं है, लगभग एक डेढ़ साल में ही उसने रिपोट्र दे दी थी। फिर हमने तो एक्शन भी ले लिया मगर मैं चौ. चांद राम जी से पूछना चाहता हूं कि ये तो सन् 1946 से चले आ रहे हैं ये क्यों दोनों आंखे बन्द करके सोते रहे?

चौ. चान्द राम: स्पीकर साहिब, हमने 1953 में कानून बना दिया था। इसी सदन से 19 एम.एल.एज. के साथ मैंने वाक–आउट किया था और प्राईम मिनिस्टर नेहरू से जाकर हम मिले थे।

श्री बंसी लाल: बाद में ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, तब ही इम्पलीमैंट कर जाते।

चौ. चान्द राम: आप तो अढ़ाइ साल से चले आ रहे हैं। मैं चार पांच महीनों से ज्यादा नहीं रहा वरना इम्पलीमैंट कर देता।

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर का घंटा है, इसलिये प्रश्न करना चाहता हूं। क्या मैं माल मंत्री या मुख्यमंत्री जी से जान सकता हूं कि जो जमीन हरिजनों के लिये या भूमिहीनों के लिये कंसोलिडेशन आपरेशन में छोडी गई थी वह सब बंट गई है या नहीं बंटी है, यदि नहीं बंटी है तो कितनी ऐसी जमीन है जो छोड़ी गई थी और आजतक नहीं बंटी?

Sh. Bansi Lal: This supplementary does not arise out of this question. I require as separate notice for it.

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अभी जो जवाब दिया उसमें इन्होंने बताया कि प्राईम मिनिस्टर की चिट्ठी में होम–स्टैड लैंड देने के लिये जिक्र है और हमारे प्रदेश के अन्दर 30 गांवों को छोड़कर बाकी सब गांवों में बगैर मुआवजा लिए हुए जमीन दे दी गई हैं तो मैं अब सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सब जमीन बंट गई है? अगर नहीं बंटी है तो सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है?

श्री बंसी लाल: इसके लिये आनरेबल मैम्बर अगर सैपरेट नोटिस दें तो जवाब दूंगा।

चौ. चान्द राम: क्या ऐसे भूमिहीन आदमियों को जिन्हें कंसौलिडेशन के बाद होम–स्टैड जमीन नहीं मिली जमीन दी जाएगी।

चौ. चान्द राम: स्पीकर साहब, हाउसिंग मिनिस्टर्ज कांफ्रेस पहले जयपुर में और उसके बाद साऊथ में हुई थी। उसका यह फैसला था कि भूमिहीनों को होम–स्टैड जमीन अक्वायर करने के लिये भारत सरकार प्रान्तीय सरकार को ग्रांट देगी। इसके बारे में एक खबर में निकला था कि हरियाणा सरकार ने इस तरह की ग्रांट भारत सरकार से नहीं मांगी है। तो क्या मैं जान सकता हूं कि हरियाणा में कोई भी भूमिहीन ऐसा नहीं है जिसके पास होम–स्टैंड जमीन न हो? अगर इनसे कोई लैप्स हो

गया है, गवर्नमैन्ट आफ इंडिया को लिखने की बात नजर से ओझल हो गई थी तो क्या अब ये इस बात के लिये लिखेंगे ताकि जो पैसा मिले उससे जमीन खरीद कर भूमिहीन लोगों को दी जा सके?

श्री बंसीलाल: स्पीकर साहिब, आनरेबल मैम्बर ने रैवन्यू डिपार्टमैंट का सवाल पूछा था परन्तु अब ये हाउसिंग डिपार्टमैंट पर चले गए। इसके लिये ये सैपरेट नोटिस दें तो बता दिया जाएगा कि इसमें क्या हुआ है।

चौ. चान्द राम: स्पीकर साहब, मैने तो इधर–उधर की कोई बात नहीं की। मैंने तो यह कहा है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया जब पैसा देती है उसे हम क्यों नहीं लेते? (विघ्न)

Mr. Speaker: Your suggestion is good and it has been noted. So, you need not repeat it, because they will naturally consider it.

श्री दया कृष्ण: चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में फरमाया है कि मुरब्बाबन्दी के बाद जिनके पास मकान के लिये जमीन नहीं थी उनको जमीन दे दी गई है। क्या वे बतायेंगे कि शहरों मैं जिन आदमियों के पास रिहायशी मकान के लिये जमीन नहीं है उनको भी जमीन दी जाएगी।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, लैड रैवन्यू या रैवन्यू डिपार्टमैन्ट में शहर कही बीच में आते नहीं, यह हाउसिंग

डिपार्टमैंन का सवाल है। इसके बारे में आनरेबल मैम्बर सैपरेट नोटिस देकर पूछें हम जरूर बतायेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहिब, यह सवाल चीफ मिनिस्टर साहब के जवाब से ही पैदा होता है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसका उत्तर आना चाहिए।

Mr. Speaker: One pertains to the rural areas; the other pertains to the cities. This is what they hve said.

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब, मुख्यमंत्री जी ने जो जववाब दिया था कि प्राईम मिनिस्टर की चिट्ठी आई है कि भूमिहीनों को घरों के लिये जमीन दी जाए वह सारे हरियाणा के लिये है, इसलिये उस जवाब से ही यह सवाल पैदा हुआ है?

Ch. Ranbir Singh: The entile State is divided into different estates. However, the fct remains that whether they are parts of a city or otherwise, they are parts of certain revenue estates.

श्री बंसी लाल: जनाब, इसके लिये तो ये सैपरेट नोटिस दें तभी जवाब दिया जा सकता है?

चौ. चान्द राम: स्पीकर साहिब, मैंने सवाल के पार्ट (ख) में पूछा था कि क्या सरकार ने भूमिहीन लोगों तथा अनुसूचित जातियों के सदस्यों को भूमि बांटने के सम्बन्ध में कोई समेकित हिदायतें जारी की हैं। इसके जवाब में इन्होंने कई एक इंस्ट्रक्शन्ज का हवाला नम्बर और तारीखों सहित दिया है मगर उनकी नकल

मेरे पास नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में एक बात सरकार को बताना चाहता हूं कि जब तक गवर्नमैंट उन जमीनों को फुल्ली ओर अनऐनकम्बर्ड ढंग से ट्रांसफर नहीं करेगी तब तक उन हरिजनों और भूमिहीनों को बैंक से कर्जा नहीं मिल सकता और मैं जानना चाहता हूं कि अगर लोग लम्प सम में किश्तें दे दें और दूसरी शरायत पूरी कर दें तो उनको मुकम्मल तौर पर कब्जा ट्रांसफर कर दिया जाएगा?

श्री बंसी लाल: सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहिब, चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि रूरल एरिया में हरिजनों को जमीन दे दी है। मगर हकीकत यह है कि कुछ विलेजिज में नहीं दी गई है। मजे की बात यह है कि आस–पास के विलेजिज में तो जमीन दे दी गई लकिनबीच में विलेजिज छोड़ दिए गए। यह कोई अच्छी बात नहीं। इससे दुःख भी होता है ओर लोगों में रिजैटमैंट भी पैदा होती है। मोरखी मेरा गांव है। इसके आस पास तीन गांव मेरे गोत के हैं, उन तीन गांवों में तो इन्होंने जमीन दे दी मगर बीच में मोरखी को छोड़ दिया।

श्री बंसीलाल: स्पीकर साहब, इनके गोत वालों को जमीन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ये तो हरिजन नहीं हैं, महाजन हैं।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी अढ़ाई साल से चण्डीगढ़ आये है। ये अपनी गांव की संस्कृति को भी भूल गये। गोत से मेरा मतलब यह है कि जाटों के कई कई गांवों का एक गोत होता है। मैं तो बनिया हूं। हमारे गांव में इतने घर नहीं होते (हंसी)। वहां कई जातियों के लोग बसते हैं। जिनमें हरिजन भी होते हैं। तो मेरे गांव में भी बाकी तीन आस पास के गांवों की तरह हरिजन थे मगर उनको जमीन नहीं दी तो इसलिये उनमें बड़ी भारी रिजैन्टमैंट है। क्या उसको दूर करने की कृपा करेंगे?

Mr. Speaker: Question hour is over.

श्री बंसी लाल: अगर कोई ऐसा गांव है तो छान–बीन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की दिक्कतें दूर करेंगे।

चौ. चान्द राम: स्पीकर साहब, इस सवाल पर मैं पूरी तहर से सप्लीमैंटरी नहीं कर सका। इसलिये कल के लिये आप इजाजत दे दें ताकि मैं एक–दो सप्लीमैन्टरी और कर सकूं।

श्री अध्यक्ष: आप इतनी देर तक बैठे रहे, पहले आपने क्यों नहीं किये। And in between you were sitting and other hon. Member were asking question.

चौ. चान्द राम: स्पीकर साहब, यह सवाल मैंने किसी मकसद के लिये किया था और जिस मकसद के लिये मैंने किया उसका जो सरकार ने जवाब दिया है उससे लोगों को फायदा नहीं

पहुंचेगा। क्योंकि सरकार ने जा जवाब दिया वह पूरी तरह से मेरे सवाल को समझ नहीं पाई है। इसलिये मुझे एक–दो सप्लीमैन्टरी करने की इजाजत दी जाये।

श्री अध्यक्ष: चौ. साहब इस सवाल पर काफी टाईम लगा है। इसलिये अब टाईम देना मुश्किल है।

चौ. चान्द राम: स्पीकर साहब, इसमें मेरा क्या कसूर है। अगर कोई मैम्बर मेरे से पहले ही उठ जाता है तो उसकी सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: इस पर काफी सप्लीमैंटरी हो चुके हैं and it will be only at the cost of other questions which are fixed for tomorrow.

चौ. चान्द राम: कल का तो आखिरी दिन है फिर तो सैशन खतम हो जायेगा। एक–दो सप्लीमैंटरी के लिए आप इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष: बजट के टाईम पर आप कह लें।

चौ. चान्द राम: ज्यादा की इजाजत न दें। केवल दो सप्लीमैंटरी मैंने करने है।

3 p.m.

श्री अध्यक्ष: आप भी जिद कर रहे हैं I am not going to agree.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED

QUESTIONS LAID ON THE TABLE UNDER RULE 45

Starred Question No. 1117

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of Starred Question No. 1117, which has been granted. The question is, therefore, postponed.

Literacy in Haryana

***1161. Sh. Randhir Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state the percentage of literacy in Haryana as in 1967 together with the increase made in such percentage district-wise in 1970?

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): Time and labour involved in replying to the question is not commensurate to the benefit likely to be obtained.

MESSAGE FROM THE GOVERNOR

Mr. Speaker: I have received a message from the Governor whcih reads as follows:-

"I beg to acknowledge receipt, with thanks, of yoru demi-official letter No. HVS-LA-2-71/4164, dated the 12th February, 1971, forwarding a copy of the motion of thanks passed by Haryana Vidhan Sabha at its meeting held on the 12th February. Please convey my thanks and appreciation for their kind thought in accepting the motion".

(Thumping from the Treasury Benches.)

RULING GIVEN BY THE SPEAKER

Mr. Speaker: On the 12th February, 1971, Ch. Jai Singh Rathi during the course of his speech stated that an M.L.A. could aspire to cecome a Chief Minister, Minister or Deputy Minister and not a Peon. Thereupon the Chief Minister remarked that, "यह तो चपड़ासी बनने के भी काबिल नहीं हैं। A Chaprasi is more responsible than this Member."

On this Ch. Ranbir Sing, M.L.A., rising on point of order sought expunction of the remarks made by the Chief Minister comparing a Member with a peon.

There is much of difference between the status of an hon. Member and that of a peon and in our society we have nto got different categories of peopel having a particular status in our society and comparison of a person having a better status with that not having sucha status is likely to be misconstrutec and it will only be proper if such liek references are avoided during the course of discussion in the House. In the book 'Practice and Procedure of Indian Parliament by S.S. More' as page 341 the words comparing a certain Member with the tea-sellers have been mentioned in the list of deprecated works. Accordingly I hold that the words "यह तो चपड़ासी बनने के भी काबिल नहीं है। A Chaprasi is more responsible than this member." are undignified and should be expunged from the proceedings of the House dated the 12th February, 1971.

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, आपने जो रूलिंग दी है यह तो सारी की सारी डिबेट में छपेगी?

श्री अध्यक्ष: जी हां, पूरी छपेगी।

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received notices of there Call Attention Motions from Ch. Ranbir Singh and Smt. Chandravati, M.L.As., concerning the non-laying on the Table of the House of the Annual Reports of the following statutory bodies during the current session :-

1. Haryana Agro-Industries Corporation.

2. Haryana Warehousing Corporation.

3. Haryana State Co-operative Agriculture and Marketing Federation.

4. Seed Corporation.

5. Haryana Financial Corporation.

6. Haryana State Industrial Development Corporation.

7. Haryana State Small Industries and Export Corporation.

8. Haryana Khadi and Village Industries Board.

9. Haryana State Electricity Board.

Although these cannot be termed as a matter of urgent public importance yet undoubtedly it is a matter of public

importance as the subject-matter of the notices pertaiins to the laying on the Table of the House of certain documents which the Government is required to do under the rules. I am sure they will do this in due course of time.

Now we take up general discussion of the Budget.

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR 1971-72

श्री राम सरन चन्द मित्तल (नारनौल): माननीय अध्यक्ष महोदय जब भी किसी देश या प्रदेश का बजट पेश होना होता है तो उसकी लोग इंतजार बड़े उत्साह से करते हैं। (इस समय उपाध्यक्ष पदासीन हुई)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, बजट के अन्दर उस प्रदेश या देश की जिसका वह बजट होता है प्रौसपैरेटभ और इकौनोमिक कन्डीशन का पूरा रिफ्लैक्शन होता है। जो हरियाणा का बजट पेश किया गया है उससे बेखूबी साबित है कि हमारे प्रदेश की इकोनोमी बड़ी साउन्ड है। जिस वक्त हरियाणा बना था उस वक्त बाहर के लोग और हमारे पंजाब के साथी कहा करते थे कि इनके पास तो सरकारी मुलाजमों का तन्खाह देने के लिये भी पैसा नहीं होगा। लेकिन अब इन तमाम बातों को देखने से पता चलता है कि दो–तीन साल के अन्दर इस प्रदेश ने किस कदर तरक्की की है और जहां डैफिसिट था वहां कई बातों में यह सरप्लस हो गया

है। यह अच्छी चीज है। बजट में जितनी फिगर्ज दी हुई हैं वे करोड़ों में दी हुई हैं और वे यहां हाउस में दोहराई नहीं जा सकती हैं। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि बावजूद इसके कि 11 करोड़ 56 लाख का डैफिसिट है लेकिन फिर भी डैफिसिट कम होता जा रहा है। यह बजट बहुत अच्छा साउन्ड इकौनोमी का बजट है। इसमें कोई शक नहीं कि इस बजट से यह प्रतीत होता है कि हमारा प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और दूसरे प्रदेशों के लिये एक उदाहरण बन गया है। हमारे प्रदेश की पैदावार दो साल पहले 27 लाख 64 हमार मीट्रिक टन थी, अब 46 लाख 26 हजार मीट्रिक टन हो गई है। इन फिगरों से ऐसा मालूम होता है कि हमारी इकौनोमी बहुत अच्छी है ओर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके इलावा हमारी सरकार के मुख्य मंत्री, फाइनैन्स मिनिस्टर साहिबा, हमारी तमाम पार्टी ओर यह तमाम हाउस बधाई का पात्र है। हमें इस बात की बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमारी पर कैपिटा इन्कम 342 रूपये थी लेकिन अब यह इन्कम 430 रूपये पर कैपिटा हो गई है।

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ इन्फर्मेशन, मैडम। बजट के ऊपर पहले स्पीच अपोजीशन की होनी चाहिये या ट्रेजरी बैचिज की?

उपाध्यक्षा: इसमें डैफिनेट रूप नहीं है, कोई भी कर सकता है।

श्रीमती चन्द्रावती: मैडम, मुझे इनफर्मेशन के तौर पर अगर यह रूल बता दें तो कृपा होगी?

उपाध्यक्षा: मैंने बता दिया कि किसी की भी तरफ से हो सकती है। उस वक्त जब मैं यहां नहीं बैठी थी और स्पीकर साहब यहां बैठे थे, आप यह पूछ सकती थी।

श्री राम सरन चन्द मित्तल: मैडम, अगर यह अपोजीशन का रोल प्ले करना चाहती है तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्रीमती चन्द्रावती: कांग्रेस प्रैजीडैंट होकर इन्हें ऐसी आब्जैक्शनेबल बात नहीं करनी चाहिए। He must withdraw these words.

Sh. Ram Saran Chand Mital: I refuse to withdraw.

मुझे बोलने की इजाजत माननीय स्पीकर साहब ने दी है ओर वह एक रूलिंग हो गई है। रूलिंग हो जाने के बाद आपको क्वैश्चन करने का क्या हक है?

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यह किसी मैम्बर साहब के एतराज करने की बात नहीं थी। मैंने उनके खिलाफ कोई पर्सनल बात नहीं की and there is nothing to feel irritated.

श्री दया कृष्ण: मैडम, यह एतराज अगर शुरू में होता तो ठीक बात थी। अब तो स्पीच शुरू हो गई है, इसलिये यह एतराज मेरे ख्याल में ठीक नहीं।

उपाध्यक्षा: आनरेबल मैम्बर की नौलेज के लिये मैं यह बता देना चाहती हूं कि मैंने पहले ही यह बात कही है कि जिस वक्त इन्होंने बोलना शुरू किया उस वक्त यहां चेयर पर अध्यक्ष महोदय थे। अगर उस वक्त यह प्वायंट रेज किया जाता तो और अच्छा रहता। हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि सबसे पहले अपोजीशन ही बोले लेकिन मेरे ख्याल में रवायात यह रही है कि आपोजीशन की तरफ से बोला जाना शुरू होता है, वैसे कोई भी बोल सकता है। अब जब उन्होंने बोलना ही शुरू कर दिया है, कोई क्वैश्चन ऐराइड नहीं होता।

श्री राम सरन चन्द मित्तल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, 2–4 मिनट बातों में खराब हो गये। खैर, मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारी स्टेट की आलराऊंड डिवैल्पमैंट के लिये मै। गवर्नमैंट को बधाई देता हूं। इस बजट के अन्दर जो इरीगेशन, एजूकेशन, बिजली ओर डिफरेंट डिपार्टमैंटस की जो तरक्की हुई है वह काबले तारीफ है और खासतौर से हिसार, करनाल और रोहतक के लोगों को मैं बधाई देता हूं क्योंकि उनके लिये यहां बहुत ही अच्छी स्कीमें इम्पलीमैंट होने जा रही हैं।

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): आपने महेन्द्रगढ़ का नाम नहीं लिया।

श्री राम सरन चन्द मित्तल: थोड़ा–बहुत हर डिस्ट्रिक्ट के लिये हुआ है, लेकिन खासतौर से यह जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके लिये ज्यादा हुआ है, इसलिये दूसरे डिस्ट्रिक्टों के लिये मैं एनीमी की भावना नहीं रखता। मैं दो–चार बातें और अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि कुछ चीजों की अभी और जरूरत है कल या परसों पिछले दो अधिवेशनों के अन्दर माननीय सदस्यों ने एतराज किया था। कुरपशन के मुताल्लिक। अच्छा होता यदि इसमें कुछ ऐसे मैनशन होता कि सरकार के कुरप्शन को मिटाने के लिये बजट में इतने रूपये का प्रोवीजन रखा है। (विघ्न) मेरे देखने में नहीं आया, मुमकीन है किया हो लेकिन यह चीजें लोगों के सामने आनी चाहियें। इलैक्ट्रीफिकेशन में इसमें कोई शक नहीं कि बिजली सभी जगह प्रोवाईड की गई है। सड़कों के लिये बड़ा रेपिड प्रोग्राम है। नहरें सारे एशिया में शायद सारे संसार में ऐसी नहीं बनी होंगी जैसी हमारे यहां जुई और लोहारू कैनाल बनी हैं। जब और सरप्लस पानी हो जायेगा तो ये प्राजैक्ट भी पैरेनियल हो जायेंगे। इसमें हर एक को खुशी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मै। यह भी अर्ज करूंगा कि बई एरियाज ऐसे हैं जहां इरीगेशन कैनाल से नहीं हो सकती। कुछ इरीगेशन टयूबवैल एक्सप्लोरेशन से कर रहे हैं लेकिन इसमें दो चीजों की बहुत कमी है। जैसे बिजली सब जगह गांव गांव में जाती है, लेकिन गांवों के लोग

कहते हैं कि बिजली तो हो गई मगर कुओं में पानी नहीं क्योंकि उनकी तहें रोकी हैं, पथरीली है। और वहां पर पानी निकालने के लिये आर्डिनरी बोरिंग मशीनें काम नहीं देतीं वहां पर अच्छी ड्रिलिंग मशीनें चाहियें, जो पत्थर को तोड़ कर नीचे से पानी निकाल लेती है। वे मशीनें काफी कीमती होती हैं, क्योंकि पत्थर के नीचे से पानी निकालता होता है। इसलिये जब तब वे मशीनें नहीं आयेगी वह एरिया निग्लैक्टिड रहेगा। कई आश्वासन दिये गये हैं। चीफ मिनिस्टर सहिब ओर कई मिनिस्टर साहबान की तरफ से कि हम वे मशीनें मंगवाएंगे लेकिन वे अब तक नहीं आई हैं। जब तक वे हम नहीं मंगवायेगे तब तक वह एरिया बिल्कुल निग्लैक्टिड रहेगा। जब हम करोड़ों रूपया कैनालज के ऊपर खर्च कर रहे है या और बातों के ऊपर कर हे हैं तो इस तरह की मशीनों को मंगवाने के लिये भी पैसा खर्च करना चाहिये। वे फौरन कन्टरी से मंगवाई जानी चाहिएं क्योंकि यहां तो बनती नहीं। सैन्टर के पास भी वे मशीनें हैं, हमारे पड़ौसी राज्य राजस्थान के पास भी हैं और दूसरी स्टेट्स के पास भी हैं लेकिन हमारे यहां नहीं है। उस तरह की मशीनें जब तक नहीं आयेंगी वह एरिया हमारे काबू में नहीं आ सकेगा। उस तरह की मशीनों के बगैर सबटैरेनियन स्ट्रैटा जो राकी है वह काबू में नहीं आयेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक–दो मशीनों से तो आपका काम चलेगा नहीं, काफी मशीनें चाहिएं। इसलिये जल्द से जल्द गवर्नमैंट को ऐसी मशीनें मंगवाने की कोशिश करनी चाहिये। ड्रेन नं. 1 का पानी जो है अब तो कंट्रोल हो गया है लेकिन पहले बहुत दफा जाया चला जाता था

और इसके अलावा नुकसान भी बहुत करता था। इसलिये हर गांव में जहां जहां हो सके वहां एक तरह से छोटे बांध बनाये जायें ताकि वह पानी खेतों के काम आ सके। इसके अलावा उससे कुओं का वाटर लैवल ऊंचा होगा। आपसे कुछ बांध बनाये हुए हैं लेकिन इतनी ही प्रोग्रैस काफी नहीं है। इसके अलावा मेरी समझ में तो आता है कि गवर्नमैंट को इसके लिये एक सैपरेट महकमा खोलना चाहिये ताकि बांधों का सर्वे वगैरा भी हो सके और लोगौं का बांध बना बना करके पानी का फायदा पहुंचाया जा सके।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: उसका वजीर भी अलग से बनाया जाये।

श्री राम सरन चन्द मित्तल: आपको ही बना दैंगे। यह सजैशन बहन जी नोट कर रही हैं और मान भी लेंगी और फिर आप क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: आपकी प्रेजीडैंटशिप भी जाती रहेगी और यह मिनिस्टरी भी जाती रहेगी। (विघ्न)

श्री राम सरन चन्द मित्तल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं बता रहा था कि डैम्ज के वाटर को ठीक करा के हम लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं और यह काम किफायत का होता है इस पर ज्यादा खर्च नहीं होता। मैंने घौलेडा, वीधोपुर ओर सरेली में देखा है कि वहां पानी इतनी बर्बादी करता है कि यदि एक जगह पर कमजोर बांध टूट गया तो जो उसका पानी है वह दूसरे गांवों

को जायेगा और फिर खेतों और मकानों को बहुत नुकसान देगा। यह पानी काम में आ सकता है।

मुझे ज्यादा इन्ट्रैस्ट ऐजुकेशन में है और मुझे खुशी है कि हमारे ऐजुकेशन मिनिस्टर यहां मौजूद है।

श्री सत्यनारायण सिंगोल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये डिमांड्ज पर नहीं बोल रहे हैं ....

Deputy Speaker: Today, it is general discussion on the Budget.

Sh. Satya Narain Syngol: In a circular that has been issued to us, it is stated –

"It has been decided that the following demands will be discussed in the Vidhan Sabha on the day set down for dicussion on Demands of Grants."

Deputy Speaker: That is for the 16th. Today, there is general discussion on the Budget.

श्री राम सरन चन्द मित्तल: भाई सिंगोल, क्या सो रहे हो? 16 तारीख तो कल को है। आज तो हरियाण में 15 तारीख है।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: सिंगोल साहब आप बैठ जाइए। आज तो जनरल डिस्कशन ही है। .....

Sh. Satya Narain Syngol: No date has been given herein and, therefore, the presumption is that these will be discussed.

श्रीमती ओम प्रभा जैन: परन्तु बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट ऐकसैप्ट हो चुकी है, उसमें यह प्रोग्राम दिया हुआ है .....

श्री सत्य नारायण सिंगोल: डिपटी स्पीकर साहिबा, मैंने थोड़ी–थोड़ी अंग्रेजी जरूर पढ़ी है। इसमें कहीं भी तारीख्वा का जिक्र नहीं है। अगर डेट न दी गई हो तो यह प्रिजम्पशन होती है कि एजैन्डा आज का होगा।

Smt. Om Prabha Jain: It is for the day which has been set down for discussion on demands for grants.

Sh. Ram Saran Chand Mital: Today, there is general discussion on the Budget. That is for tomorrow. मेरे लायक दोस्त यह कहते हैं कि मैंने अंग्रेजी थोड़ी–थोड़ी पढ़ी है तो मैं उनसे पूछता हूं कि वे बी.ए.एल.एल.बी. की डिग्री कहां से उठा लाये?

श्री सत्य नारायण सिंगोल: यह तो सोशल सर्विस से ली है।

उपाध्यक्षा: मित्तल जी, आप अपनी स्पीच जारी रखें। .....

.

श्री राम सरन चन्द मित्तल: ऐजुकेशन बे बारे में रिपोर्ट में भी और बजट स्पीच में भी दिया हुआ है कि हमने 239603

आदमियों की बजाय अब 259433 आदमियों को ऐम्पलायमैंट दी है। लेकिन यह ऐसी बात है कि हर साल इतने मैट्रीकुलेट्स टर्न आउट होते हैं, इतने ग्रैजुएट्स टर्न आउट होते हैं कि गवर्नमैंट के लिये चाहे वह किसी भी स्टेट की हो या सैट्रल गवर्नमैंट हो यह मुमकिन नहीं है कि वह हर एक ऐजुकेटिड यंग मैन को एम्पलायमैंट प्रोवाइड कर सके। यह अनएम्पलायड लोगों की जो फौज बढ़ती जा रही है, यह देश के लिये हानिकारक है और इससे देश का टेलैन्ट बेकार जाता है। इसके अलावा मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी ऐजुकेशन यानी शिक्षा की जो प्रणाली है, इसमें तबदीली आनी चाहिए। इस प्रणाली पर बहुत गम्भीर विचार किया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि इस सिलसिले में कई कमेटियां और कई कमीशन बैठ चूके हैं लेकिन इस मामले को अभी तक हल नहीं किया गया है। सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब हम लड़कों को स्कूलों में पढ़ाते हैं तो वह मैट्रिक पास होने के बाद, हाथ से काम करना पसन्द नहीं करते। यह एक टैडैंसी सी हो गई है, यह एक ऐटीकेट सा बन गया है, कुद कन्वैन्शन सी ही बन गई है कि लोग हाथ से काम करने वाले को अच्छा नहीं समझते। रोज स्टेज पर डिगनिटी आफ लेबर पर लैक्चर दिये जाते हैं। जब तक इस बारे में एगजाम्पल सैट नहीं की जायेगी तब तक डिगनिटी आफ लेबर की इम्पलीमैटेशन नहीं होगी। हर स्कूल के अन्दर या तो बच्चे ऐग्रीकल्चर फार्म पर काम करें और ऐग्रीकल्चर ऐजुकेशन लें या जहां पर फार्म नहीं मिलते हैं वहां कोई इंडस्ट्रियल टाइप की शिक्षा दी जानी चाहिए। जब

तक ऐसी शिक्षा बच्चों को बचपन से ही नहीं मिलेगा तब तक लोग यहीं कहेंगे कि ऐसी शिक्षा को तो बन्द कर देना चाहिए जो कि हाथ से काम करना पसन्द करने वाले लोग न पैदा कर सके। 10–15 वर्ष की बात थी जबकि भारत सेवक समाज के कैम्पस होते थे। एक बार यूनैस्को (UNESCO) का एक डैलीगेशन आया। उसमें एक इजरायली लेडी थी, एक फ्रैंच प्रोफेसर और एक–दो आदमी और थे। मैंने उनको कैम्प दिखाये थे जहां पर कि हम लोग मैनुअल लेबर का बच्चों से काम ले रहे थे। तो इजरायली लेडी ने हमें बतलाया कि हमारे यहां 18 साल का लड़का या लड़की चाहे वह किसी भी छोटे से लेकर बड़े आदमी का हो, उसको हम कैंसक्रिप्शन के तहत कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग देते है। इसके अलावा एक ऐसा काम भी सिखा देते हैं जिससे कि वह 3 साल के बाद फौरन किसी न किसी काम में लगा दिया जाये, यानी वह आईडल या बेकार नहीं रहेगा। अगर हमारे यहां सरकार की ओर से ही कोई ऐसी बात हो जाये कि मैनुअल लेबर सिखाई जाये, तो फिर लोगों को अपने हाथ से काम करने में शर्म नहीं आयेगी। एक कारपैन्टर जो कि हाथ से काम करने वाला है 400 रूपये महीने का कमा लेता होगा लेकिन एक मैट्रिकुलेट बड़ी सिफारिश करके 150–200 रूपये की नौकरी करना तो पसन्द करेगा किन्तु ब्लैकस्मिथ का या दूसरा कोई हाथ का काम करना पसन्द नहीं करेगा। हमें इस बारे में सोसाइटी का नजरिया बदलना होगा। यह काम ऐजुकेशन डिपार्टमैंट ही कर सकता है। इसके लिये कोई ऐगजाम्पल सैट करने होंगे। तब कोई बात बन सकती

है वरना जो हम करना चाहते हैं वह नहीं हो सकता। मैं यही कहूंगा कि ऐजुकेशन की प्रणाली में कुछ फंडामैटल चेजिज आनी बहुत जरूरी हैं। जहां हमने और बातो में हरियाणा का ऐगजाम्पल सैट किया है, शिक्षा की तरफ भी ध्यान देकर एक अच्छा ऐगजाम्पल सैट करना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि जो लड़के लिट्रेटी टेस्ट के हैं या हमेशा होशियार निकलते हों उनको आगे ने बढ़ने दिया जाय। लेकिन हाथ से काम करने की सरकार को सब बच्चों को आदत डालनी चाहिए। इसमें किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझा जाना चाहिए बल्कि उनको यह काम अवश्य आना चाहिए। दूसरी बात जो हमने देखनी है वह यह है कि स्कूलों ओर कालेजों के अन्दर स्ट्राइक्स और डिमान्स्ट्रेशन्ज होती हैं। अब टीचर्ज ओर दूसरे कर्मचारी भी ऐसा करने लग गये हैं। मैं समझता हूं कि हमारी पढ़ाई के अन्दर कुछ नुकस हैं। हम डिसिप्लिन के अन्दर नहीं रह सकते। करैक्टर बिल्डिंग का काम, टैम्पटेशन को रिजिस्ट करना ओर एक आइडल सिटिजन के तौर पर रहना बहुत जरूरी है। जहां तक मेरी समझ में आता है, सोसायटी के अन्द आइडल सिटिजन बनाने के लिये लैक्चर न दिये जायें बल्कि उस तरह से रह कर लोगों को दिखाया जाय। हमारी ऐजुकेशन के अन्दर यह एक तरह का डिफैक्ट है। मैं आपके द्वारा अपने माननीय दोस्त से निवेदन करूंगा कि इस बात की तरफ पूरा ध्यान दिया जाय और ऐजुकेशन के अन्दर जो कमियां हैं वे दूर की जाएं। इस बात में कोई शक नहीं है कि आपने हर साल कई प्राइमरी स्कूल खोले हैं। कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां पर कि

प्राइमरी स्कूल नहीं होगा, सैंकड़ों की तादाद में मिडल स्कूल अपग्रेड किए हैं और हाई स्कूल अपग्रेड किए हैं। यह एक बहुत अच्छी बात है लेकिन अभी भी इसमें ऐक्सपैंशन का स्कोप है। इसके साथ ही साथ मैं निवदन करूंगा कि गर्ल्ज ऐजुकेशन की तरफ आपको और ध्यान देना चाहिए। आप कहते है कि को–ऐजुकेशन है वह ठीक नहीं जंचती। प्राइमरी स्कूलों के अन्दर ठीक है, कई जगह मिडल और हाई स्कूलों तक भी ठीक मानी जा सकती है लेकिन कालेजों के अन्दर को–ऐजुकेशन नहीं होनी चाहिए। मैं अपने मित्र को सलाह दूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर गर्ल्ज कालेज सरकार की तरफ से अवश्य होना चाहिए। इन्होंने कुछ कालेज तहसील हैडक्वार्टरज पर खोले हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन गर्ल्ज ऐजुकेशन की तरफ जितीन तवज्जोह सरकार को देनी चाहिए, उतनी नहीं दी जा रही है। मैं मानता हूं कि कुछ और जरूरी खर्चे होंगे लेकिन देहातों के अन्दर हम देखते हैं कि लड़कियां नहीं पढ़तीं हैं क्योंकि उनके यहां बाहर की मास्टरनियां पढ़ाने नहीं आती। लोकल या मुकामी लड़कियों को हायर ऐजुकेशन दिलाना आवश्यक है। वह लड़कियां जब तक को–ऐजुकेशन कालेज हैं, पढ़ने नहीं आवेगी यानी वहां की लोकल लड़कियां वहां कालेजिज में नहीं पढ़ पाती। इसलिये मैं चाहता हूं कि गर्ल्ज ऐजुकेशन के लिये गवर्नमैंट की तरफ से अलहदा कालेज खोले जाने चाहिएं। यह कहना कि कोई प्राईवेट सिटिजन कालेज खोल ले ठीक बात नहीं है। मैं मानता हूं कि कई जगह प्राईवेट गर्ल्ज कालेज लोगों ने खोले भी हुए हैं लेकिन कई जगहें ऐसी हैं

जहां पर कि लोगों की फाइनैन्शिल कन्डीशंज ऐसी नहीं हैं कि वे कालेज खोल सकें या कालेज चला सकें। इसलिये मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि सरकार को हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर एक गर्ल्ज कालेज अवश्य खोलना चाहिए।

चौ. जय सिंह राठी: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। मित्तल साहब हमारे बुजुर्ग हैं ओर काफी लिटरेरी हैं। यह एक शब्द मास्टरजी इस्तेमाल कर रहे हैं। यह ग्रामर के लिहाज से गलत है। मास्टर कौमन जैण्डर है इसलिये इस लफ्ज का ही इस्तेमाल इस हाउस में होना चाहिए।

उपाध्यक्षा: अक्सर बोलचाल की भाषा में मास्टरनी ही इस्तेमाल होता है।

चौ. जय सिंह राठी: अगर हम कोई गलत शब्द बाहर इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम यहां तो न करें।

उपाध्यक्षा: मैं समझती हूं कि यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। यह तो बोलने का ढंग है। इस हाउस के अन्दर बहुत से शब्द ऐसे बोले जाते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि यह ग्रामर के प्वायंट आफ व्यू से ठीक नहीं हैं, यहां हरियाणवी भाषा में ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो ग्रामर के लिहाज से ठीक नहीं हैं।

चौ. जय सिंह राठी: मेरे जैसा अनपढ़ कह दे तो कोई बात नहीं हैं, ये तो बहुत पढ़े लिखे है।

श्री राम सरन चन्द मित्तलः एक एल.एल.बी. और लरनिड आदमी अपने आपको अगर अनपढ़ कहता है तब तो बड़ी हैरानी की बात है। खैर, मैडम, मैं अर्ज कर रहा था कि पिछले साल जब हमारे चौ. खुरशीद अहमद के पास ऐजुकेशन का पोर्टफोलियो था उन्होंने सहैसियत ऐजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमैंट कालेज, नारनौल, के प्राईज डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त एक कमिटमैंट किया था कि वहां पर लड़कियों का होस्टल जरूर बनवाया जाएगा, 1970 के शुरू से वहां पोस्ट–ग्रैजुएट क्लासिज शुरू कर देंगे और वहां पर कुछ एम्पलाईज को बढ़ाने की भी बात थी। वहां का कालेज जो बी.ए. या बी.एस.सी. तक है, 1954 से चल रही है। वह कमिटमैंट पूरा होना चाहिए चाहे ऐजुकेशन मिनिस्टर कोई भी हो। लड़कियों के होस्टल के बारे में जो कमिटमैंट है उसको इम्पलिमैंट करना चाहिए क्योंकि इस वायदा को करने के बाद काफी टाईम बीत गया है। वहां पर देहात की लड़कियों के लिये होस्टल होना जरूरी है क्योंकि अगर देहात की लड़कियों को वहां रहने की कोई जगह होगी तो वह ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकेंगी। इसी तरह से नारनौल में गवर्नमैंट हायर सैकेण्डरी स्कूल फार गर्ल्ज जिस बिल्डिंग में है उसमें पहले पटियाला स्टेट का प्राईमरी स्कूल था लेकिन उसी बिल्डिंग में यह स्कूल चलाया जा रहा है। यह बहुत पुरानी बिल्डिंग है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हर 10–15 गांव के पीछे लड़कियों का मिडल स्कूल और हायर सैकेण्डरी स्कूल का होना जरूरी है। यह एक बहुत ही इम्पौरटैण्ड चीज है। वहां पिछले साल जे.बी.टी.

क्लासिज खोलने के लिये सरकार ने अपने बजट में कुछ रूपया प्रोवाइड किया था और इस रूपये से वहां बिल्डिग बन सकती है। परन्तु मेरा ख्याल है कि वह रूपया लैप्स हो जाएगा क्योंकि अभी तक वहां कोई काम नहीं हुआ है।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि वहां पर कई जगह जमीन ब्रैकिश है और इस कारण उसकी फर्टिलिटी कम है। अमृतसर में लैंड रैक्लेमेशन एंड इरीगेशन रिसर्च इंस्टिच्यूट है। वहां के डायरैक्टर राय बहादुर कंवर सैन थे जोकि इंटरनैशनल फेम के इंजीनियर है। उन्होने रिकेमैण्ड किया था कि हरियाणा में उस टाईप का एक इंस्टिच्यूशन होना चाहिए। हमारे प्रान्त की फर्टिलिटी तथा सायल कन्जरवेशन की जितनी प्रौब्लम्ज हैं वे इस तरह के इंस्टिच्यूशन से हल हो जाएंगी। इसमें कोई शंक नहीं कि इस बजट के अन्दर इन कामों के लिये काफी रूपया प्रोबाईड किया गया है। लेकिन अगर इस तरह का इंस्टिच्यूशन भी खोल दिया जाए तो इससे स्टेट की प्रौब्लम बिल्कुल हल हो जाएगी।

हरियाणा कैटल वैल्थ के लिये मशहूर है। यहां के कैटल बाहर जाते हैं और हमारे यहां भी उनकी काफी जरूरत है। हमारे प्रान्त ने वैटरनरी अस्पताल खोलने में काफी प्रोग्रैस की है लेकिन अभी भी इनकी बहुत जरूरत है। इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि 10–15 गांवों के ग्रुप के लिये एक ऐनिमल डिस्पैंसरी होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक किसान को देखा, उसके बैल की टांग कुछ खराब हो गई थी। उस किसान ने कहा कि इस

बैल की कीमत तीन हजार रूपया है। वइ अपने बैल को दूर की डिस्पैंसरी में ले गया जहां कि 10–15 दिन में ठीक हो गया। मेरा कहना यह है कि अगर उसको समय पर एड नहीं मिलती तो उस बेचारे का तीन हजार का नुक्सान हो जाता। हमारे जमींदार को अपने कैटल से बहुत प्यार है। (विघ्न)

उपाध्यक्षा: आप अपनी स्पीच कंटिन्यू रखिए।

श्री राम सरन चन्द मित्तल: अगर राठी साहब इण्ट्रेप्शन न करें तो इनकी रोटी ही हजम नहीं होती।

चौ. जय सिंह राठी: मैंने आज रोटी खाई ही नहीं है। (विघ्न)

श्री रामसरन चन्द मित्तल: इतना कह कर ही, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपनी सीट लेता हूं।

श्री सत्य नारायण सिंगोल (सफीदों): डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा का बजट इस सदन में पेश हुआ है और मुझे इसको देखकर एक कहावत याद आ गई है। हरियाणा में एक कहावत है कि बनिए की बावन बिद्ध होती है। मुझणे इस बजट को देख कर पूरा विश्वास हो गया है कि जो बनिए की बावन बिद्ध वाली कहावत है वह बिलकुल ठीक है यह कहते हैं कि यह घाटा सिर्फ 11 करोड़ 56 लाख रूपए का है।

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): आपकी राए में कितना है?

श्री सत्य नारायण सिंगोल: मैं आपको बताता हूं। 6 करोड़ तो आपका पब्लिक लोन है, 6 करोड़ 81 लाख आपको सैंट्रल गवर्नमैंट से मिलेगा, इसके इलावा आप सैंट्रल गवर्नमैंट से एड ऐक्सपैक्ट करते हैं, आप यह भी एक्सपैक्ट करते हैं कि सैंट्रल पूल से भी सहायता की रकम ज्यादा मिलेगी। आपके अफसर वही है। आपकी स्टेट में व्यापार वही है और टैक्स आप लगा नहीं रहे तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आप कैसे एक्सपैक्ट करते हैं कि आपको आमदनी ज्यादा होगी? दूसरी तरफ आप टैक्स लगा रहे हैं ओर जब आपको प्वायंट आऊट किया जाता हे तो आप कहते है कि यह राव साहब के टाईम से ऐसा होता आ रहा है। आपने अगर कोई बात करनी है तो आपको ओन करनी चाहिए और इसके तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपने राज साहिब का नाम ले लिया, यह तो ज्वायंट पंजाब के वक्त में लगा था। अब आप 1975 तक लोगों पर ठोंस रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने टैक्स कोई नहीं लगाया। इन्होंने दो टैक्स लगाए हैं, उनमें इन्क्रीज किया है लेकिन उसके लिए बजट में कोई प्रोविजन नहीं लाया गया और यहां पर ही बस नहीं उसके अन्दर यह भी कोई गारंटी नहीं कि आगे के लिए वह टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इन्होंने इसमें लिखा है –

No New measures are being proposed for the present.

अगर टैक्स लगाना था तो फिर यह न गारण्टी देते कि थरू–आऊट दी ईअर कोई और टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से गुमराह करना इनका एक शेवा बना हुआ है। यह दावा करते हैं कि हम डिवैल्पमैंट बड़ी करते हैं और टैक्स इस तरह से बढ़ाते रहते हैं लेकिन बजट में उनको दिखाया नहीं जाता। यह कहते हैं कि हमने इतनी इलैक्ट्रिफिकेशन कर दी है लेकिन आज भी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के जिम्मे 30 करोड़ की लायबिलिटी है। उसका कोई फिक्र नहीं कि पेमैंट कहां सह होगी? लोन जितना ले सकते थे वह ले लिया, और मिलने की गुंजायश नहीं, स्टेट के अन्दर घाटे की कोई कमी नहीं लेकिन एक पौलिश्ड तरीके से इन्होने दिखा दिया है कि यहां पर सब कुछ ठीक है। जिजली बोर्ड ने वैसे दिवाला निकाल रखा है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, सिर की मार तो पैरों पर ही पड़ेगी। इनको आज नहीं तो अगले साल लोन वापिस देना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं कि बजाए इसके कि ये कर्जे के नीचे हरियाणा को दबाते जाए ये क्यों नहीं टैक्सेशन के जरिये ओर इकौनोमी के साथ काम चलाते ओर अच्छे ढंग का बजट क्यों नही पेश करते? जहां तक घाटे का ताल्लुक है, इनके अपने हिसाब के मुताबिक भी यह 2 करोड़ और 67 लाख रूपए का बनता है, 5 करोड़ रूपए का सैंटर से लोन है, 6 करोड़ का पब्लिक लोन है और फिर काफी रकम पब्लिक डैट की है। 6 करोड़ को जो पब्लिक लोन खड़ा कर रहे हैं, वह अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाने आता है उसको मजबूर करके लिया जाता है और कचहरियों के अन्दर भी एग्जैक्टिव साईड से इन्होंने लेना

शुरू कर दिया था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं जो भी बातें कह रहा हूं वह पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। इन्होंने हर पटवारी के जिम्मे 50 हजार रूपया इकट्ठा करने लगाया है और अगर कोढ नहीं लाकर देता तो उसको सस्पैंड करते हैं जब कोई जिमींदार 50 हजार रूपए की रजिस्ट्री करवाने जाए तो उसको कहते हैं कि पांच हजार रूपया स्माल सेविंग का दो। जिमींदारों की हालत तो आप जानते हैं कि कितनी मुश्किल से वह अपना माल–डंगर बेच कर रूपया इकट्ठा करके रजिस्ट्री करवाने के लिए जाता है, उसके पास जमीन की कीमत के अलावा बड़ी मुश्किल से रजिस्ट्री की फीस देने के लिए पैसे होते हैं। इसलिए वह किसी को साथ लेकर तहसीलदार साहिब के पैर पकड़ कर कहता है कि मुझसे आप ब्याज ही ले लो और मेरा पीछा छोडो। तो वह रकम जो होती है वह तहसीलदार खुद ही खा जाता है और इस तरह के कुरप्शन का यह एक बहुत भारी अदायरा बना हुआ है। मैं समझता हूं कि इस लोन से कोई फायदा होने वाली बात नहीं है बल्कि कुरप्शन को बढ़ावा देने की ओर लोगों को तकलीफ में डालने वाली बात है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और ला एंड आर्डर के बारे में मित्तल साहब कहते हैं कि बहुत ही अच्छा है। मैं यह बात नहीं कहता कि ला एंड आर्डर को चीफ मिनिस्टर साहब खराब करते हैं या कोई ओर बजीर साहब करते हैं ला एंड आर्डर को खराब करने की जिम्मेवारी इंडीविजुयल लोगों की होती है, लेकिन इसमें गवर्नमैंट किस हद तक जिम्मेवार है उसके बारे में मैं चार मिसालें पेश करता हूं और आप उन बातों की इनक्वायरी

करवाएं। अगर यह बात गलत हो तो मैं उसके लिए जिम्मेवार हूंगा। सिगाणा एक गांव है। वहां पर मर्डर हुआ। वहां पर आदमी ठीक मरा और वह ठीक मारा गया जायज तौर पर क्योंकि कोई भी आदमी अपनी बहू–बेटी की बेईज्जती बरदाश्त नहीं कर सकता। इसलिए लोगों ने तंग आकर अपनी इज्जत बचाने के लिए उस आदमी को मारा। क्योंकि उनकी इज्जत का कोई मुहाफिज नहीं था इसलिए उन्होंने उसको मार दिया। दिन के पांच बजे उसको मार दिया गया लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमें जेा सबसे बड़ी एतराज की चीज है वह यह है कि उसको थानेदार की साजिश से मारा गया। थानेदार ने इस चीज का पहले ढाई हजार रूपया लिया लेकिन बाद में किसी ने कह दिया कि इतना थोड़ा रूपया इतने बड़े केस में आपने क्यों लिया है, इसके लिए तो बहुत बड़ी रकम ली जानी चाहिए थी। तो फिर उस थानेदार ने उनको तंग करके छः हजार रूपया लिया।

एक हजार रूपया इनक्ववायरी वाला ले गया और चार हजार एक और अफसर ले गया। इस किसम के काम आज पुलिस की कनाइवैस के साथ हो रहे हैं। यह ठीक है कि कोई दुनिया की ऐसी हस्ती नहीं जो मर्डर्ज को बिल्कुल बंद कर सके और न यह पुलिस वाले इस चीज को होने से रोक सकते हैं क्योंकि पुलिस को क्या पता कि कोई किसी को मर्डर करने की स्कीम बना रहा है लेकिन जब पुलिस को पता लग जाता हे कि फलां ने मर्डर किया है फिर वह कोई कार्यवाही न करे बल्कि उससे मिल जाये

तो उसे ला एंड आर्डर नहीं कहा जा सकता। मैं आपको जुलाना थाना का एक केस बताता हू कि किस तरह ला एंड आर्डर कि मिट्टी पलीद की जा रही है। वहां एक जाट और खाती का मामूली सी बात पर मकान की मुरम्मत के सिलसिले में झगडा हो गया और जाट ने खाती को पीट दिया। खाती ने अपना एक दांत निकलवा लिया और थाने पहुंच गया। थानेदार ने कहा कि मुकदमा बनायेगा तो डाक्टरी करवानी पड़ेगी और डाक्टर को पैसे देने पड़ेगे वैसे ही उसकी मारपीट कर देंगे थाने में बुलाकर तो जाट को थाने में बुलाया गया और हवालात में बंद कर दिया गया। थाने के सामने हलवाईयों की दुकानें हैं और वहां दलाल बैठे रहते हैं। तो थानेदार के एजंट जाट के पास पहुंच गये और पूछने लगे कि क्या माजरा है। जाट ने कहा कि भाई मुझे यहां से निकलवा दो। उन्होंने कहा कि 500 रूपये लगेंगे क्योंकि 350 थानेदार लेगा और 150 खाली लेगा। जाट ने कहा चाहे कुछ लग जाये यहां से निकलवाओ, और 500 पर मामला तय हुआ। उसके पास 213 रूपये नकद थे और एक घड़ी थी और वह दोनों चीजें थानेदार को दे दी। अपने दिन सुबह जाट 300 रूपये देकर घड़ी वापस ले आया। जाट ओर खाती पड़ौसी थे ओर उनकी आपस में बातचीत थी। जाट ने खाती से कहा कि तेरे को मैने 150 रूपया दिया लेकिन वह कहने लगा कि उसे कोई पैसे नहीं मिले। फिर झगड़ा पड़ा। उन्हौंने पंचायत की और उसे जाट ने बताया कि उसने पुलिस को 500 रूपये दिये थे जिसमें से 150 खाती को मिलना था। जींद के एस.पी. के पास शिकायत की गई और उसने

350 वापस दिला दिये लेकिन 150 का अभी पता नहीं दिये या नहीं दिये या दलाल ही खा गये। पुलिस तो लेती थी लेकिन इस राज में अब पुलिस के दलाल भी लेते है। तीसरा वाक्या जींद में हुआ। वहां एक आदमी पेशी भुगतने के लिये आया लेकिन पुलिस उसे रास्ते से पकड़ कर ले गइ ओर उसे पांच–छः दिन जेल में नाजायज हरासत में रखा। उस पर नाजायज पिस्तौल रखने का केस बना दिया और जिस आदमी से पिस्तौल बरामद किया गया था उससे सौ रूपया लेकर उसे छोड़ दिया। जींद का थानेदार था और मैं उसका नाम ले देता हूं क्योंकि मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कहता उसकी तारीफ ही करूंगा। हमारे यहां खाई वालों का सट्टा चलता था और आज तक उसे कोई बन्द नहीं कर सका था। उस थानेदार में चाहे कितनी ही नुक्स हो लेकिन जिस दिन वह आया उसने आते ही खाई वालों का सट्टा नहीं चलने दिया। उस थानेदार का नाम हमारी लाल है। लेकिन इन्होंने उसे बदल दिया पता नहीं इनको सट्टा उसका बन्द करना पसंद नहीं आया। उसके जाने के बाद आज फिर वह सट्टा चल रहा है। जो सट्टे वाले थे और खाई वाले काम छोड़ गये थे उनसे कहते हैं कि काम शुरू करो और कमाई करके हमें दो, नहीं तो तुमको रगड़ेगे। क्या यह ला एंड आर्डर है? जब आप कहते हैं कि ला एंड आर्डर ठीक है तो वे लोग जो यह खराबियां कर रहे हैं समझते हैं कि वे भी अच्छे हैं और इस तरह शह लेकिर वे इस तरह के काम करते हैं। ला एंड आर्डर को अच्छा कहो लेकिन यह न कहो कि बहुत ही अच्छा है और कोई कमी उसमें नहीं है। ऐसा कहना ठीक नहीं है।

मैंने चार केस बताये हैं और इनके बारे में मैं यह नहीं कहता कि उनका आज ही हाउस में जवाब दें। यह वेरीफाई कर लें, पूरी तहर तसल्ली कर लें और फिर बता दें। डिप्टी स्पीकर साहिबा इस वक्त यहां दो वजीर भाई नहीं हैं। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों वह सफीदों दौरा पर गये। इस गवर्नमैंट ने और खासतौर पर इन वजीरों ने कानून की मिट्टी पलीद करने का शेवा बना रखा है। एक महकमा की तरफ से कुछ हिदायते जारी हुई कि यह काम इस ढंग से होगा। मैंने महकमा के डायरैक्टर से पूछा कि आपने जो हिदायतें जारी की हैं क्या वे कम्पलाई विद होंगी। तो उसने कहा कि कोई वजह नहीं कि न हों लेकिन अगर ऊपर से कुछ हो जाये तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि वे हिदायतें कैरी आऊट नहीं हुई वजीर साहिब गये, रोहतक के रैस्ट हाउस में ठहरे और वहां से छः टैलीफोन किये। एक आया उसे भी कह दिया हां ऐसा करा देता हूं, दूसरा आया उसे भी कह दिया, हां करा देता हूं, और उन्होंने छः टेलीफोन किये। यह सब होते हुये फिर ये कहते हैं कि ला एंड आर्डर ठीक है। ये जो दो वजीर भाई है ये सफीदों में मेरे खिलाफ प्रचार करने जाते हैं लेकिन मैं उनके इस प्रचार से नहीं डरता क्योंकि मैं सिद्धांत का आदमी हूं और कहता हूं कि आदमी अपनी बुराई से मरता है उसे कोई मार नहीं सकता। तो यह भला ही करके आते हैं। ये वहां गये मेरे खिलाफ प्रचार करने के लिये और आप मेरी फराखदिली देखिए। मेरी सफीदों में दुकान है। उनके ग्रुप के आदमी मेरे पास आये ओर कहने लगे कि कालेज के

लिये पैसा इकट्ठा करना है। जितना पैसा उन्होंने दिया उतना ही हमने दिया चन्दा का और वजीर साहब के गले में नोटों की माला डाली गई। अनाउंस तो कर आये कि यह पैसा कालेज को दिया जायेगा लेकिन अपने आदमियों के पास वह रूपया दे आये। उन्होंने क्या किया कि अपने पैसे वापस ले लिये और हमारे पैसे रोटी–पानी के हिसाब में काट लिये। आप देखें कि इनका खर्च भी हम ही दें और यह बुराई भी हमारी ही करें। वहां चीफ मिनिस्टर साहब गये और कहने लगे कि आपके हलका के मैबर का काम नहीं करेगे। बनिये मुझे बनिया नहीं मानते लेकिन जमींदार मुझे अपना समझते हैं। इनकी बातें सुनकर जमींदारों ने तो कह दिया यह पोला ढौंग है। अगर हमारा मैंबर कांग्रेस में आ जाता तो यह कहते कि मैम्बर बढ़िया है लेकिन अब उसे बुरा कहते है और वे उठकर चले गये। चौ. दलसिंह के हल्का में गये और उनको बहुत इनाम देकर आये लेकिन जब मेरे हल्का में आये तो मुझे उनसे कम इनाम देकर आये थे। इनकी बातें सुनकर बनिये तो हंसे और यह भी खुश हो गये कि बुराई हो गई लेकिन इनको यह नहीं पता कि वह बनिये न मेरे है और न इनके ही हैं। बनिया तो बणी का होता है, आज मेूरी हकूमत है तो मेरे साथ होंगे कल को आपकी होगी तो आपके होंगे। जब ये वहां गये तो इनके इंतजाम के बारे में डी.सी. साहब ने कहा कि सारा खर्च और इंतमाज ज्वायंट होना चाहिये और मुखालफित नहीं होनी चाहिए। मेरे एक दोस्त थे चौ. इन्दर सिंह उन्होंने कहा कि जिसका आपको खतरा है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और वे पैंसे दे देंगे। यह सफीदों

गये और हम इनके स्वागत के लिये रोटी–पानी के इंतजाम के लिये सांझीदार रहे लेकिन यह बदनामी मेरी ही करके आये। ये रोटी–पानी भी हमारा ही खाते हैं और बुराई भी हमारी ही

4.00 p.m.

करते हैं। स्पीकर साहब, इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हर तहसील हैडक्वार्टर पर एक कालेज होगा। इस डिक्लेरेशन को मदेनजर रखते हुए हमारे इलाके के लोगों ने एक डिमांड रखी थी कि सफीदों में कालेज खोल दिया जाए लेकिन इन्होंने कालेज की डिमांड को इन्कार कर दिया। जब सफीदों के कालेज खोलने के लिए पैसा मांगे तो ओम प्रभा जैन जी कहती हैं कि मेरे सिर में दर्द है। इनके सिर में दर्द कैसे हो सकता है। इनके पतिदेव डाक्टर हैं, संडे और सैचरडे को तकरीबन हफ्ते भर के लिए ठीक तरह से चैक–अप करके भेजते हैं। लेकिन जब कालेज खोलने के लिए पैसा देने की डिमांड आई तो कह दिया कि मेरे सिर में दर्द है। चीफ मिनिस्टर साहब कलानौर में खरीददारी करने के लिये गये तो चार लाख रूपया दे दिया लेकिन सफीदों के लोगों ने जब मांग की तो सिर में दर्द हो गया।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: आप भी कोशिश करें। कुछ आप करो और कुछ गवर्नमैंट दे देगी। (व्यवधान)

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी खरीददारी करने के लिये गये थे। मैं पूछती हूं कि वे क्या खरीदने के लिए गये थे?

श्री सत्य नाराण सिंगोल: खरीदने के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं, टमाटर खरीद सकते हैं आलू खरीद सकते हैं मैम्बर खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पावर को जायज तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ला एंड आर्डर तभी चल सकता है अगर कानून हर एक के लिए अन्धा हो। ये सफीदों में गये। एक भाई के खिलाफ कुछ ऐलीगेशन्ज थे जो कि म्युनिसिपल कमेटी का प्रैजीडेंट था। स्पीकर साहिब, मेरे अपने असूल हैं कि आदमी अपने कर्मो से ही मरता है और कर्मो से ही जीता है, दूसरे के मारने से नहीं मरेगा। वे इन्हीं के भाई थे। उन्होंने इतनी कुरप्शन की जिसका कोई हिसाब नहीं। हर तरह की कुरप्शन की, ऐन्क्रोचमैंट की, करैक्टर की कुरप्शन की ओर जो ऐलीगेशन्ज लगे उनकी इन्क्वायरी हुई। म्युनिसिपल कमेटी के मैम्बरों ने पूरी कार्यवाही की और जब देखा कि उसके अगेन्स्ट बहुत बड़े ऐलीगेशन्ज है और बच नहीं सकता तो वे कांग्रेस (आर) में शामिल हो गया। वह आदमी एक दम शुद्ध हो गया, महात्मा बन गया तमाम ऐलीगेशन्ज खतम हो गये। मैंने खुरशीद अहमद से पूछा कि क्या गधा गंगा नहाने से गऊ बन सकता है? .....

श्रीमती ओम प्रभा जैन: डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो आदमी हाउस में आकर अपने आपको डिफैंड नहीं कर सकता

उसकी क्लीयर आइडैंटिटी करके चर्चा न की जाए। यह मैं हाउस के डैकोरम को कायम रखने के लिए कह रही हूं .....

उपाध्यक्षा: मैं सुन रही थी इन्होंने किसी का काम नहीं लिया है।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैं कह रहा था कि अगर काप अच्छा आम करेंगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे। इसके इलावा आपने बजट में कैसे लिख दिया कि प्रोफैशनल टैक्स जो पंचायत समितियां लगाती थीं बन्द कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बजट में बहुत बड़ा झूठ है। इससे बड़ा झूठ ओर कोई नहीं हो सकता। प्रोफैशनल टैक्स इस बजट के पेश हाने या स्पीचें देने से बन्द नहीं होगा। यह टैक्स तो बाकायदा ऐक्ट के तहत लगा है और ऐक्ट के अन्दर अमेंडमैंट लानी जरूरी है। जब तक ऐक्ट में अमेंडमैंट नहीं लाएंगे तब तब यह बन्द नहीं हो सकता। इस टैक्स को खतम करने का एलान जो ये कर रहे हैं यह बिल्कुल पालिटिकल मुफाद के लिए किया जा रहा है, इसका और कोई मतलब नहीं। देहातों में मुलाजम हैं। ये उनको कहेंगे कि इलैक्शन में तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारे लिए आर्डिनेंस जारी कर देंगे और तुम्हारे ऊपर लगा हुआ प्रोफैशनल टैक्स बन्द कर देंगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा इससे बड़ा फ्रोड बजट का और कोई नहीं हो सकता अगर यह फ्रोड नहीं है तो बजट सैशन में यह अश्योरेंस दे कि इसी बजअ

सैशन में ऐक्ट की अमेंडमैंट लाएंगे और यह क्लाज जो टैक्स लगाने की है, डिलीट कर देंगे।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके इलावा दूसरी चीज ग्रांट के बारे में, एड के बारे में कहना चाहता हूं। इन्होंने पुलिस के डी. ए. पर जो कट लगाई थी वह तो रिस्टोर हो गई है लेकिन टीचर्ज ने क्या कसूर किया है कि उनके डी.ए. पर कट लगाई जा रही है? क्या इसलिए लगाई जा रही है कि ये इनकी गुड–बुक्स में नहीं है? यह टीचर्ज के साथ डिस्पैरिटी है। अब ये कहेंगे कि चूंकि टीचर्ज ने रिट कर रखी है, अगर रिस्टोर कर दिया तो रिट पर असर पड़ेगा। मैं कहता हूं कि क्या असर पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा वह रिट खारिज हो जाएगी, और क्या हो सकता है? इसके रिस्टोर करने से हाई–कोर्ट के आर्डरज की डिस–ओबिडिएंस नहीं होती। जब आपने पुलिस डिपार्टमैंट के कांस्टेबल को दिया है तो इनको भी मिलना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने कहा कि ऐग्रीकल्चर के अन्दर सरकार ने बहुत तरक्की की है और करेंगे। डिपार्टमैंट ने हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर पर चार चार, पांच पांच ऐग्रीकल्चर ऐक्सपर्टस बैठा रखे हैं जो कोई काम नहीं कर रहे। एक ऐग्रीकल्चर ऐक्सपर्ट से मैंने पूछा कि भाई तुमने कितना काम किया है। उसने बताया कि सिर्फ एक टयूबवैल का पानी टैस्ट किया है और वह भी जींद से चार मील के फासले पर है। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट में अपने महकमें के नक्शे बनाये हुए हैं जिनसे पता

चलता है कि फलां एरिए में मीठा पानी मिल सकता है। फलां एरिया काबले–काश्त है, फलां एरिए में खारा पानी है और वह नाकाबले–काश्त है, इन चीजों के नक्शे होते हैं। इसके इलावा ऐसी मशीनें हैं जो बहुत नीचे तक बोर कर सकती हैं। इन मशीनों से पूरा पूरा फायदा नहीं उठाया जाता। अगर एक जगह खारा पानी मिलता है तो उसको और एक्सटैंड करके देखें, आहिस्ता आहिस्ता किसी न किसी स्टेज पर 50 फुट पर, 60 फुट पर मीठा पानी मिल सकता है। अगर एरिए को ऐक्सटैंड करके चला जाए तो पानी की कमी पूरी हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं बजाये कमी को पूरा करने के, सरकार की कमी क्रिएट कर रही है। हमारे इलाके में पहले हमेशा पानी लगता था। हम पहले यही कहते थे कि जुई की नहर हमारा पानी ले लेगी। हम ठीक कहते थे। आज मित्तल साहब के दिमांग से निकल गया कि इस जुई नगर को परमानेंट बनाएंगे, सिर्फ तीन महीने के लिए नहीं। इन्होंने कहा कि कुछ अर्से के अन्दर यह परमानेंट नहर बन जायेगी। यह परमानेंट कैसे बनेगी, हमारे इलाके का पानी काट लिया जाएगा क्योंकि यह हमारे इलाके में से गुजर कर जाती है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं नहर के नजदीक ही रहता हूं और देखता आया हूं, मुझे हर चीज मालूम है। मैंने यह कभी नहीं देखा कि नहर पानी से भरी हुई हो और रजवाहे खाली पड़े हों। यह चीज हमारे इलाके में क्रिएट होने वाली है जिससे हमारे इलाके को पानी नहीं मिल सकता। इसके इलावा जमींदार जब ट्यूबवैल लगाते हैं तो उनकी मदद नहीं की जाती। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के ऐक्सपर्ट जमींदारों को बतायें कि

इतनी गहराई पर पानी मिल सकता है। अगर जमींदार 12.—125 फुट तक बोर करता है और उसको पानी नही मिलता तो गवर्नमैंट के ऐक्सपर्ट उसे बतायें कि तुम 10 फुट और बोर करो तो पानी मिल सकता है लेकिन कोई हैल्प नहीं की जाती। अगर ऐसी हैल्प मिल जाए तो जमींदार का एक्सट्रा खर्च बच जाता है। सरकार के पास मुलाजम हैं, पैसा है, पता नहीं मुलाजमों से क्यों काम नहीं लिया जाता। मुलाजमों से काम ले और देखें कि पानी कहां तक मिल सकता है। जिस जमीन के अन्दर 'नूणी' है उसको ठीक करने के लिए जमीदारों को सुझाव दें कि किस तरीके से पानी दें, क्या चीज इसके अन्दर बीजें, कैसे सेम खत्म हो इन सारी चीजों के लिए जो एक्सपर्टस मौजूद होते हैं उनसे काम लिया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर के महकमें में मार्किट कमेटियां इन्होंनं बनाई। डेमोक्रेसी के अन्दर हर इंस्टीच्युशन डेमोक्रेटिक बनाया गया और उसकी वजह यह थी कि डेमोक्रेसी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके। मगर अफसोस है कि यहां इस बात का भी उल्लंघन हो रहा है। मार्किट कमेटियों की टर्म खत्म हुई लेकिन इसके अन्दर इन्होंने नौमिनेशन कर दी बजाय इसके कि इलैक्शन कराते। चौ. दल सिंह जी ने एक बात कही और वह हकीकत है। मुझे तो बाद में पता लगा लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा काम होना नहीं चाहिए। मिनिस्टर साहब फजूल ही आपे से बाहर हो रहे थे। (श्रीमती ओमप्रभा जैन की तरफ से विघ्न) हाउस से बाहर आप ही कह दें कि यह बात गलत थी तो हम मान जाएंगे। आपको भी इस बात का पता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर इस तरह से एक

मिनिस्टर रिश्वत लेकर काम करे उससे बुरी बात और कोई हो नहीं सकती।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, फिर इन्होंने कहा कि हर ब्लौक के अन्दर पांच मौडल विलेजीज बनायेंगे। इसके बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जब ये ब्लाक के अन्दर गांव छांटें तो शहर के आस पास के गांव न छांट करके इंटीरियर इलाके के कुछ दूरी पर बसे हुए गांव छांटें ताकि जब ब्लौक के मुलाजमिन उनमें जाएं तो रास्ते में पड़ने वाले विलेजीज को भी देखते जाएं। यह जो स्कीम इन्होंने बनाई है, यह बहुत अच्छी हैं बशर्ते कि इसके ऊपर ठीक ढंग से अमल हो। मुझे मालूम है कि इसमें सिवाए एग्रीकल्चर के काम के कोई और काम होना नहीं है क्योंकि चौ. माडू सिंह स्कूल वहां बनाएंगे नहीं और चौ. बंसीलाल सड़कें वहां बनायेगें जहां उनकी मर्जी होगी। तो इसके लिए यह जरूरी है कि डिफरैन्ट डारैक्शन्ज में और डिफरैन्ट प्लेसीज पर ये गांव छांटे जाएं ताकि सभी लोगों का भला हो।

उपाध्यक्षा: आप कितना टाईम और लेंगे?

श्री सत्य नारायण सिंगोल: 6 पर कोई सी सुई को ला दो, आपकी मर्जी है।

उपाध्यक्षा: छोटी को तो ला नहीं सकती परन्तु क्या आपमें इतनी हिम्मत है।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: हिम्मत देखनी है तो तमाशा देख लो। जब चार चार घंटे अदालत में हम मग्ज मार सकते हैं तो क्या यहां नहीं बोल सकते।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: यहां भी मग्ज मारने आये हो।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: यहां तो मैं सुझाव दे रहा हूं। मान लो तब तो ठीक है वरना मग्ज मारना ही होगा।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे बोलने का कल टाईम दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो आमतौर पर जनरल डिसकशन जब बाईन्ड अप होती है तभी मिनिस्टर जवाब देता है लेकिन चूंकि दो दिन रखे गए हैं इसलिए मैं कल ही जवाब दूंगी।

उपाध्यक्षा: सत्यानारायण जी आप 6 से 5 पर आ जाएं।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: बहुत अच्छा जी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं ट्रांसपोर्ट महकमें के बारे में कुछ बातें अर्ज करूंगा। ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को उंगली उठाने का मौका न मिले। जींद को आते जाते वक्त हमें असंद के पास बसस्टैंड पर उतरना पड़ता है क्योंकि 15–20 मिनट के लिए वहां बस रूकती है। पीछे जैसे जब मैं वहां रूका और चाय पीने लगा तो लोगों से मैंने पूछा कि आपका यह स्टैन्ड कब ठीक होगा? तो उन्होंने बताया कि अब आया टाईम। मैंने पूछा क्यों? तो कहने लगे कि एक अफसर का लड़का यहां आया था और

कहने लगा कि मैं जरा जमीन ले लूं उसके बाद फौरन बस स्टैण्ड इरैक्ट हो जाएगा क्योंकि मेरी जमीन पहले बिक जायेगी। इस तरह से गवर्नमैंट के सिर के ऊपर डिप्टी स्पीकर साहिबा, अफसर और उसके लड़के पल रहे हैं। इसी तरह की एक बात और मैं आपको सुनवाऊं। मेरे हल्के में एक अफसर का फार्म है वहां सारे दिन में मुश्किल से दो तीन सवारियां उतरगी होगी मगर वहां बस स्टैंड बना दिया गया है क्योंकि उस अफसर को वहां सामान उतारना पड़ता है। सफीदों इतना बड़ा शहर है, म्यूनिसिपल कमेटी वहां है तहसील हैडक्वार्टर वह है, मगर वहां बस स्टैंड नहीं बनाया गया। जींद अब तक बस स्टैंड नहीं बना। कोई इनका क्राईटेरिया नहीं है कि आया तहसील हैडक्वार्टर पर बनेगा, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर बनेगा या सब–डिविजनल हैडक्वार्टर पर बनेगा। जहां इनकी समझ में आता है बना देते हैं या जो खुशामद कर ले वहां बना देते हैं। इसमें बहुत घपलाबाजी होती है। जींद में यह मिनि–सैक्रिटेरियेट और सिविल स्टेशन बना रहे हैं। वहां इन्होंने जमीन अक्वायर की सिविल स्टेशन के लिए और हस्पताल के लिए डिप्टी स्पीकर साहिबा वहां दफा 4 का नोटिस हुआ, 6 का नोटिस हुआ लेकिन कुछ एग्रीकल्चरिस्ट की जमीन जो कि स्वयं खेती करते थे और जिस जमीन के ऊपर आज भी खेती खड़ी है, अगर विश्वास न हो तो जाकर देख लें, उसको तो अक्वायर कर लिया और पैसे दे दिए मगर दूसरी तरफ जो जमीन कैपिटैलिस्टों ने ली हुई थी उसे छोड़ा हुआ है, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि कोई पोलिटिकल प्रैशर पड़ गया तो वे

डि–रिक्वीजिशन करा देंगे। वे लोग कहते भी हैं कि डि–रिक्वीजिशन करवाना हमारे बांये हाथ का खेल है। जिस जमींदार ने तो जमीन को काश्त करना है उसकी जमीन को अक्वायर कर लेना और जिस जमींदार या दूसरे कैपिटेलिस्ट ने उस पर खेती नहीं करनी है और उसे आगे बेचना है उसे न लेना या डि–रिक्वीजिशन करना बड़ी गैर–इंसाफी का धंधा है, यह नहीं होना चाहिए। अगर इनकी छोड़नी है तो उन जमींदारों की भी छोड़ दो और सिविल स्टेशन को दस कदम 'परे' कंस्ट्रक्ट कर लो। अगर लेनी है तो सबकी लो वरना किसी की न लो। यह मेरी सबमिशन है।

इसके पश्चात् डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी सबमिशन यह है कि ये अश्योरेन्स तो दे देते हैं मगर उसे पूरा नहीं करते। पिछली दफा एक क्वैश्चन पूछा गया था और चौ. खुरशीद अहमद ने प्राईवेटली मुझे जवाब बता दिया था कि पैसा नहीं है लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि मैं महकमें को कहूंगा कि जितना पैसा लैप्स होता है वह मुझे बताओ। यह 2 लाख 30 हजार था। मैंने इनसे रिक्वैस्ट की कि सफीदों में हस्पताल नहीं है, एक छोटा सा प्राईमरी हैल्थ सैन्टर है उसको अपग्रेड कर दीजिए। इन्होंने वह 2 लाख 30 हजार रूपया सैक्शन कर दिया था परन्तु मैंने लाख कोशिश कर ली, डारैक्टर से पूछ लिया, डारैक्टोरेट से पता कर लिया, पी.डब्ल्यू.डी. वालों से पूछ लिया, उस पैसे का पता ही नहीं लग रहा कि कहां है। हस्पताल मेरे लिए नहीं है, जनता के काम

आने वाली चीज है और जनता के फायदे के लिये है। मैं समझता हूं कि इसे वहां महज इसलिये नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि मैं उस जगह को रिप्रैजैन्ट करता हूं। यह बात होनी नहीं चाहिए। इसलिये, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि उस पैसे को जहां भी वह पड़ा हो, तलाश करके वहां लगाना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा एक बात यहां यह कही गई कि ऐनक्रोचमैन्टस को एलिमिनेट करेंगे। ऐनक्रोचमैन्टस ऐक्ट जो बना हुआ है उसके अन्दर यह है कि शडयुल्ड रोड़ के दोनों तरफ 100 मीटर जगह के ऊपर कोई ऐनक्रोचमैन्ट नहीं होगी। लेकिन कई एक सड़कें ऐसी हैं जिन्हें न तो शैडयुल्ड रोड़ करार दिया गया और न ही उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन को रोका गया। कई जगह मकान बन जाएं और कई जगह न बनें इससे झगड़ा बढ़ता है। इसलिये मेरी दरखास्त है कि जो भी रोड़ बने उसे इन्हें कम्पलीट होने के फौरन बाद शडयुल्ड रोड़ करार दे देना चाहिए। आज भी जो शडयुल्ड रोड़ करार दिए हुए हैं उनके ऊपर इतने मकान बने हुए हैं जिसकी कुछ हद नहीं। उनके विरूद्ध कोई ऐक्शन नहीं लिया जा रहा है। गरीब आदमियों को तो सरकार ने नोटिस दे दिए हैं परन्तु जो बड़े आदमी हैं जिनकी अप्रोच है उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

मुझे यह तो खुशी है कि श्री रामधारी गोड़ ने हमारी एक बात को मान लिया हैं। मेरे हल्के में बोरखी गांव है। वहां पर

पंडित जी गये थे। वहां पर उन्होंने उस रजबाहे का मौका भी देखा था। देख कर इस बात के लिये मुतमइन भी हो गये थे कि यह पटरी वाकई खराब है और किसी भी वक्त टूट सकती है। उन्होंने वहां पर यह यकीन दिलाया था कि जब तक इसकी मुरम्मत न हो जाये तब तक किसानों पर किसी भी कट का ताउन नहीं पड़ेगा। परन्तु इनके मौका देखने के पश्चात् वह पटरी पांच छः बार टूट गई है लेकिन महकमें वाले उसको हमेशा कट बना देते हैं। इस तरह से उन पर कई लाख रूपये का ताउन बना दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं की पंडित जी ने यह भी यकीन दिलाया है कि इसको माफ कर देंगे लेकिन उन्हें अपना वायदा निभाना चाहिए। जब मौका देखकर ये आ चुके ह। तो फिर किसानों को परेशान करने के लिए महकमें वाले क्यों ताउन लगा देते हैं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जींद के इलाके में और करनाल के इलाकें में मुनक से मुवाना फाल तक शैलो टयूबवैल लग रहे हैं। हमारे यहां भी अंटा फाल है। उससे हमारे यहां जींद डिस्ट्रिरूयूरी नम्बर तीन निकलती है। उसके साथ ही साथ पांच–छः मील का एरिया है। अगर उसके हैड पर शैलो टयूबवैल लगाकर उस पानी को रजवाह नम्बर तीन में डाल दिया जाये तो उससे यह होगा कि वहां जो जमीन बंजर पड़ी है, नाकाबलेकाश्त हो गई है, रैह हो गयी है वह भी काबलेकाश्त बन जायेगी। दूसरा यह फायदा होगा कि वहां जो पानी निकलेगा वह

आगे विलेजीज के लिए जायेगा और सिंचाई के काम आयेगा। अगर वहां पर दस ट्यूबवैल भी लगा दिये जायें तो 10–12 ट्यूबवैलों के अन्दर ही काम बन सकता है। इस प्रकार से डिस्ट्रिब्यूटरी नम्बर तीन का पानी बढ़ जायेगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछले दिनों एक स्कीम आयी थी इन्डस्ट्री के महकमें की। वह वूल–टौप की इन्डस्ट्री थी। हरियाणा सरकार ने उस इन्डस्ट्री को जींद में लगाने को योजना बनायी और वह वूल टौप का कौटा हरियाणा में जींद जिले में जाना था। लेकिन हमारे जिले के साथ धक्का हो रहा है। उसके खिलाफ मैंने आवाज भी उठाई – जीन्द डिस्ट्रिक्ट का इन्डस्ट्री अफसर इस बात में इंट्रैस्टिड था कि वह लुधियाना के लोगों को लाकर यह इंडस्ट्री लगवाये क्योंकि वह पहले लुधियाना रह कर आया था। परन्तु इस दौरान सैन्ट्रल गवर्नमैंट की एक स्टडी टीम आयी। मैं भी उनसे मिलने की गर्ज से चला गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप भी अपना वियु बतायें। मैंने उसी समय कहा कि जींद में जो भी इन्डस्ट्री लगाये वह कोई बाहर का आदमी नहीं होना चाहिये। अगर लुधियाना का आदमी आकर यहां इन्डस्ट्री लगायेगा तो इससे अच्छा आप इस वूल टौप के कोटे को लुधियाना को दे दो। जीन्द के अन्दर लुधियाना का आदमी क्यों आये? क्या हरियाणा के लोगों को इन्डस्ट्री लगाने का मौका ही नहीं दिया जायेगा? उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के आदमी को ही इन्डस्ट्री लगाने का मौका देना चाहिए।

उसी आश्वासन के आधार पर जींद के लोगों ने खड्डियां भी खरीद लीं और दूसरी मशीनरी भी ले आये थे लेकिन वहां जो इन्डस्ट्री आफिसर लगा हुआ है उसको यह भाता नहीं था इसलिए उसने उस वूल टौप के कोटे को ही कटवा दिया है। इसलिए मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि आप इस विषय में इन्कवायरी करायें कि वह वूल टौप का कोटा हरियाणा को क्यों नहीं मिला? जो इन्डस्ट्री जींद में लगनी चाहिए थी वह जींद में ही लगायी जाये।

मैंने पहले भी दो–तीन डंगरो के हस्पतालों के बारे में जिक्र किया था। मेरे इलाके में कालवा और डढ़वाड़ा दो गांव हैं, वहां पर डंगरों का हस्पताल बनना चाहिए था लेकिन वहां बनाने की बजाए चौधरी नेकी राम ने हल्के में एक कालन में बना दिया दूसरा डुमापा खेड़ा में बना दिया। जब मेरे हल्के में डिप्टी डायरैक्टर गया तो मैंने उनसे कहा कि क्या कारण है कि इन गांवों में हस्पताल नहीं बने? उन्हौंने इस बात को मापा कि हां यहां हस्पताल डंगरों का बनना चाहिए, और आपकी डिमांड जस्टीफाईड है। जब आपका आफिसर इस बात को मानता है तो उन गांवों के अन्दर हस्पताल बनने चाहिएं। डिप्टी स्पीकर साहिब इस रूलिंग कांग्रेस ने अब बैल तो छोड़ दिये और गाय ले ली है। इसलिए उनका इलाज तो ठीक प्रकार से करायें। इस प्रकार सरकार ने तो अपना सही हाल रखना है। पहले ये कागज के बैल

पर रबड़ की स्टैम्प लगा कर उसको काटते थे, अब रकड़ की मोहर लगा कर गाय को काटना शुरू कर देंगे।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: डिप्टी स्पीकर साहिबा क्या यहां ये इलैक्शन का प्रौपेगैन्डा कर रहे है?

श्री सत्य नारायण सिंगोल: इलैक्शन प्रौपेगैन्डा से हमारा क्या वास्ता? दूसरे हम उतना प्रौपेगैन्डा नहीं करेंगे जितना आप कर रहे हैं। (घंटी) अभी एक मिनट में ही खतम करता हूं। मैंने अभी पहले दो गावों का जिक्र किया है और तीसरा गांव हाट है वहां भी सड़के बन रही हैं। चौधरी रणसिंह भी वहां गये थे, ओम प्रभा जैन भी गयी थी। काफी बड़ा गांव है। इसलिये वहां भी डिसपेंसरी बननी चाहिए।

अभी कुछ समय पहले हमारे साथी मित्तल साहब जे.बी. टी. ट्रेनिंग के बारे में जिक्र कर रहे थे कि वह क्यों बन्द कर दी? मैं तो कहता हूं कि बि उसकी क्या जरूरत है? जब पहले ही इतने टीचर बगैर नौकरियों के फिर रहे हैं? हमारे हल्के में लड़कियों का देहात में एक स्कूल भी नहीं है। इसलिए वहां स्कूल खोल दिया जाये। इस जे.बी.टी. से क्या फायदा होगा।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं अभी तक नहीं बोली हूं न गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर और न ही किसी बिल वगैरह पर।

उपाध्यक्षा: आपकी पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी की तरफ से जो चिट आयी है उसमें आपका नाम नहीं है। मैं तो आपके विषय में खुद सोच रही थी कि आप किसी भी विषय पर नहीं बोली हैं। मगर फिर भी मैं आपको इनके बाद टाईम दे दूंगी।

श्रीमती चन्द्रावती: मैं भी अभी तक नहीं बोली हूं मुझे पहले टाइम मिलना चाहिए।

उपाध्यक्षा: आप पहले बोलिए फिर प्रसन्नी देवी जी बोलेंगी।

चौ. जय सिंह राठी: इनकी ही पार्टी के बोलना चाहते हैं और यही आपस में मुखालिफत कर रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): डिप्टी स्पीकर साहिबा आपने मुझे समय दिया मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं अपनी बजट स्पीच शुरू करने से पहले हमारे बड़े भाई मित्तल साहब, ने जो कुछ बातें मेरे विषय में कहीं हैं उनका जवाब देना चाहूंगी। मैं जब ऐ एम.एल.ए हूं तभी से यह देखने में आया है कि आदतन अपोजीशन का लीडर ही हमेशा पहले स्पीच शुरू करता है। मैंने तो सोचा कि मित्तल साहब कहीं कांग्रेस से डिफेक्ट तो नहीं कर गये हैं। मैं यह बात उनके नोटिस में लाना चाहती हूं कि भले ही यह बात उनको बुरी लगी लेकिन मेरा बुरा लगाने का कोई मकसद नहीं था। मैंने तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो पुरानी रिवायात चली

आ रही हैं हाउस में उसके अनुसार क्युरैसिटी को पूरा करने के लिए यह बात आपसे जाननी चाही थी।

यह जो बजट श्रीमती ओम प्रभा जैन जी ने यहां हाउस में रखा है, बहुत अच्छा बजट है। इसके बावजूद भी मैं अपने कुछ सुझाव हाउस के सामने रखना चाहूंगी। (इस समय सभापतियों की सूची के एक सदस्य चौ. जय सिंह राठी पदासीन हुए) चेयरमैन साहब मैं यह मानती हूं कि इस दो–अढ़ाई साल के अन्दर काफी रूपया खर्च हुआ है भिन्न भिन्न योजनाओं पर लेकिन जो मैं समझती हूं और जो आज के संसार की गति है उस गति का हिसाब दिनों और महीनों में न लगा कर आज हमें मिनट और सैकिन्डों में लगाने की आवश्यकता है। उस हिसार से प्रगति की रफतार कुछ धीमी है। मैं दूसरे सूबों का हिसाब नहीं लगाती हूं। हमें तो संसार की प्रति का हिसारब लगाना चाहिए। जब हम फैंशन में और दूसरी चीजों में संसार की नकल करते है। तो हमें तरक्की करने में भी दूसरे देशों की नकल करनी चाहिए। उसी के हिसाब से मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूं। कुछ बातें सख्त भी हो सकती हैं। अगर सख्त कह भी दी जायें, तो जो राज करते हैं उनका दिल तो बड़ा होना चाहिए। उनमें कुछ सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े दिन लसे काम करते हैं, काम करने में दिलावर भी हैं लेकिन साथ साथ जुल्म करने में भी बड़े दिलावर हैं। परन्तु उनको हाउस का बड़ा डर लगता है। मुझे एक कहानी याद आ गई रात के वक्त कुछ गरीब लोग आपस में

बातें कर रहे थे कि टपकले से बड़ा डर लगता है, क्योंकि कुछ बुन्दाबान्दी भी हो रही थी। वह गांव कुछ जंगल में था। इसलिए उस जंगल से कोई शेर आकर उस 'चीड़े' में आकर खड़ा हो गया। इधर से किसी कुम्हार का गधा भी, खो गया वह अपने गधे को तलाश करता हुआ फिर रहा था। बरसात का मौसम था ही, कुछ बिजली का चमका लगा .....

मुख्यमंत्री (बंसीलाल): चेयरमैन साहब, मुझे तो हाउस का डर लगता है, इसलिए बहन जी को गधे 'टोने' भेज दो, ये 'टो' लायेंगी, हाउस को फिर देख लेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती: आप मेरी बात पूरी होने दें उसके बाद कह लेना। गधे तो यहां भी मिल सकते हैं ढूढने की जरूरत नहीं है चेयरमैन साहब, मैं कहने जा रही थी कि उसने थोड़ी चमक में देखा तो उसने यह समझा कि यह गधा है। कुम्हार ने उसका कान पकड़ा और उसके ऊपर चढ़ गया। दिन में जब रोशनी में देखा तो वह शेर था। कुम्हार ने सोचा कि यह बहुत मुश्किल बात हो गई। जैसे छान में टपकने का डार लगता है (उसका मतलब है वह छान चोती थी) इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी को भी टपकले का डर लगता है लेकिन हाउस में तो कोई टपकला नहीं है। डरने की क्या जरूरत है? हम मैजोरिटी में हैं। डेमोक्रेसी के अन्दर एक एम.एल.ए. है, यह उसका काम नहीं कि किसी को नौकरी पर लगवा दे। यह काम तो सरकार का है। जो लोग ऐग्जैक्टिव में बैठ गये हैं, सब लोगों को काम दिलवाना

उनका काम है। परन्तु आजकल तो ट्रान्सफर का काम एक बिना काम का धन्धा शुरू हो गया है। उसका कोई नियम नहीं है। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगी कि उसका कोई नियम, कानून या कायदा होना चाहिये। एक एम.एल.ए. का समय जो इसता कीमती समय होता है, स्टेट की भलाई के लिये होता हे। अगर ट्रान्सफर के लिये सर्विसिज में कोई कायदा कानून एक या दो साल के लिये बनाया जाए तो सरकार की यह दिक्कत मिट जाती है और एम.एल.ए. की भी मिट जती है। मैं हमेशा ऐडमिनिस्ट्रेशन की एक बात को महसूस करती हूं और यह जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है उसकी आदतन तारीफ करने वाले लोगों में से मैं नहीं हूं। मैं यह महसूस करती हूं कि ब्यूरोक्रेसी का इतना कसूर नहीं होता जितना पौलिटिशियन्ज का होता है। अगर पौलिटिशियन्ज चाहें तो ब्यूरोक्रेसी में ऐफिसिऐन्शी भी हो सकती है। ब्यूरोक्रेसी में अगर काम तेजी से करवाना चाहें तो भी पौलिटिशियन्ज ही करवा सकते हैं। मैं एक उदाहरण को दिये बिना नहीं रह सकती। मुझे याद है कि डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ के एक साहिब डिप्टी कमिश्नर थे। जब वह छुट्टी या 4 महीने की ट्रेनिंग के लिये चले गये तो उनकी जगह पर एक एस.डी.ओं. को चार्ज दिया गया। उनको इतना ऐक्सपीरियंस नहीं था और वे कामयाब नहीं हुए लेकिन आदमी बहुत अच्छे थी। बदकिस्मती से उनका ऐक्सीडेंट हो गया और उनको कुछ चोटें आई। अब अगर वे छुट्टी पर जायें तो डी.सी. की कुर्सी चली जायेगी इस वजह से बेचारा हस्पताल में कुछ दिन रह कर अपने घर में ही काम करता रहा लेकिन छुट्टी नहीं ले

सका। छुट्टी ले ले तो वह पोस्ट चली जाए। मैं समझती हूं कि अफसरों में इस बात का कंफिडेंस होना चाहिये कि अगर वे योग्य हैं तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको उनका औहदा जरूर मिलेगा। अभी भी उनको शायद छुट्टी भेजा गया है या नहीं मुझे पता नहीं लेकिन अब वे वहां नहीं हैं। बेचारा अपना इलाज भी ठीक ढंग से नहीं करवा सका। अगर हम इतना भी यकीन अपनी सर्विसिज में नहीं दिया सकें तो मैं समझती हूं कि जो लिंक पौलेटिशियन और ब्यूरोक्रेसी के बीच में होता है वह नहीं हो सकेगा। चेयरमैन साहिब, मैं कुछ बातें सामने लाना चाहती हूं। कृषि सुधार के लिये इन्होंने काफी कोशिश की। काश्तयोग 82 लाख एकड़ भूमि में से 50 लाख एकड़ में बाढ़ें आती थी। इसी तरह 20 लाख एकड़ भूमि में सूखा पड़ता था दोनों को ठीक करने के लिये और बाढ़ को रोकने के लिये लोहारू ओर जुई की योजना बनाई जिसमें 7.98 करोड़ रूपया लगाया गया। यह एक अच्छी बात है क्योंकि जुई तोशाम का और कुछ सिवानी का एरिया है जिसमें पानी पीना भी मुश्किल है। वहां पर नलों का पानी दिया जाता है जो कि मात्रा में बहुत थोड़ा रहता है। जिस हिसार ने नलों में गर्मी में पानी आता है उस हिसाब से उनके आगे 'बाशनो' की लाईन लग जाती है। इसके बावजूद भी वह स्कीम है बहुत छोटी बनाई गई है। हम लोगों को सकेरसिटी क्रिएट करने की आदत पड़ गई है। मुझे बताया गया है कि पांच गेलन पानी एक परिवार को मिल पाता है। जमींदार जब हल बाह कर घर आता है तो वह एक बार में ही आधा घड़ा पी जाता हैं। पानी उनको बहुत

कम मिकदार में मिलता है। हो सकता है कि इस नहर के आ जाने से सब–स्वायल वाटर कुछ मीठा मिल जाए और इन लोगों की दिक्कतें भी कुछ दूर हो जाएं लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात महसूस करती हूं और कहना चाहती हूं कि जमींदार कितनी ही पैदावार बढ़ा ले उसको पैसा तो उतना ही मिलता है। यदि वह सौ मन पैदा करेगा तो भी उतना ही मिलेगा और यदि दो सौ मन पैदा करेगा तो भी उतना ही मिलेगा क्योंकि भाव गिर जाते हैं। बाजरे का भाव 85 रूपये से 45 रूपये रह गया। मैं आपको आंकड़े बता रही हूं और आई बार ही ऐसा होता है। अब यदि गेंहू ज्यादा हो जाएगा तो गेहूं का भाव भी घट जाएगा। किसी चीज की भी जैसे दियासिलाई की सिग्रेट की, चाय की, मेरा मतलब है जो सीधे कारखाने से आती हैं उनकी कीमतें कभी नहीं घटती। जैसे ग्राफ बढ़ता है उसकी तरह से इनकी कीमतें भी बढ़ती चली जाती हैं लेकिन जो किसान के घर में चीज पैदा होती है उसकी फसल घर में आने के एक दम बाद किमतें बिलकुल डाऊन चली जाती हैं। तो उनका कहीं तो हिसाब किताब देखें। हम अगर आंकड़े देखने लगे तो सब चीजों की कीमतें तो ग्राफिक तरीके से बढ़ी हैं लेकिन जो खेतों में पैदा होता है चाहे वह कपास हो चाहे वह आयल सीड्ज हों कोई भी चीज हो, कम से कम उनकी कीमतें साल में दो बार घटती हैं। मगर फिर भी हम कहते हैं कि हम तो गरीबों के लिये काम करते हैं। हमारे यहां किसानों की मैजोरिटी है, इसलिये हमें चाहिये कि उनके फायदे के लिये काम करें। अगर नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? स्वास्थ्य के बारे में मैं यह कहना

चाहती हूं कि अगर हम थोड़ा बहुत भी औबजर्व करें तो हमें मालूम होगा कि लोगों को प्रोटीन की मात्रा उस हिसाब से नहीं मिलती है जिस हिसाब से मिलनी चाहिये। जापान की औसत लम्बाई 20 साल में दो इंच बढ़ी है। लेकिन हमारे यहां मैं समझती हूं दो इंच घटी है। क्या पता हम कितने छोटे होते चले जाएंगे ओर वह कितने लम्बे होते चले जाएंगे। रोहतक में हरियाणा का मैडीकल कालेज है। मैं किसी के खिलाफ शिकायत नहीं करती लेकिन वहां पर यदि कोई बीमार चला जाए तो बीमार के पीछे तीन आदमी और चाहियें। वहां अच्छा खाना नहीं मिलता। कहां से लाएं खाना? या तो कोई मकान किरायें पर लेकर रहें या फिर ढाबे वाले से लाएं। अगर हस्पताल में आप बीमार को खाना नहीं दे सकते हैं ओर उस बीमार की देखभाल के लिये तीन आदमी चाहियें तो मैं समझती हूं कि अपने जैसे गरीब देश में किस तरह से लोग इलाज करवाएंगे? मैं चाहती हूं कि वहां पर उस हस्पताल में खाना मिलना चाहिये। यदि देखा जाए तो जो तीन आदमी वहां रहते हैं उनको खाना अपना बनाना सस्ता पड़ेगा। लेकिन मैं चाहती हूं कि बीमार को हस्पताल से ही खाना दिया जाए और उसके बिल में उसके पैसे लगा दिये जाएं। मैं चाहती हूं कि सरकार मेरे सुझाव को जरूर मानें क्योंकि हमारे यहां एक ही तो बड़ा हस्पताल है और उस हस्पताल में खने का इंतजाम नहीं है। जो रोगी है उनको इससे बड़ी दिक्कत होती है। मैं समझती हूं कि यह दिक्कत सभी को ही होती होगी। शायद पैसे वालों को

दिक्कत इतनी नहीं होती होगी क्योंकि वह पैसा खुल्ला खर्च कर सकते हैं।

चेयरमैंन साहब, मैं आपको बताने जा रही हूं कि इसी तरह से जो रूरल हैल्थ सैटर्ज हैं, वहां पर एक्सरे प्लांट नहीं हैं। मैं समझती हूं कि आज के युग में हर एक अस्पताल में एक्सरे प्लांट जरूर होना चाहिये। अब लोग दवाई तो अगर अस्पताल में न हो, बाजार में लेंगे मगर यदि किसी की हड्डी टूट गयी है, तो उसको ऐक्सरे करवाने के लिये कहीं दूर जाना पड़ेगा। इसलिए मैं समझती हूं कि यह निहायत ही जरूरी है कि चाहे कोई अस्पताल गांव का हो या शहर का, उसमें ऐक्सरे प्लांट अवश्य होना चाहिए। हमारे यहां डाक्टरों की कमी है और खासतौर पर लेडी डाक्टरों की तो बहुत कमी है। इसके इलावा रूरल अस्पतालों की तो बहुत ही कमी है। इसलिए मैं यह चाहूंगी कि सरकार ने हैल्थ सैंटर्ज तथा अस्पतालों के लिये जो पैसा रखा है, वह बहुत कम है। इनके लिए ज्यादा पैसा रखना चाहिए। चेयरमैन साहब, मुझे याद है कि जब पंजाब और पैप्सू मर्ज हुआ और जब मैं पार्लियामैंट्री सैक्रेट्री थी, तो गुड़गांव के आस पास कुछ माडल विलेजिज बनाये गये थे। कुछ हरिजनों के गांव भी उसमें थे। वहां देखने के लिये फारनर्ज भी आते थे। मैं खुद भी देखकर आयी थी और मुझे उन्हें देखकर बड़ी हुई थी। अब तो मुझे पता नहीं वह गांव कहां गये। वह फरीदाबाद सलम एरिया में चले गये या गुड़गांव के स्लम एरिया में चले गयें मैं चाहती हूं कि पांच गांव ही मौडल बिलेज न

बनाएं बल्कि सो गांवों की ही प्लानिंग ऐसी बननी चाहिए कि कहां गावं का जंगल होगा, कहा स्कूल होगा और कहां दूसरी चीजें होगी। यह सब बातें हमको सारे गांवों के लिये ही करनी चाहिएं। मैं तो यह समझती हूं कि इन्होंने शहरों का जो प्लानिंग किया है, वहां पर वही बुरी हालत है। हम वैसे तो समाजवाद की बहुत लम्बी चौड़ी बातें करते हैं लेकिन जहां अफसरों की कालोनी होगी, मेरी किसी खास अफसर की ओर इशारा नहीं है, आप मुझे माफ करेंगे, वहां ज्यादा देर तक पानी आयेगा और जहां दूसरे लोग रहेंगे वहां पानी कम आयेगा या कम देर तक आयेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि कया वजह है कि हम इन लोगों के लिए हर चीज की सकैरसिटी क्रिऐट करते हैं। हम आजतक भी छोटे–बड़े का फर्क रखना चाहते हैं। हम आज भी यह चाहते हैं कि पानी भी कुछ प्रिवीलेज्ड लोगों को ही मिले या कुछ प्रिवीलेज्ड लोगों को ज्यादा मिले और बाकी के लोगों को कम मिले।

इस सरकार ने गरीब आदमियों यानी हरिजन वगैरा के लिये यह रखा है कि उन्हें मकान बनाने के लिये लोन दिया जायेगा। यह बहुत अच्छी बात है और मैं इसे एप्रीशियेट करती हूं और चाहती हूं कि उस लोन का यूज भी ठीक से हो। उसका यूज ठीक से तभी होगा जबकि लोगों का पता लगेगा कि यदि हम इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लोन वापस ले लिया जायेगा या कुछ और कार्यवाही की जायेगी। कुछ एक गांवों की लाइफ तो नर्क के बराबर है। एक बार सरकार का ध्यान भी था कि जो

बड़े–बड़े गांव हैं, वहां पर यह मिलिटरी टाईप का सैनेटरी सिस्टम या कोई और सिस्टम लगायेगी। जब तक मिलिटरी फीडिंग एरियाज की जो मांए और बहिनें हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक कहां से स्वस्थ लोग या अच्छी पीढ़ी पैदा हो सकेगी? मैं थोड़ी सी बातें और कहना चाहूंगी।

चेयरमैन साहब, शिक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि मैं जहां तक समझती हूं शिक्षा में बिल्कुल ही परिवर्तन करने की जरूरत है। जो निगलैक्टिड एरियाज या गांव होते हैं, मैं नहीं समझती कि उनको आगे आने का चान्स मिलता हो। यह जो लोग ऊपर के औहदों पर बैठे हैं यह नहीं चाहते कि गांव के लोग भी योग्य हो जायें ओर ज्यादा सर्विसिज में आयें। यदि वे योग्य हो जायेंगे तो वे इनके साथ कम्पीटीशन करेंगे। इसलिए हो सकता है कि इनकी नीयत में भी कुछ खराबी हो और ये चाहते हों कि जैसा सिस्टम चल रहा है वही चलता रहे, तो ठीक है। इस वक्त जो सिस्टम है वह बिल्कुल असंतोषजनक है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगी कि इस सिस्टम से देश का चरित्र नहीं बनेगां गांव हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं अगर यह सिस्टम जो कि उसको तोड़ने का एक साधन है, हमने इसे दूर नहीं किया तो शहर वाले लोग भी इससे बचेंगे नही क्योंकि गांव के जो इतने लोग खराब होंगे उनके प्रभाव से बड़े लोगा जिनके बच्चे अच्छे–अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन पर भी इसकी आंच जरूर आयेगी। बंगाल का जो हाल हो रहा है, वह हम देख रहे हैं। वहां एक आदमी तो 2

करोड़ रूपये के मकान ने रहता था और लाखों–करोड़ों आदमी फुटपाथ पर सोते थे। वहां पर जो असर पड़ा है, वह हम आज देख रहे हैं। मैं चाहती हूं कि शिक्षा ऐसे ढंग की हो जिससे कि गांव के बच्चों को भी अच्छी लाईफ महसूस हो सके ओर जो लोग थर्ड डिवीजनर हैं उनको गांव में मास्टर न बनाना चाहिए। मैं चाहती हूं कि मास्टर की समाज में कुछ इज्जत हो। उसके लिये मैं चाहूंगी आपने उन्हें कोठारी कमीशन तो नहीं दिया, लेकिन अच्छी तनख्वाह दें। वह बड़ा कमजोर तबका है और लोग सबसे ज्यादा उनकी वजह से नाराज हैं उनकी संख्या बहुत कम है ओर उनकी हड़ताल से गवर्नमैंट की मशीनरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए उनकी बातों को कोई ध्यान से नहीं सुनता है। मैं समझती हूं कि जो मास्टर हैं, वे आपके बच्चों के भविष्य के बनाने वाले हैं। इस चीज के लिये कि भविष्य में इस धन्धें में अच्छे लोग आयें, आपको उनके गुजारे लायक तनख्वाह देनी चाहिए।

श्री सभापति: आप कितना समय और लेंगी?

श्रीमती चन्द्रावती: चेयरमैन साहब मैं पहले कई ऐसे सब्जैक्टस पर बोली नहीं हूं। अगर आप मुझे और टाईम दे देंगे, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

श्री सभापति: बहिन जी, क्योंकि टाईम की अलाटमेंट करनी है इसलिए आप खुद ही बता दें कि आप चार मिनट लेंगी या पांच मिनट लेंगी .....

श्रीमती चन्द्रावती: चेयरमैन साहब, मैं हालांकि बहुत ज्यादा बोलने वालों में से नहीं हूं लेकिन पांच मिनट तो नहीं, कुछ और ज्यादा टाइम दे दिया जाय।

चौ. हरकिशन लाल कम्बोज: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सरं अभी दो–तीन रोज पहले स्पीकर साहब ने यह फैसला फरमाया था कि किसी भी सदस्य को 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा और 15 मिनट से ज्यादा किसी भी हालात में नहीं दिया जायेगा। श्रीमती इन्द्रावती जी के 15 मिनट हो गये हैं, इसलिए मैंने यह प्वायंट खड़ा किया है।

श्री सभापति: मेरे पास अभी–अभी स्पीकर्ज की लिस्ट आयी है, इसीलिए मैने उनसे पूछा है कि वे कितना टाईम लेंगी क्योंकि दूसरों के लिये भी मैंने टाईम मुकर्रर करना था। इनके बाद कोई भी मैम्बर ज्यादा समय नहीं बोलेगा।

श्रीमती चन्द्रावती: चेयरमैन साहब, इनको 5–7 मिनट और बोल लेने दें। इनके बाद 10 मिनट वाला सिस्टम मुकर्रर कर लें।

श्री सभापति: ठीक है, ये बोल लें।

श्रीमती चन्द्रावती: चेयरमैन साहब, दूसरे मुल्कों में जो मुफ्त शिक्षा दी जाती है, उसका मतलब है कि बच्चों को हरेके चीज जैसे स्टेशनरी कागज, किताब आदि सब कुछ मुफ्त मिलता है और इसके साथ ही साथ दोपहर का खाना भी मुफ्त मिलता है।

हमारे यहां यदिी 5 रूपये की फीस माफ कर दें तो हम लोग करते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। चेयरमैन साहिब, हर आदमी शिक्षा क्यों नहीं ले पाता? हमने अपने कांस्टिरूयूशन में लिखा है कि हर आदमी को शिक्षित करेंगे? 22–23 साल में लड़कियों को तो हम शायद 0.20 प्रतिशत ही शिक्षित कर पायें हैं। लड़कों की शिक्षा शायद ज्यादा होगी लेकिन फिर भी मैं यह समझती हूं कि हमारे यहां बहुत ज्यादा इल्लीट्रेसी हैं। हम बच्चों को किताबे तक नहीं खरदी कर दे सकते। इसलिये यह जरूरी है कि बच्चों को मुफ्त किताबें मिलें? ज्यादा नहीं तो कम से कम आठवीं श्रेणी तक तो मुफ्त किताबें मिलनी ही चाहिए ताकि सारे लोगे लिट्रेट हो सकें। बात यह है कि हमारी सरकार गांवों तक में भी 10 पैसे चन्दा लगा देती है। गांवों में 75 प्रतिशत बच्चों की मांए ऐसी होती है जो उनको 10 पैसे भी नहीं दे सकतीं। वे किताबें कहां से खरीद कर देंगी? सरकार ने हरिजनों को इतना बढ़ावा दिया है लेकिन इसके बावजूद भी वे इतने कम पढ़े लिखे क्यों रह गये? इसलिये कि वे किताबें नही खरीद सकते। आपने शिक्षा के लिये जो बजट में पैसा रखा है वह बहुत कम है, इसके लिये और ज्यादा पैसा रखना चाहिए। मैं समझती हूं कि आपको मेरा यह सुझाव मानना चाहिए कि बच्चों को किताबें मुफ्त मिलनी चाहिएं।

चैयरमैन साहिब अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहती हूं। मुझे खुशी है और मैं तो इसे बहुत अच्छी बात मानती हूं कि

हर गांव में बिजली पंहुच गई हैं मैं मानती हूं कि हर घर में तो बिजली नहीं पहुंची लेकिन हर गांव में जरूर पहुंच गई। लेकिन इसके बावजूद विलेजिज में डोमैस्टिक कंजम्पशन जीरो के बराबर है। इसके बारे में मैने एक सवाल पूछा था लेकिन उसका उत्तर नहीं आया। टयूबवैल की जो बिजली मिलती है वह बहुत मंहगी है। हमारी पालिसीज ने पहले ही व्यापारी को चोर बना दिया और अब किसान भी चोर बन जाएगा। क्योंकि जो बिजली का रेट हे अगर उस रेट के हिसाब से भुगतान किया जाए तो एक साल में ट्यूबवैल पूरा बिक जाएगा और वह अगले साल बिजली नहीं ले सकेगा। बिजली की दर बहुत मंहगी है और पानी बहुत गहरा है। अम्बाला और करनाल में कुछ पानी उथला है बाकी सब जगह पानी काफी नीचा है। इसलिए मै। सरकार से दरखास्त करूंगी कि चाहे सरकार को कुछ दिक्कत आए लेकिन बिजली की दर कम होनी चाहिए। ये दरें ऐसी है जिन दरों पर किसान आज भी बिजली नहीं ले सकता है। (इस समय सभापतियों की सूची के एक सदस्य प्रिंसिपल ईश्वर सिंह पदासीन हुए)।

चेयरमैन साहब, मैं जंगलों के सम्बन्ध में भी कहना चाहती हूं। हमारे पास जो आंकड़े है उसके अनुसार हरियाणा में दो फीसदी जंगल हैं, देश के दूसरे हिस्सों में बीस फीसदी है और शायद प्लानिंग वाले 1/33 का हिसाब रखते है। मेरा कहना तो सिर्फ यही है कि जहां भी जगह मिले वहां कोई न कोई पेड़ लगा देना चाहिए। क्योंकि पेड़ लगने से एक तो सड़क कम टूटेंगी और

डस्ट कम होगी, जिससे सफाई की समस्या हल हो जाएगी। आज जिस तरह से घरों का फर्नीचर तथा दुकानों का फर्नीचार बन रहा है अगर जंगलों की यही हालत नही तो हमें एक बालिस्त लकड़ी भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि हर शहर और गांव की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि उस गांव या शहर को छोटा–मोटा जंगल हो। रहिड़ा, जड़ बेरी, जांट जैसे पेड़ खूब लगाने चाहिएं। चेयरमैर साहब मैं एक–दो बातें और कहकर अपना स्थान लूंगी।

ट्रैक्टर से सम्बन्धप में मैं यह कहना चाहती हूं कि ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और मैं तो वही बात दुहराती हूं कि हर चीज की सिकेयरसिटी क्रिएट की जाती है। चेयरमैन साहब, पुराने जमाने में ठगी कानून में चलती थी और ठगी करना कोई बुरी बात नहीं मानी जाती थी। ठगी लार्ड बेन्टिग के जमाने में थी। जिस चीज पर ज्यादा नफा हो, ज्यादा कमीशन हो उसी की सिकेयरसिटी कर दी जाती है तो ठगी और सिकेयरसिटी एक ही चीज है। फर्क सिर्फ इतना है कि सिकेयरसिटी बीसवीं सैन्चरी की है और ठगी 16वीं–17वीं सदी की है। अगर हमने इन चीज को नहीं हटाया तो मैं समझती हूं कि दूसरी समस्याओं की तरह यह भी एक राक्षस की तरह हमारे सामने आएगी। मैं एक चीज और कहकर समाप्त करूंगी। सड़कों के बारे में कहा गया है कि दो साल के अन्दर तमाम सड़कें बना दी जाएंगी। मैं तो अपने इलाके की बात जानती हूं कि मेरे इलाके में चैड़ की सड़क बन रही थी

वह भी अभी बन नहीं पाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह सड़क जरूर बन जाएगी। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्रीमती प्रसन्नी देवी (इन्दरी): चेयरमेन साहब, आज हाउस के सामने हमारी वित्तमंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया है उस पर बहस शुरू हुई है। बजट को देखने से ऐसा लगता है कि पिछले सालों की तरह से यह बजट बहुत अच्छा है और इस बजट के जरिए हरियाणा पिछले सालों से भी ज्यादा हरेक क्षेत्र में तरक्की कर सकेगा। चेयरमैन साहब, अगर हम अपनी सरकार के पिछले दो–अढाई साल के काम को देखें तो पता लगता है कि पिछले बीस सालों में भी उतना काम नहीं हुआ है जितना इन अढाई सालों में हुआ है।

कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां बाढ़ बहुत भंयकर रूप से आती थी और कुछ इलाके ऐसे थे जहां सूखा ही सूखा था। मैं ऐसे इलाके से चुनकर आती हूं जहां साल में पांच–छः महीने पानी रहता है। वहां के लोग पानी में घिरे रहते थे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता था। मैं सरकार की बहुत ज्यादा सराहना करती हूं कि उसने मेरे इलाके मैं इस बाढ़ की समस्या को बहुत हद तक हल कर दिया है और जहां पानी की कमी थी वहां कम से कम पाने का पानी तो हर गांव में पहुंचा दिया गया है। इसके साथ ही जुई और लोहारू केनाल बनाकर इस सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। चाहे थोड़े समय के लिए ही इनसे पानी मिलेगा लेकिन उससे भी बड़ फायदा होगा। कुछ लोग कहते हैं

कि हमारा पानी काटकर इन नहरों को दिया गया है। मैं तो यह कहती हूं कि जिन इलाकों में बिल्कुल पानी नहीं है वहां अगर हमार हिस्से में से थोड़ा पानी काटकर उनको दे दिया गया है तो इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि जहां पानी दिया गया है वह हरियाणा का ही हिस्सा है और जिन लोगों को दिया गया है वह भी हमारे हरियाणा के हैं। मैं इस काम के लिए सरकार की बहुत सराहना करती हूं, जिसने बाढ़ को रोकने के लिए और सूखे को खतम करने के लिए इतना अच्छा कदम उठाया है। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अभी मेरे इलाके में बहुत काम करने को है क्योंकि वह सारा इलाका जमुना के साथ साथ चलता है और बड़ी जमुना के साथ कई जगह छोटे नाले जिनको छोटी जमुना कहा जा सकता है, बरसात के दिनों में जो गांव परली तरफ हैं उनके रास्ते इधर आने के लिए बन्द कर देते हैं और जो गांव इस तरफ हैं उनके लोगों के लिए उधर जाने का रास्ता बंद कर देते हैं और जो गांव इस तरफ हैं उनके लोगों के लिए उधर जाने का रास्ता बन्द कर देते हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी कि इन गावों में जहां पानी भर जाता है वहां पर पुल बनाए जाएं जिससे कि लोगों की समस्या कुछ हल हो सके।

5.00 p.m.

यह ठीक है कि वहां पर पुल कई कई लाख की लागत से कम नहीं बन सकते, लेकिन जब हरियाणा सरकार इस बात को सामने रखकर चल रही है कि जो इलाके पिछड़े हुए हैं या जहां

पर काम नहीं हो सका उनको दूसरों के बराबर लाने के लिए पैसा ज्यादा खर्च किया जाएगा तो फिर उन पुलों को पहले बनाया जाना चाहिए। मैं इस बात को मानती हूं कि जमुना पर एक लम्बा चौड़ा बांध बांधा गया है लेकिन अभी तक काफी एरिया ऐसा है जहां पर या तो बांध बनाए जा सकते हैं या जो जमुना से छोटे–छोटे नाले निकलते हैं उनको बांध कर पक्की ठोकरें बनाई जा सकती हैं। ऐसा करने से लोगों को बहुत सहायता मिल सकती है। मेरे इलाके में बहुत सी ड्रेनें हैं। इंद्री ड्रेन जो है उसमें काफी पानी आता है, जमुना कैनाल की बड़ी नहर भी वहां से ही गुजरती है, एक अनौरी स्केप है। इस तरह से वहां पर छोटी छोटी काफी ड्रेनें हैं। अगर उस सारे पानी को किसी तरीके से इक्ट्ठा करके उन इलाकों को दिया जाए जहां का पानी नहीं पहुंचता तो ऐसा करने से जिनको पानी मिल जाएगा उनकी खेती अच्छी हो सकती है और जो अब पानी में डूबे रहते हैं वे बच सकते हैं। हमारे यहां एक पुरानी नहर है जो किसी जमान में जमुना कैनाल की वजह से खोदी गई थी। इसकी वजह से काफी जमीन बेकार पड़ी है। किसी का खेत परली तरफ है और किसी का खेत उरली तरफ हैं अगर उस नहर में पानी इकट्ठा करके कहीं आगे लेजाकर उन इलाकों को दिया जाए जहां पर सूखा पड़ता है तो उससे काफी बजत हो सकती है। मैं प्रार्थना करूंगी कि इसका आप सर्वे करवाएं ओर इस काकम को जल्दी करवाने का यत्न करें। जैसे मैं पहले बता चुकी हूं उस इलाके में छोटी छोटी काफी ड्रेनें हैं। घनौरा ड्रेन और इन्द्री स्केप तो बडी सिरदर्दी बनी हुई हैं और वहां पर पुल न होने

की वजह से लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। गवर्नमैंट का तो यह पुराने हिसाब से कानून चला आ रहा है कि तीन मील के फासले से कम एरिया में पुल नहीं बनाया जाएगा। मगर अब अगर गवर्नमैंट इसी पालिसी पर चलेगी तो मेरे इलाके के लोगों की तकलीफ कभी भी दूर होने की सम्भावना नहीं हो सकती। घनौरा स्केप ओर इन्द्री स्केप के साथ साथ एक तरफ गांव है तो दूसरी तरफ खेत है, लोगों को कई कई मील का चक्कर डालकर अपने खेतों में जाना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगी कि उनके लिए जो तीन मील की शर्त रखी हुइ है वह हटाई जानी चाहिए और जिन जिन गांव को पुलों की जरूरत है वहां पर जल्दी से जल्दी पुल बनवा कर देने चाहिए। जमुना की बड़ी नहर मेरे इलाके के बची में से गुजरती है और लोगों को उसमें से पानी नहीं मिलता लेकिन उससे सेम वहां पर बहुत हो जाती है। उस नहर का निकाल बढ़ाने के लिए उसे कई कई फुट ऊंचा किया गया है। इसके आस पास के जो गांव हैं उन लोगों को अपने पशुओं को पानी पिलाने की बहुत तकलीफ है। अगर लोग वहां पर खुद गऊघाट बनवाना चाहें तो उनके पास इतना पैसा नहीं है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी कि सरकार अपनी तरफ से वहां पर गऊघाट बनवाने ककी कृपा करे और इसके लिए बजट में प्रोविजन कर दी जाए।

इसके बाद मैं सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले दो अढाई सालों में

हरियाणा सरकार ने जितनी सड़कें बनाई हैं वह एक रिकाड है। मेरा खादर का इलाका है, वहां पर बहुत तादाद में सड़कें बन भी गई है लेकिन अभी तब सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनको दस–दस पंद्रह–पंद्रह मील कच्चे रास्तों पर स चल कर जाना पड़ता है। तो मैं निवेदन करूंगी कि उस इलाके के लिए दो साल की कंडीशन न रखी जाए बल्कि उनको नम्बर 1 पर रखकर दूसरे इलाकों की निस्बत पहले सड़कें बनाई जाएं ताकि वह इलाका भी और इलाकों की तरह तरक्की कर सके।

श्री सभापति: आप और कितना टाईम लेना चाहती?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: मुझे दस मिनट और दे दीजिए। अगली बात आती है हैल्थ के बारे में। इसके लिए वैसे तो सरकार ने काफी पैसा रखा है लेकिन जिस हिसाब से अब काम चल रहा है और जितना उसको फैलाने की जरूरत है उसके हिसाब से वह पैसा कम है। मेरे हल्के में पूरे ब्लाक में एक ही हैल्थ सैंटर है। जो गांव सड़कों से जुड़े हुए हों वहां पर तो कुछ न कुछ गुजारा हो सकता है लेकिन जहां पर रास्ते ठीक न हों और एक ब्लाक में सैंकडों गांव आ जाते है जैसे कि मेरे इलाके में है वहां पर लोगों के लिए बहुत मुश्किल पेश आती है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि जैसे आप की सड़कों के लिए और बिजली के लिए स्कीम है इसी ढ़ंग से इसके बारे मे ंभी स्कीम बनाएं और कम से कम पांच मील के एरिया में सब–सैंटर होना चाहिए और इस मील से ज्यादा फासले पर लोगों को प्राईमरी हैल्थ सैंटर के लिए नहीं

जाना पड़े। आजकल प्राईमरी हैल्थ सैंटरों में लेडी डाक्टरों के न होने से बहुत मुश्किल पेश आती है। इसकी वजह यह है कि हमारे देहातों की बहुत कम लड़कियां है जो डाक्टर बनती हैं और जो शहरों की लड़कियां होती हैं वे जब डाक्टर बनती है तो उनकी कोशिश यही होती है कि हमें शहरों में या अच्छे कसबों में लगाया जाए। इस कमी को पूरा करने के लिए मैं सुझाव देती हूं कि हमारे जो मैडिकल कालेज हैं उनमें देहातों की लड़कियौं के लिए सीटें रिजर्व की जाएं ताकि वे डाक्टर बन कर देहातों में जाकर लोगों की सेवा कर सकें। इसी तरह से वैटरनरी हस्पतालों का भी जितना इंतजाम होना चाहिए उतना नहीं है। जब तक इसका योग्य प्रबंध नहीं होगा तब तक हमारा पशुधन अच्छा नहीं हो सकता और अगर पशुधन अच्छा नहीं होगा तो हमारे बच्चों को दूध दही अच्छा नहीं मिल सकता ओर उनकी सेहत अच्छी नहीं बन सकती। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगी कि जितेन वैटरनरी हस्पताल खोले जाएं उतना ही अच्छा है। उसके बाद एक बात सिंचाई के बारे में मैं कहना चाहती हूं। वैसे तो सरकार ने खेती के लिए पानी देने के लिए हर तरह से कोशिश की है, जैसे मेरा इलाका है वहां नहर का पानी तो है नहीं लेकिन वहां पर बिजली के ट्यूबवैल लगाकर अच्छा कदम उठाया है। गांव गांव और किल्ले किल्ले पर ट्यूबवैल लगे हुए हैं। लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहां पर दो–दो तीन–तीन किल्ले के मालिक किसान हैं और वह अलग अलग टयूबवैल नही लगा सकते। ऐसेस इलाकों का भी सरकार सर्वे कराये ओर वहां पर सरकारी टयूबवैल लगाये। कई जगह तो

लगे भी हुये हैं लेकिन जो इलाके रह गये हैं और जहां लग सकते हैं वहां लगाये जायें और लोगों को पानी दिया जाये। कैथल में कुछ और एरियाज भी ऐसे हैं जहां पर मीठा पानी मिलता है मगर गहरा है। वहां पर डीप बोरिंग कराकर टयूबवैल लगाये जाये। जिसकी जमीन में मीठा पानी निकल आये बेशक बाद में उसेस बोरिंग का खर्च ले लिया जाये लेकिन इस तरह करके लोगों का पानी दिया जाये। अगर इस तरह से पानी का इंतजाम हो जाये तो वह जमीन सोना उगलने वाली है और काफी पैदावार अनाज की हो सकती है। बिजली के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने सारे देश में सबसे बढ़िया काम किया है और गांव गांव में बिजली पहुंचा दी है। कई भाईयों को शिकायत है कि गांव तक जो बिजली पहुंच गई है लेकिन गांव में नही पहुंची है। मैं कहना चाहती हूं कि गांव का आदमी घर में बिजली का लाटू लगाने को इतनी अहमियत नहीं देता जितनी इस बात को देता है कि उसके खेत में टयूबवैल के लिये बिजली मिल जाये और वह मिल गई है। आज किससान कई तरह के छोटे मोटे धन्धे बिजली से कर सकता है और कितने ही काम जो वह शहर में जाकर करने को सोचता था आज गांव में कर सकता है। इसके साथ ही मैं यह जरूर कहना चाहती हूं कि इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है और कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं समझती हूं कि महकमा के ज्यादा फैलने की वजह से स्टाफ ज्यादा है इसलिये कंट्राल कम हो पाता है। शिकायतें बार बार होते हुये भी कई कई दिन बिजली गई रहती है लेकिन ठीक करने के लिये नही आते हैं। इस बारे में मेरा सुझाव है कि

अगर छोटे स्टाफ की कमी है तो उसे बढ़ा दें और बड़ा स्टाफ अगर कम करना पड़े तो कर दें क्योंकि काम का निशाना जो रखा था वह पूरा हो गया है इसलिये अगर बड़ा स्टाफ कम भी पड़ जाये तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन छोटे स्टाफ के बगैर रोज का काम नहीं चलेगा इसलिये उसे बढ़ा दें ताकि लोगों की दिक्कतें दूर हो जायें। खेती–बाड़ी के मामला में जिला करनाल अव्वल नम्बर पर रहा है और रहता है लेकिन वहां और भी तरक्की हो सकती है अगर वहां के किसानों को छोटे छोटे ट्रैक्टर दिये जायें। यह ठीक है कि हरियाणा में लाटरी सिस्टम से काफी ट्रैक्टर लोगों को दिये गये हैं और लोगों को काफी फायदा हुआ है लेकिन अभी तक लोगों की पूरा मांग पूरी नहीं हो पाई है। इस बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर किसानों को छोटे छोटे ट्रैक्टर दिय जायें तो अकेला करनाल जिला सारे हिन्दुतान को अनाज सप्लाई कर सकता है। खाद के बारे में ठीक है कि कमी नहीं है लेकिन इसका भाव बहुत महंगा होता जा रहा है लेकिन अनाज का भाव उसी तरह से है ओर इस बात को किसान बहुत महसूस करते हैं। अगर अनाज भी उसी हिसार से मंहगा हो गया तो गरीब लोग खरीद नहीं सकेंगे और यह बात ठीक नहीं होगी। इसलिये इसका हल यही है कि खाद की कीमत पर कंट्रोल किया जाये ताकि किसानों को नुकसान न हो ओर वे पैदावार ज्यादा से ज्यादा कर सकें। यह बात ठीक है कि शिक्षा के लिहाज से हरियाणा ने काफी तरक्की की है और पिछले दो ढाई साल में बहुत स्कूल अपग्रेड किये गये हैं। मुझे ऐसे ऐसे इलाकों का पता

है जहां पर पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं थी और लोग पढ़ने के लिये तरसते थे लेकिन अब वहां पर मिडल और हाई स्कूल खोल दिये गये हैं। मैं समझती हूं कि अभी भी और स्कूलों की जरूरत है क्योंकि हम जिस भी गांव में जाते हैं वहां लोगों की पहले मांग यही होती है कि मिडल और हाई स्कूल खोले जायें ओर अपग्रेड किये जायें। इस बारें में मैं यह कहना चाहती हूं कि सर्वे करा कर देखा जाये कि कहां कहां कम स्कूल बने हैं ओर उसके बाद जहां ज्यादा बन गये हैं वहां साल दो साल के लिये रोक लगा कर दूसरी जगहों में जहां कमी रहती रही है वहां ज्यादा बना दिये जाये तभी उन पिछड़े इलाकों की तरक्की हो सकती है। इसके अलावा पिछड़े इलाकों में कालेज नहीं हैं। जिला करनाल मे सिवाये कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी के कोई गवर्नमैंट कालेज नही हैं लेकिन रोहतक में एक ही साल में दो तीन कालेज खुल गये। जो पिछड़े इलाके हैं जहां शिक्षा की कमी है वहां अगर गवर्नमैंट कालेज खोले जायें तो ज्यादा लाभ हो सकता है। सरकार ने एक अच्छी बात की है जो हरिजनों के लिये हरिजन कल्याण निगम बनाया है। हरिजन एक ऐसा वर्ग समाज का है जो बहुत पिछड़े रहे हैं। यह ठीक है कि उनके लिये वजीफे भी दिये और किताबों के लिये कर्जे भी बढ़ा दिये हैं लेकिन मैं समझती हूं कि वे लोग इतने गरीब हैं कि कर्जो की बजाये उनके बच्चों को प्राइमरी से लेकर कालेज तक मुफ्त किताबें दी जायें तभी कोई फायदा हो सकेगा। मैं समझती हूं कि यह निगम बनाने में भी काफी समय लगा है लेकिन अब बन गया है और मैं समझती हूं कि हरिजन

और बैकवर्ड क्लासों के लोग अकेले तौर पर या अपनी कोआप्रेटिव सोसायटियां बनाकर काफी फायदा उठा सकते हैं और रोजगार हासिल कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ में उम्मीद करती हूं कि जो सुझाव मैंने दिये है उन पर अमल किया जायेगा।

चौ. प्रभु राम (छछरौली एस.सी.): चेयरमैन साहब सबसे पहले मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इतने थोड़े अर्से में हरियणा को बहुत ऊंचा उठा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह सरकार जो ईमानदार सरकार है अगर इसी तरह चलती रही तो हरियाणा हिन्दुस्तान में सबसे अव्वल नम्बर पर हो जायेगा। अब मैं एक दो बातें अपने इलाका के बारे में कहना चाहता हूं मेरे इलाका में पहले बिजली नहीं थी और लोग बिजली देखने के लिये और यह देखने के लिये कि पंखा कैसे चहता है, रेडियों कैसे चलता है शहरों को जाते थे लेकिन आज मेरे इलाका में घर घर में बिजली जगमगा रही है और यह इस सरकार की मेहरबानी से हुआ है। इसके अलावा कई स्कूल अपग्रेड किये, कई सड़के बनी और एक और नया काम जो किया वह यह है कि जो हरिजन कल्याण स्कीम थी उसके बारे में मेरे इलाका में कोई नहीं जानता था लेकिन आज वहां कई हरिजनों को गांव में मकानों के लिये ग्रांटें दी गई और कई किस्म के कर्जे दिये गए जिनसे पशुपालन के काम और दूसरे जूती बनाने वगैरा की इन्डस्टरीज उनके घरों में चल रही

हैं। इसके लिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं।

मेरे इलाका में नहर जमन गरबी चलती है और उससे मेरे इलाका में कोई आठ नौ गांव सैराब होते हैं। उसके माइनर वन आर से चार पांच गांव को पानी मिलता है। उस माइनर से नागड़ नाला गुजरता है और बरसात के दिनों में बहुत खराबी करता है। बरसात के दिनों में लोग जीरी लगाते हैं। लेकिन वह नाला हर साल माईनर को तोड़ देता है और परिणाम यह होता है कि किसान भाईयों को बहुत नुक्सान होता है। मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि या तो उस नाले पर पुल बना दिया जाए या माईनर 1 आर का पानी 2 आर में डाल दिया जाए तथा उस माईनर को पौंटा रोड़ तक पक्का बना दिया जाए और गवर्नमैंट उसका प्रबन्ध अपने अधिकार में ले ले ताकि लोगों को नुक्सान न हो।

इसके इलावा हमारे इलाके में बैटरमैंट टैक्स लगता है। भाखड़ा नहर से जो जमींदार पानी लेते हैं उन्हीं के ऊपर वाटर लैवी यानी बैटरमैंट टैक्स लगता है। जब वह नहर बनी थी तो किसान भाइयों ने नहर के लिए जमीन मुफ्त दी थी। इस नहर के इलावा इस इलाके में बहुत पुरानी नहर जमन गरबी चलती है। चूंकि लोगों ने नहर के लिए जमीन की कीमत नहीं ली थी इसलिए यहां बैटरमैंट टैक्स नहीं लगना चाहिए। मेरे अपने खास गांव में 1750 एकड़ जमीन हे जिस पर बैटरमैंट टैक्स लगता है लेकिन

पानी सिर्फ साढ़े साल सौ एकड़ पर लगता है। मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि जहां 1000 एकड़ तक जमीन को पानी मिलता है उसकी माईनर का खर्च गवर्नमैंट को देना चाहिए ताकि गरीब किसानों को राहत मिल सके। इस माईनर की जिम्मेवारी महकमा नहर की होनी चाहिए। क्योंकि यहां कुछ जमीन साढ़े सतारह सौ एकड़ है जबकि पानी केवल साढ़े सात सौ एकड़ को लगता है। आबयाना जो सारी जमीन का लिया जाता है वह भी खतम करना चाहिए। पानी कम मिलता है और खर्चा ज्यादा है इसलिए मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि हमें पानी पूरा दिया जाए। सरकार ने एक स्कीम बनाई हुई है कि नहर में ट्यूबवैल्ज लगाकर जमींदारौं को पानी दिया जाएगा। मेरे इलाके से नहर गुजरती है इसलिए इसमें ट्यूबवैल्ज लगाए जाएं ताकि सारी जमीन को पानी दिया जा सके।

इसके इलावा सरकार ने गन्ना मिल लगाने की स्कीम बनाई हुई है। यह स्कीम पानीपत और कैथल वगैरा के लिए बनाई हुई है। मेरे इलाका में गन्ना की पैदावार काफी होती है, इसलिए सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि वहां एक मिल लगा दी जाए ताकि किसानों का गन्ना इस्तेमाल हो सके। चेयरमैन साहब, अम्बाला जिला का नाम हर सैशन में नहीं आता, इसके लिए कोई खास स्कीमें नहीं बनाई जाती जबकि टैक्स देने में यह सबसे आगे है। जबकि टैक्स देने में अम्बाला सबसे आगे है इसलिए डिवैल्पमेंट के कामों में भी यह सब से आगे होना चाहिए।

सड़कौं का जहां तक ताल्लुक है, सड़कों को बनाने में जो पुरानी स्कीमें थी उनके तहत तो सड़कें बनी हैं लेकिन नई स्कीम के तहत नई सड़कें बनाने की स्कीम नहीं आई है। इसलिए मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि जो सड़कें बननी जरूरी हैं उनके लिए कोई स्कीम बनाये और सड़कें बनाई जाएं।

चेयरमैंन साहब, मेरे इलाका में ट्यूबवैल्ज की बहुत कमी है, सड़कों की भी कमी है। इसको बैकवर्ड करार दे दिया जाए। लोगों के मकान कच्चे और फ्स के बने हुए हैं। इस साल मकान गिर जाते हैं और लोगों का लाखों रूपये का नुक्सान होता है। यह नुक्सान जनता का ही नहीं होता बल्कि सरकार का भी होता है क्योंकि जनता का नुक्सान होना सरकार का नुक्सान होना है। इसलिए मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि लोगों को टीन का कोटा दिया जाए ताकि वे अपने मकान रहने लायक बना सकें और गरीब हरिजन, गरीब किसान हर साल होने वाली तबाही से बच सकें।

चेयरमैन साहब, पंचायतों की जमीन पंचायतों के तहत होती थी लेकिन अब गवर्नमैंट पंचायतों से लेकर दूसरे लोगों में तक्सीम कर रही है। इसलिए मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि यह जमीन पंचायतों के पास ही रहनी चाहिए। पंचायतों ने बंजर जमीन को तोड़ा, उसको ठीक किया और गरीब लोगों को काश्त करने के लिए दिया लेकिन अब उन मुजारों को सरकार बेदखल कर रही है और दूसरे लोगों को तक्सीम कर रही है। मैं रिक्वैस्ट

करूंगा कि जमीन पंचायतों के पास ही रहे और मुजारे पहले की तरह ही कामय रहें।

चेयरमैन साहब, जहां तक एजुकेशन का ताल्लुक है, मेरे इलाके में कोई कालेज नहीं है। सिर्फ अम्बाला और जगाधरी में कालेज हैं लेकिन मेरे इलाके में नहीं हैं। बीस बीस पच्चीस पच्चीस मील तक कोई कालेज नहीं है। मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि छछरौली में एक कालेज खोल दिया जाए ताकि लोगों को तालीम की सहूलियत हो और बच्चे आसानी से तालीक हासिल कर सकें।

मेरा इलाका देहाती इलाका है जिसमें पाने के पानी की बहुत कमी है। लोग बरसात का पानी इक्ट्ठा करते हैं और उसको तीन तीन दिन तक छानते हैं तब कहीं पीने के लायक बनाते हैं। इस तरह लोगों को गन्दा पानी पीना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि सबसे पहेले पाने का पानी मुहैया किया जाए। जो डिवैल्पमैंट के काम करने हैं उनमें सबसे पहले पाने के पानी की तरफ ध्यान दिया जाए।

मेरा इलाका दरिया के पास है। एक दरिया जमुना है और एक नहर है। जितने भी गांव इस दरिया के आस पास हैं उनमें बरसात के मौसम में फ्लड आता है और सारे इलाके की तबाही हो जाती है। हर साल नये गांव बसाने पड़ते हैं। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस इलाका में, दरिया जमुना के साथ साथ बांध बना दिया जाए या कोई ऐसा इंतजाम करें

जिससे लोग तबाही से बच सकें। इससे गरीब जनता को फायदा पहुंचेगा, उनके गरीब बच्चे सरकार को दुआयें देंगे। इसके अलावा सोम फतेहगढ़ का पुल बनाया जाए क्योंकि इस पुल में तीन तीन दिन तक पानी बन्द रहता है। नागन नाला के ऊपर भी पुल बनाया जाए। पुलों के लिए मैं सरकार से खास तौर पर रिक्वैस्ट करूंगा कि इनको बनवाया जाए ताकि लोगों को आने जान की सहूलियत हो सके। चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे बोलने का टाईम दिया। मैं सरकार का भी मशकूर हूं जिसने बहुत अच्छे काम किए और उम्मीद रखता हूं कि मेरे इलाका में भी यह और डिवैल्पमैंट के काम करेगी।

Ch. Jai Singh Rathi (Naultha): Mr. Chairman, since 3 P.M., we are having the discussion on the Budget. Much has been said regarding the law and order situation in the State. I have not to add any thing to that because that was a very hollow picture of the law and order situation which has beene explained by the earlier speakers. One thing which attracted me much on which I woiuld like tomake certain comments. After reading through the Budget paragraphs I found that in the concluding paragraph the Finance Minister was carried not by the sentiments of the people but by their political motives and unnecessarily, for the first time-may be in the history of our democracy-none State culd have ever introduced the name of the Prime Minister in the Budget speech. It is a departure from the set principles that the only praise was made of the leadership of the Prime Minister of India. But the Finance Minister could not see what is happening in the State? They had given different slogans just to carry the voters or the people of the State alongwith them with the help of the slogans and I mistake not if I say that this entire Budget which has been

presented, appears to be a slogan only. That is why I would just bring home to the Finance Minister that by these slogans which have been given in this Budget, you are not going to deliver any goods to the people. Not only this, as I feel from the debates earlier and during the Supplementary grants and other things this Government was completely exposed. Their misdeeds were brought here before the House. And atleast 80 per cent of the misdeeds which were told and all the charges which were made on the Goernment, were unreplied. The Government accepted. They have got no answers for it. What I feel today that this Ministry is one whole system of oppression, robbery of the individuals, spoilation of the public, supersession of the whoel system of the Government. It is only in order to vest in the worst natives all the possible powers which can be entrusted or which can be existed in a Government; they are being taken by the Chief Minister. I charge the Chief Minister for all this villainy. And, I further say in this House; in the name of this august House, I charge the Chief Minister for betraying the trust of the House which was reposed in him, when they passed the unanimous resolution. I charge the Chief Minister in the name of the populace of this State for completely suppressing their laws, rules and liberty of the land, and for violation of the justice. I also charge the Chief Minister in the name of the humanity which have met the cruelty, complete outrage and suppression at the hands of the Chief Minister. In a State, where the people and made tools to this extent, that they lose their individual identity; they are not allowed to exercise their right. The Government have never felt that peoples' rights are their duty and the rights of the Government are the duties of the people. They have nto been able to incorporate the spirit among the people that the rights and duties are correlative terms. They expect much from the people; they are giving nothing to the people; not even their rights and still they want that the people should not come forward to say anything against the Government. They hollowness

of their propaganda that they have electrified the State; they are going to construct the entire roads to every village, that is not going to satisfy anybody. The so-called what change in the structure they want to bring, it would not give good fruit or good results, unless or until we raise the moral standard of the people. We shall completely say to the people, not liek that, as I again charge that the brave people of this soil, their character and courage have been dishonoured by the Chief Minister. At the time of the Chandigarh agitation, people showed the good courage; they had the character; they had the feelings.

Mr. Chairman: This is a discussion on the Budget and not on.

Ch. Jai Singh Rathi: Yes, exactly, I can discuss anything on this Budget.

Mr. Chairman: It has nothing to do with the Budget.

Ch. Jai Singh Rathi: I am talking of the people; they are completely connected with this Budget; it is not a Budget for those people who have got that much character and the courage in themselves; they can rise above. The Government is simply giving a slogan. What I say is for the people if they can find any place or anything which can raise their moral standard, which can bring in them the confidence in the Government. By this they cannot getthe confidence of the people. They cannot repose confidence in this Government because of the reasons that whatever the progress they are saying they have made, that is not the real progress. I remember the occasion when they talk that there is hunger, there is no food, there is provety, I am remainded of one of the greatest sayings. Once, Great Churchill and Mr. Bernarad Shaw were setting together. Bernarad Shaw, as you know, Mr. Chairman, was a very thin and lean man, a very skinny man, and Churchill being very healthy, fatty and well-built. Churchill said to Shaw “Shaw, it is an

insulting one if somebody sees you in other country, he would say that there is a famine in England." So, Mr. Churchill said to Shaw" If somebody see you outside England, he would say that there is a famine in England." and Shaw replied and retorted "If somebody sees you outside, he will at once say that you are the cause of it". Exactly, this is the state in Haryana. If you look at the people, everybody in this world can at once say by looking at the faces and the bodies and the manners in which these Ministers are living, they are the cause of poverty in this State. They are getting huge amount, as salaries, as pay, as T.A. and D.A., and what not everything. They are living in palatial buildings and they are simply living for the people; that they will construct roads; that is all. How are you going to improve the lot of the people? You are not going to remove the poverty like that. You are not going to get any source of income to anybody. You are not making any efforts to bring more industries where labour could go. You are not bringing any shop or anything of the sort where the people can settle; fell completely safe; rather this Government has also announced like the Prime Minister that we are going to do something. We are going to remove this particular thing and get it the right of the property. I may quote here that one of the greatest democrat and in democratic history also, much has been said what is the democracy, what the Government can do and what the Government should so. There are certain principles in life also, So, I quote here that-I would like to have the attention of the Finance Minister. She would bear me for sometime when I read. I quote for her "You cannot being about prosperity by discourageing thrift", but the Government does not believe it. By discouraging thrift further, you canot strengthen the weak by weakening the strong. But, they say they can do it. This is a set principle that if you want to make weaker a stronger, do not make the stronger weaker one, but rather who is weaker, you should make him strong. That should be the principle, but they are saying they would weaken the stronger and then improve the lot of

the weaker. How can it happen? But, they say they would do it. The third thing is that you cannot establish sound security on borrowed money, but they are saying that they would borrow and make the security. How you can do it? A borrowed money remains a borrowed money. By this borrowing habit, by giving loans to the Harijans and other poor classes, they have made them completely slaves. They are slaves of the Government. Today, I remember, in some discussion earlier, it came that they are distributing more loans to the Harijans. What woiuld happen? They have also started collecting the old taccavies, and so on and so forth. Either they should vote or they would be sent to the jails. This is one instrument which they want to keep in their hands; that you can only keep the poor, under your thumb by giving them loans. And, they are also accepting loans from other countries. Again, I quote for the Finance Minister that you cannot help the poor by destroying the rich; you are not going to help the poor if you destroy the rich. You make the poor rich, that is something logical. One can understand that, but not this that you are going to make the rich a poor and then you can help the poor. Furthermore, I would quote that this is all in connection with the Budget I am saying. These things have got no place in this Budget. Madam Finance Minister, you cannot build character and courage by taking away the man's initiative and independence. You want to take everything from the people. You do not want to let them feel that they are independent. I would request you, you should create such a circumstance and such an atmosphere in the State, where the people should have the confidence and courage, where they can walk errect, look everybody in the face. Does not matter, if they ae jobless, homeless, friendless. Even they should feel that they have self-confidence and they have belief in themselves, but you are not allowing the people to rise to that occasion, where they can feel that they are confident in themselves. Next I would just quote that

–

"You cannot help a man permanently by doing for them what they can do for themselves."

Everytime they are saying, people they can do much but they want to give rather spoon-feeling to them so that they shuld not mature at all. They want to keep them completely babies. They do not want to teach them the principles of demorcracy. They are talking the peopel away. They are not educating the people in the right earnest, right sense, by saying that they are going to open the schools. But what is the standard in the schools? They say, "We are going to open the hospitals". But what is the standard of the hospitals? If you just look at your budgets-last budget and this budget:- How much funds you have allottted for giving medicines in the hospitals? These are not medicines available for a poor man. A man like me, who is a privileged person he can get medicines in the hospitals? There are no medicines available for a poor man. A man like me, who is a privileged person he can get medicines from the hospitals and not the poor man, who has got no privilege at all. These hospitals should be for the poor and these schools should be for the poor, a persons who cannnot affored. By saying all this that we are going to construct roads and Harijans and poor classes can go and work there as labourers, you are only creating labourers as the Britishers when they were ruling were only producing clerks. You are only producing labourers. You are not going to produce a better class of the society and you are only managing and doing the things with this interest that we should always make every body a labourer and that is the communistic theory followed by your Prime Minister who is turning as a communist now and from this Budget when she was praised I was thinking that this budget is not a budget of the people of Haryana but is a budget which has got the influence of a foreign power. (At this stage Principal Ishwar Singh Chairman, saw the time).

With these remarks it appears my speech time is fact reaching and I don't know what had been decided in may absence whether or not any time limit was fixed? I would conclude that this sort of budget is not a budget of the people. I won't improve their lot; it won't improve law and order situation; it won't improve any industrial impact; it won't improve anywhere, on the co-operative sector or cooperative societies; nothing would be improved by this only budget by saying that we would borrow and borrow and put the State in such an affair where nobody would be able to take it out anywhere. Thank you, Mr. Chairman.

(Thumping from the Opposition Benches)

चौ. हरि सिंह सैनी (हांसी): चेयरमैन साहब, आपकी विसातत से मैं बजट पर बोलने जा रहा हूं। हरियाणा की वित्तमंत्री महोदया 71–72 का जो बगैर टैक्स के बजट लायी हैं और करोड़ों रूपया पिछले सालों की अपेक्षा ज्यादा रखकर लोगों को जो राहत दी है उसके लिए मैं वित्तमंत्री महोदया को बधाई देता हूं। चेयरमैन साहब, जब से यह मौजूदा सरकार वजूद में आयी है तभी से हरियाणा निवासियों को एक आशा बन्धी है और उसका भी एक कारण है। वह कारण यह है कि मौजूदा सरकार के चीफ मिनिस्टर ने इतने तरक्की के काम लिये हैं कि हरियाणा की जनता उनकी सदा ऋणी रहेगी। उन्होंने हरियाणा की तरक्की करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे याद है कि सन् 1967 में जब मैं एम. एल.ए. बनकर आया और मैंने अपने खेत के ट्यूबवैल के लिए बिजली के कनैक्शन के लिए प्रार्थना पत्र दिया तो उस वक्त के

बिजली तथा पानी के मंत्री ने कहा कि चौ. साहब कनैक्शन कहां से दें अभी तो तार और खम्भे भी नहीं हैं? परन्तु आज की मौजूदा सरकार ने तीस करोड़ रूपये से सात हतार देहातों में बिजली दे दी जबकि संयुक्त दल की सरकार आठ महीने में एक भी ट्यूबवैल को कनैक्शन नहीं दे सकी।

(इस समय सभापतियों की सूची के एक सदस्य चौधरी कटारा सिंह छौकर पदासीन हुए)

श्री सत्य नारायण सिंगोल: तीस करोड़ का कर्जा बकाया है।

चौ. हरि सिंह सैनी: काम करेंगे तो कर्जा होगा ही। मैं अर्ज कर रहा था कि जहां इस बजट में करोड़ों रूपया ज्यादा है वहां मेरी बहिन ओमप्रभा जी ने प्रोफेशनल टैक्स जो एक बीमारी लगा रखी थी उसको खतम कर दिया। संयुक्त दल की सरकार तो सन् 67 में आबयाना को भी डेढ़ गुना करके जा रही थी। वह तो भला हो मनीराम गुदारा का कि वे अड़ गये और कहा कि अगर आबयाना ज्यादा किया तो मैं मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दूंगा। दूसरे सबसे अच्छा काम इस सरकार ने यह किया है कि बिक्री टैक्स की छूट दी है। हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि लोगों को आशा बन्धी हुई है कि और भी अधिक तरक्की हरियाणा में होगी। अभी हमारे मोहतरिम बुजुर्ग श्री रामशरण मित्तल जी ने बताया था कि सन् 67 में सरकारी मुलाजमों के लिए

सात महीने की तन्खाह भी देने को नहीं थी लेकिन आज की मौजूदा सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा खर्च करो। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। चेयरमैन साहब हरिजन कल्याण बोर्ड जो बनाया है यह बड़ा अच्छा है। इसके लिए समाज कल्याण मंत्री बधाई के पात्र हैं मगर हरिजन और बैकवर्ड जो बहुत पिछड़े हुए वर्ग हैं इस प्रदेश के उनको जो राहत दी है उसके लिए तो मैं सरकार को बधाई देता हूं मगर वह मेरी जो अपनी आत्मा कहती है उससे कुछ कम है। यह वर्ग बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग है। इस विषय में वित्तमंत्री महोदया को मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के लिए मौजूदा सरकार कुछ और अधिक पैसा दे। दूसरे मैं किसानों के लिए भी यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो किसानी औजारों पर सेल्ज टैक्स लिया जाता है वह मेरे विचार के अनुसार नहीं लिया जाना चाहिए।

मैं पहले कह ही चुका हूं कि सरकार बहुत जोरों से काम कर रही है और सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसने हांसी सब–डिविजन में काफी काम किया है परन्तु मेरे उस सब–डिविजन में दो तरह की समस्यायें है एक तो वहां बाढ़ की समस्या है दूसरे वहां खुश्की की समस्या है। बाढ़ की समस्याके विषय में मैं सिचाई तथा बिजली मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि पिछले साल जो यह मौजूदा साल चल रहा है, वैस्टर्न जमुना कैनाल ऊंची करने के लिये एक करोड़ रूपया दिया गया था मगर हांसी और हिसार में मेजर और पटवाड़ मेजर पर एक पैसा नहीं

लगा। हिसार मेजर की ऐसी बुरी हालत है कि उसे रजवाहा या नाला भी नहीं कह सकते और मैं समझता हूं कि फिरोजशाह तुगलक ने जब यह नहर बनवाई होगी उसी वक्त का यह पैसा लगा होगा। मैं अपनी सरकार से, सिंचाई मंत्री से तथा वित्तमंत्री साहिबा ने यह दरखास्त करूंगा कि हिसार मेजर और पटवाड़ मेजर को ऊंचा करवा दिया जाये क्योंकि वहां फल्ड भी आते हैं। जब फ्लड आते हैं तो वह नाला जो बना है, फ्लड के कारण उसका पानी कट जाता है और वह पानी गांव को डुबो देता है। इसलिये जरूरी है कि उस नहर के किरानों को ऊंचा कर दिया जाये। मैं नहरों के लिये वित्तमंत्री साहिबा से और सिंचाई मंत्री जी से फिर दोबारा दरखास्त करूंगा कि उनके विषय में ध्यान दें।

हमारे बुजुर्ग इन्डस्ट्री मिनिस्टर यहां तशरीफ फरमान नहीं हैं। मेरी बहन जी जरूर इमदाद करेंगी। हांसी सब–डीविजन की आबादी 4½ लाख है। हर सब–डिविजन में इन्डस्ट्रीयल एस्टेट है मगर हांसी के अन्दर नहीं है। मैं आशा करता हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि वह एस्टेट हांसी में भी बनेगा। बहन जी, हांसी का कस्ब और उसके चारों तरफ के गांव बहुत जोर से यह मांग करते है कि काफी बड़े शहरों में लोकल बसें चलती हैं मगर हमारे इलाके के अन्दर लोकल बसें नहीं हैं। मैं आपसे यह दरखास्त करूंगा कि लोकल बसें हांसी और उसके आठ मील के इलाके के लिये चलाएं।

आपसे जो माडल विलेज की स्कीम रखी है वह बड़ी अच्छी स्कीम है। अपोजीशन बैंचों के भाई कहते हैं कि क्या किया है? इससे लोगों का राहत मिलेगी, सुख मिलेगा, जब यह स्कीम चालू हो जायेगी। मुझे सरकार से पूरी आशा है कि यह स्कीम बहुत जोरों से चालू होगी और जिस होशियारी से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, मुझे ऐसी आशा है कि यहां गावं और शहरों मैं कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं आपका ध्यान हौसपिटल्ज की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। हांसी का कस्बा 50 हजार लोगों का है और आसपास देहात भी हैं, मगर वहां के हस्पताल में बिस्तरों का इंतजाम नहीं है। अभी मौजूदा सरकार ने कुछ पग उठाया है लेकिन उस हस्पताल का पाता नहीं वह दो सौ साल का है पता नहीं देढ सौ साल का है क्योंकि दो सौ साल पुराना हमारे यहां एक रैस्ट हाऊस है जोकि अंग्रेजों ने बनवाया था। वह 1843 में बना था। अब हमारी सरकार इतनी देर बाद गौर कर रही है। ऐसे ही मेरे ख्याल में वह हस्पताल भी अंग्रेजों ने उस वक्त अपने लिये बनाया होगा। मैं तो आपसे दरखास्त करूंगा कि जहां आपने उसको प्राविसियालाइज्ड किया है वहां उसको जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा बनाने की कृपा करें ताकि वहां के लोग महसूस करें कि मौजूदा सरकार हमें भी अच्छी तरह से राहत दे रही है। बहन जी, बस स्टैन्ड के लिये मैंने बार बार इस सदन में अर्ज की है। आज भी मैंने यह कहा था कि हमारा बस स्टैन्ड भी दीगर सब–डिविजनों के बस–स्टैन्डों की तरह बनना चाहिये। मेरी पुरजोर प्रार्थना है कि वह बस–स्टैंड जल्द से जल्द बनना चाहिए।

सीसायें गांव इस हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। मेरे ख्याल में अगर मैं भूल नहीं करता तो उसका हस्पताल बहुत घटिया और 50–60 साल पुराना है। बिल्कुल छोटा सा उस वक्त के मुताबिक अंग्रेज सरकार ने बनाया होगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि वह 10–12 हजार की आबादी का गांव है इसलिए उसके लिये नया हस्पताल बनना चाहिये। (विघ्न) मैं और भी गलती पर था। चौ. सरूप सिंह जी ने मुझे बताया है कि उस गांव की आबादी अब 14 हजार हो गई है। मेरी प्रार्थना है कि उस गांव का हस्पताल आजादी के मुताबिक बड़ा बनाया जाए। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)। उपाध्यक्ष महोदया, हांसी के अन्दर हेदात और शहर के मवेशियों का एक हस्पताल है उसकी ईटें भी सेम ने खा ली है और कर्मचारी बाहर मैदान में बैठते हैं। उस हस्पताल को गवर्नमैंट जिस भी शक्त में हो सके बनाने की कृपा करें ताकि हांसी के मवेशियों को भी राहत मिले जैसे आदमियों को राहत मिली है। (विघ्न) अन्त में मैं उपाध्यक्ष महोदया आपका धन्यवाद करता हूं और बहन ओमप्रभा जी से पुरजोर प्रार्थना करता हूं कि वे हमारी बातों पर अवश्य ध्यान दें और खासतौर पर मैं सिंचाई मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे हिसार में पटवाड़ मेजर को ऊंचा करें। इन शब्दों के साथ डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूं।

सिंचाई एंव विद्युत मंत्री (श्री रामधारी गौड़): करवा देंगे।

6.00 p.m.

श्री कंवर सिंह दहिया (रोहट एस.सी.): डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज हरियाणा स्टेट के बजट पर जो बहस हो रही है, उस पर मैं बोलने जा रहा हूं। इस बात में कोई शक नहीं है कि बजट बहुत अच्छा है और हरियाणा सरकार पिछले ढ़ाई वर्षों से जिस तेजी से काम कर रही है, वह सबके नोटिस में है। लेकिन इस साल के बजट को देखने से और ज्यादा अनुमान लगाया जा सकता है कि स्टेट के अन्दर और भी ज्यादा काम होंगे। जो थोड़ी कमियां मैं महसूस करता हूं, वह इस तरह से है :–

पहले मैं एग्रीकल्चर के बारे में अर्ज करूंगा। एग्रीकल्चर के बारे में वैसे तो सरकार का काफी ध्यान जमीदारों की तरफ है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये भी सरकार का काफभ ध्यान है लेकिन मैं दिन प्रतिदिन अपने हल्के में अपने वाली कठिनाईयां आपको बतलाऊंगा। जैसे कि मेरे जमींदार भाई मुझे बतलाते हैं, एक कठिनाई उनकी ट्रैक्टरों की है। कोआप्रेटिव बैंकों से जो जमीदारों को ट्रैक्टर लेने के लिये कर्जा दिया जा रहा है, अव्वल तो वह बहुत लेट करके दिया जाता है, अगर टाईम पर दिया भी जाता है तो उस पर एक पाबन्दी होती है कि जमींदार खुद ट्रैक्टर चलाना जानता हो। मैं चाहता हूं कि या तो पैसा उसको जिस टाईम उसका लोन सैंक्शन हो, कैश दे दिया जाये या फिर उसको ट्रैक्टर तलाश करके दिया जाये। यह पाबन्दी नहीं रखनी चाहिए कि वह किस तरहसे ढूंढ कर ट्रैक्टर ले। इस बात

का स्टेट की तरफ से इंतजाम होना चाहिए कि जिस वक्त जमींदार को ट्रैक्टर की जरूरत हो, उसी टाईम इसको ट्रैक्टर मुहैयया हो जाये। दूसरी कठिनाई हमारे यहां खाद की है। खाद के लिये भी मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से खाद की प्रोक्योरमैंट होनी चाहिए कि हर ब्लाक में हर जमींदार का रकबा नोट होना चाहिए और दफ्तर वालों को पता होना चाहिए कि किस जमींदार को कितनी ख्वााद की जरूरत है, उसके हिसाब से उन्हें खाद की डिस्ट्रिब्यूशन हो जानी चाहिए ताकि उनको जगह–जगह भागना न पड़े ओर उन्हें खाद आसानी से मिल सके। इसके आगे पशु–पालन के धन्धे के बारे में मैं आपको उनकी कटिनाई बताता हूं। हमारे लोग खेतीबाड़ी के साथ–साथ पशु–पालन का धन्धा भी करते हैं। आजकल पशुधन इतना महंगा हो गया है कि एक–एक भैंस दो–दो हजार की होती है। जैसे कि मनुष्य के लिये चिकित्ससा और दवाई की बहुत जरूरत है, ऐसे ही पशुओं के लिये भी चिकिस्सालयों की बहुत जरूरत है। मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि कम से कम 2 मील के एरिया या हर गांव में एक वैटनरी हास्पिटल जरूर होना चाहिए। मेरे हल्के में एक भटगांव बहुत बड़ा गांव है। उस गांव की आबादी 10 हजार से भी ऊपर है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां एक भी वैटनरी हास्पिटल नहीं है। एक गांव मेरे हल्के में खरखौदा भी है। उसमें आये साल पशुओं का मेला लगता है और उससे सरकार को लाखों रूपये की आमदनी होती है लेकिन वहां भी अब तक कोई पशुओं का हस्पताल नहीं है। मैं आपके द्वारा सरकार से

प्रार्थना करूंगा कि ऐसे गावों में तो खास तौर पर सारा ध्यान देकर जल्दी से जल्दी अस्पताल बनायें ताकि गांवों मैं रहने वाले लोगों या जमीदारों के पशुओं का नुक्सान न हो। वहां पर दो–दो हमार रूपये के कम से कम 300 पशु मेले में आये थे। उनमें से कुछ की मृत्यु हो गयी। वह भी केवल इसलिये कि उनके लिये दवाई का प्रबन्ध नहीं हो सका। इसलिये मैं चाहूंगा कि आपको इस तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए। बिजली या सड़कें बनाने का सरकार जो काम कर रही है, मैं चाहूंगा कि बेशक उसे बाद में ले लिया जाय लेकिन वैटरनरी हास्पिटल आपको सबसे पहले बनाने चाहिएं।

अब मैं सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह बात ठीक है कि सड़कों की भी अपनी महत्ता है। सड़कें गांवों से मार्किटों या मण्डियों को मिलती हैं। यह भी एक जरूरी चीज हैं। इसके साथ ही साथ जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सड़कों पर जो मजदूर काम करते हैं, उसकी तरफ भी आप देखिए। वे भी आखिर हमारी स्टेट के नागरिक हैं। ठीक है, वे मजदूर हैं और मेहनत करके रोजी कमाते है। मगर आपने उनकी दिहाती औरतों के लिये पौने तीन रूपये और आदमियों के लिये 3 रूपये 40 पैसे रखी हुई है। आप उनको इस युग में इतने थोड़े पैसों से बहकाना चाहते हैं, ऐसा हमेशा नहीं हो सकेगा। वह बेचारे सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मिट्टी ढोते हैं। बड़े दु:ख से कहना पड़ता है कि आज के युग में भी उनकी दिहाड़ी सिर्फ पौने तीन

और 3 रूपये 40 पैसे ही है। इस कमाई से वह अपना घर नहीं बना सकते, बच्चों को रोटी, कपड़ या शिक्षा कुछ भी नहीं दे सकते और यह कभी सपना भी नही ले सकते कि वह कोई नई चीज भी ले सकेंगे। गवर्नमैंट ने इंडस्ट्रीज के लिये तो मिनिमम वेजिज एक्ट बनाया हुआ है लेकिन इस ओर गवर्नमैंट का ध्यान नहीं है। इनकी निगाह तो मेरे ख्याल से फैक्ट्रियों की तरफ ज्यादा हैं मैं इनसे यह प्रार्थना करूंगा कि यह मिनिमम वेजिज एक्ट इन मजदूरों के लिये भी लागू करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि जैसे बंगाल में क्रांति आयी है, हरियाणा में भी जरूर वैसी ही क्रांति आयेगी और मैं भी उसमें शामिल हूंगा।

एजुकेशन के सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत से स्कूल अपग्रेउ किये हैं। सड़के बनाने के साथ ही साथ गवर्नमैंट के पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमैंट ने स्कूलों में साइस रूम बनाने का आदेश दिया है। मैंने उन स्कूलों की लिस्ट दफतर में जाकर देखी थी जिनमें से साईस रूम बनाये जाने है। मेरे हल्के में मेरे ख्याल से पांच–छः हाई स्कूल है। एक तो भदाना में है, एक नाहरी में है, एक खरखौदा में है और एक भटगांव में हैं .....। परन्तु उस लिस्ट में मेरे हल्के का एक भी स्कूल शामिल नहीं है। मैं मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि वह मेरे हल्के के हाई स्कूलों को भी उस लिस्ट में इन्कलयूड करवा दें ताकि वहां पर भी साईस रूप बन सकैं और बच्चे अच्छी तालीम पा सकें। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी

सड़कों का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं जिन पर कि मेरे हल्के के विद्यार्थियों ने अर्थ–वर्क खुद अपने सिरों पर मिट्टी उठा–उठा कर किया हुआ है। मेरे हल्के में एक ढाई तीन मील का टुकडा है जिस पर कि विद्यार्थियों ने काम यिका हुआ है मगर उस पर अभी तक भी काम शुरू नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि नयी सड़कों पर काम शुरू करने के बजाय जहां पर विद्यार्थियों ने खुद काम किया हो, उन सड़कों पर कमा सबसे पहले शुरू होना चाहिए। कुण्डल–गढ़ी की जो सड़क है, उसमें आधा मील का टुकडा रह रहा है। वहां पर अर्थवर्क हुआ पड़ा है। दूसरी सड़कों पर काम होता चला जा रहा है लेकिन अब तक भी उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। मैं पी.डब्ल्यू.डी. के मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि इस बात की तरफ जल्दी ध्यान दें। इसके अलावा एक आधे मील की और सड़क है। वह सड़क खरखौछा से गोपालपुर को जाती है। इसके बीच में एक नहर आ जाने से वह सड़क रूक गयी है। वैसे तो बाकी की सड़क बन गयी है, लेकिन वह आधे मील का हिस्सा अधूरा पड़ा है। इसकी तरफ भी मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जल्दी ध्यान दिया जाये और इस सड़क के ऊपर जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया जाये। जहां तक सड़कों की प्लानिंग का ताल्लुक है, मैं कहूंगा कि वह बहुत अच्छी बनायी जाती है। सोनीपत से खरखौदा के लिये रोहतक रोड़ से कबाडीपुर तक एक सड़क जाती है। लोगों को खेतों में आने जाने के लिये बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आमदोरफ्त का साधनन बन्द हुआ पड़ा है। लोगों को कपड़े उतार–उतार कर उस ड्रेन को पार

करना पड़ता है। इसके दोनो तरफ सड़कें है लेकिन उनके बीच में ड्रेन न. 8 पड़ती है। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर एक पुल की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार और पुलों की तरह इस पुल की तरफ भी खासतौर पर ध्यान दे ताकि लोगों को आमदोरफ्त तथा खेतों में आने जाने के लिये सुविधा मिल सके। पानी ही हमारे यहां बडी सकेयरसिटी है। मेरे हल्के के भटगांव में और उसके आस–पास के इलाके में पहले मेरे ध्यान से 52 मोघे हुआ करते थे लेकिन आज वहां पर 2 मोघे भी नहीं रह गये है। पानी की हमारे यहां बहुत ही कमी है। वहां पर टयूबवैल भी नाकामयाब रहे हैं क्योंकि वहां पर खारा पानी निकलता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां पर टयूबवैल कामयाब हो, वहां पर नहर का पानी नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे इलाकों का पानी बन्द करके उन इलाकों का नहरो का पानी देना चाहिए जहां पर कि टयूबवैल कामयाब न हो सके हो। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे इलाके में आपको पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इस बार बरसात भी नहीं हुई है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसे इलाकों को खासतौर पर पानी देने का ख्याल रखें जहां पर कि पानी नहीं मिलता।

अब मैं ट्रांसपोर्ट की बाबत अर्ज करूंगां सपोर्ट का नेशनेलाइजेशन भी हो चुका है।

उपाध्यक्षा: आप कितनी देर और बोलना चाहेंगे क्योंकि साढ़े छः बजे हाउस एडजर्न होना है और इससे पहले श्री

हरकिशन लाल जी को भी बोलना है। अगर आप पांच मिनट में खतम कर दें तो अच्छा रहेगा।

श्री कवंर सिंह दहियाः हमारे यहां दो–तीन बसों की आवश्यकता है। एक बस खरखोदा से देहली रूट पर चलाई जाए, दूसरी खरखोदा से लामपुर बोर्डर जो नरेला की तरफ है और तीसरे सोनीपत से भटगांव तक। इन तीनों रूटों पर बसों का इंतजाम होना चाहिये। चाहे सरकार अपनी बसें चलाये या प्राईवेट बसों का इंतजाम करे।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं हरिजन वैलफेयर की तरफ आता हूं। हरिजन वैलफेयर की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है लेकिन अब समय को देखते हुए इस तरफ और ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले बजट में 6 रूपये से 8 रूपये वजीफा कर दिया था लेकिन इस मंगगाई में 8 रूपयें की क्या कीमत है। नवी क्लास और दसवीं कलस में पढने वालों के लिये कम से कम बीस रूपया वजीफा मिलना चाहिये। गांवों मैं ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो कि कपड़े तक नहीं पहन सकते। गवर्नमैंट इनको अपनी निधि समझती है। फीस की माफी के साथ–साथ उनको कपड़े की भी रियायत मिलनी चाहिये। हरिजनों को जो लोन मिलता है वह दो सौ–चार सौ रूपया होता है। इन लोन से सम्बन्ध में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कोई भी लोन पांच हजार से कम न हो। चाहे कोई इस पैसे से धंधा चलाए या पशु पाले। जो तीन सौ–चार सौ

रूपया का लोन आजकल दिया जाता है उससे कोई धन्धा कैसे चल सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहिब हरिजनों को मकान बनाने के लिये 900 रूपये का लोन दिया जाता है। इस पैसे से तो एक छोटी सी कोठरी भी नहीं डाली जा सकती है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस रकम को बढ़ाकर दो हजार रूपये कर दिया जाये जिससे कम से कम रहने के लिये एक छोटा सा मकान तो बन सके।

इसके साथ साथ कई जगहों पर हरिजन आठ–दस साल से टेनेंट बैठे हुए हैं लेकिन अब उन्हें यह डर है कि वहां से उन्हें हटा दिया जायेगा। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो हरिजन कम से कम सात साल से बैठे हैं उनको सरकार 50 प्रतिशत लोन दे और बाकी 50 प्रतिशत टेनैंट खुद दे और उनको मालिक बना देना चाहिए।

इसके साथ–साथ प्लाटों के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले कंसौलिडेशन में हरिजनों को पांच बिसवा के प्लाट रिहायशी मकान बनाने के लिये दिये थे लेकिन वह स्कीम कागजों तक ही बनी रही है उसको अमल में लाना चाहिये। उनका बटवारा या निशानदेही इस सरकार को जल्दी ही करनी चाहिये।

थोड़ा सा रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में मैं कहना चाहता हूं। पिछले साल भी यह बात कही गई थी और इस पर

कैबिनेट का फैसला भी हो चुका है लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पता नही इस पर अमल कब से लागू होगा। दूसरी प्रार्थना यह है कि हरिजनों के लिये जो बीस प्रतिशत का कोटा नौकरियों में रिजर्व है उसको अगले 6 महीने के अन्दर पूरा करने की कृपा करें ताकि जो हरिजनों के अन्दर बेकारी बढ़ रही है और हरिजनों के पढ़े लिखे लड़के बेकार फिर रहे हैं उनको कुछ काम मिल सके। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर महोदया मैं फ्री कनकैशन के बारे में बताना चाहता हूं। सरकार ने फैसला किया था कि जो हरिजन विद्यार्थी फेल हो गये हैं उनकी एक साल तक फीस मुआफ रहेगी। (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) लेकिन आजतक वह आर्डर स्कूलों में नहीं पहुंचे हैं। इस कारण बेचारे गरीब हरिजन बच्चे अपनी फीस दे रहे हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ये आर्डर्ज जल्दी से जल्दी हर स्कूल में भिजवाएं जायें और जो बच्चे अब तक फीस दे रहे हैं उनको फीस रिटर्न करने के भी आर्डर्ज भेजे जायें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पब्लिक हैल्थ और ड्रेनेज के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। शहरों में नालियां बनाने के लिये ग्रांट दी जाती है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जिन गांवों की आबादी पांच–छः हजार है वहां नालियां बनाने के लिये ग्रांट दी जाए। मेरे इलाके में कुन्डल, रामपुर, झिजोली, पीपली से सैदपुर तक ड्रेन जाती है और बरसात के दिनों में इनसे काफी नुक्सान होता है। इनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

एक बात हैल्थ महकमें के बारे में कहना चाहता हूं। हैल्थ के बारे में जहां शहरों में इतने बड़े–बडे अस्पताल बनाये जाते हैं वहां मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो गांव आठ–दस हजार आबादी के है वहां पर एक अच्छा अस्पताल जरूर बनाया जाए। मेरी कंस्टिच्यूंएसी में कई गांव है जैसे भटगांव जिसकी आबादी 10 हजार है, नारी गावं जिसकी आबादी आठ हजार है, एक फरमाना गांव है जिसकी आबादी भी आठ–दस हजार है, इन गांवों में अच्छे हस्पताल होने चाहिए।

स्पीकर साहब इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण खतम करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उनकी तरफ ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष: हरकिशन लाल जी आप कितना टाईप लेंगे?

चौ. हरकिशन लाल कम्बोज: मैं तो पन्द्रह मिनट लेना चाहता हूं बाकि जितना आप देना चाहें वह आपकी मर्जी है।

श्री अध्यक्ष: आप दस मिनट बोल लें।

VARIATION IN THE ALLOCATION OF TIME ORDER.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Mr. Speaker, the Government intends to move an official resolution which may also be included in the items approved by the Business Advisory Committee for the second sitting of the Assembly on the 16th February, 1971, and the items of business approved by the

Business Advisory Committee for that sitting may be varied accordingly. Under Rule 39 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I notify to the House that there is a general agreement for such variation and accordingly the item 'Official Resolution' may also be included in the list of buisness for the second sittin of the Assembly on 16th February, 1971 after the item 'Legislative Business'.

Mr. Speaker: It is the sense of the House to such variation in the allocation of Time Order?

Voices: Yes, yes.

Mr. Speaker: The allocation of Time Order, as amended, will be enforced accordingly.

The hon. Member can now speak till the hour of interruption.

GENERAL DISCUSSION OF THE BUDGET FOR THE YEAR 1971-72 (RESUMPTION)

चौ. हरकिशन लाल कम्बोज (रोड़ी): अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया है मैं किन लफ्जों में उसकी तारीफ बयान करूं? जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में कुछ कहने की बात ही नहीं है कस्तूरी में अपने आप ही खुशबू आती है उसके लिये किसी को कहने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं अर्ज कर दूं कि बजट निहायत अच्छा है, तरक्की पसंदाना है। मुखालिफ फरीक की तरफ से तो हमेशा नुक्ताचीनी अच्छी बातों की भी होती रहती है ओर यह हम काफी अर्से से देखते आ रहे हैं। इसमें कोई घबराते की बात नहीं है,

इन्होंने ऐनक ही ऐसी पहन रखी है। इनको सब कुछ टेढ़ा ही नजर आता है जैसे यरकान के मरीज को दूसरे लोग भी पीले नजर आते हैं। एक साल में तीन हजार किलोमीटर सड़कें बनाने का बजट में प्रबन्ध किया गया है और करोड़ों रूपया आबपाशी के जरीये ढूंढने पर लगाये जा रहे हैं और हर तरह से हरियाणा को आगे ले जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। इससे अच्छा बजट जो आजतक मैंने देखा नहीं। हमारी अपनी तरफ से भी कुछ मैंबर साहिबान ने पता नहीं जाती बिना पर या किसी और नाराजगी की बिना पर नुक्ताचीनी की है। अध्यक्ष महोदय मुझे एक शेयर याद आ गया है:–

''बेगानगिये दिन के अफसाने की ब्या कहिये

अपने न हुए अपने बेगाने को क्या कहिये।''

लेकिन अध्यक्ष महोदय, सदाकत जो है वह छिप नहीं सकती। इस बारे में मुझे एक कहानी याद आ गई। एक दफा एक पति देव जी ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं कल तुमको पीटूंगा तुम अपना संभाला कर लेना, तो उसकी पत्नी ने कहा कि बिला वजह ही पीटोगे या किसी बहाने से पीटोगे। फिर उसने जवाब दिया कि किसी कसूर से पीटूंगा। जब पति देव बाहर चले गये तो पत्नी ने पीछे से सब चीज ठीक कर दी। पति देव के दफतर से आने से पहले पहले चाय का इंतजाम भी कर दिया और साथ ही

शर्दाई भी बना कर रख ली कि कहीं पतिदेव इस बहाने पर ही न मारना शुरू कर दें, पानी ठंडा भी रख दिया और गर्म करके भी रख दिया। चुंनाचे जब वह घर पर आया तो उसको सब कुछ ठीक ठाक नजर आया और शाम तक कोई बहाना न मिल सका। लेकिन शाम को जब पत्नी आटा गूदने लगी तो कहने लगा कि सुसरी आटा गूंदती क्यों हिलती है, बस उसी वक्त बैंत पकड़ कर दो चार ठोक दिये। तो अध्यक्ष महोदय इनकी भी वैसी ही बात है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यह कहते हैं कि आटा गूंदती हिलती क्यों हो। खैर मैं ज्यादा टाईम अब इधर नहीं लगाता। बजट निहायत अच्छा है इसलिये इसकी जितनी भी तारीफ की जाये उतनी ही थोड़ी है। हमारे खजाना मंत्री ने और सरकारी कर्मचारियों ने बहुत मेंहनत के साथ इतना अच्छा बजट बनाया है। लेकिन एक दो बातों के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो इन्होंने काफी अर्सा पहले यह वायदा किया था कि हरियाणा में शराब बन्द कर दी जायेगी लेकिन उस वायदे को सरकार ने भुला रखा है। मैं मुख्यमंत्री साहब और वित्तमंत्री साहिब से रिक्वैस्ट करूंगा कि वह वायदा गुजर रहा है शराब को स्टेट से जल्दी बन्द किया जाये।

हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लिये वैसे प्रोविजन तो काफी किया गया है लेकिन जिस ढंग से हम उनकी मदद करते हैं उस तरीके से मसला हल होने वाला नहीं है। इस पर वार बेसिज पर सोच विचार करके ध्यान देना चाहिये। चन्द लाख रूपये

की ग्रांट हरिजनों के लिये रखने से उनका सुधार नहीं होने वाला है। हमारी स्टेट में आज हरिजनों की आबादी 25 लाख की है। उनके लिये अगर एक करोड़ रूपया रखते हैं तो चार रूपये फी आदमी खर्च होता है। इससे उनका क्या सुधार और तरक्की हो सकती है। इसके लिये तो खास कदम उठाने चाहिये। मैं अपनी सरकार से कहूंगा कि इस साल और आयंदा साल में हरिजनों को दूसरों के बराबर लाने के लिये खास योजनाएं बनानी चाहिएं।

स्पीकर साहब, मैं यहां पर रवाजन तो नहीं कहता बल्कि यह हकीकत बयान कर रहा हूं कि मेरा हल्का हरियाणा में बाकी इलाकों की निस्बत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मैं मिसाल के तौर पर बताऊंगा कि मेरे हल्के में एक बड़ा ब्लाक है जिस में 80 गांव हैं लेकिन उसमें सिर्फ तीन हाई स्कूल हैं और चन्द एक मिडल स्कूल हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरे हल्के में और ज्यादा स्कूल खोलने की तरफ तवज्जह दी जाये। सड़कों का तो सरकार न काफी अच्छा प्रबन्ध कर दिया है। एक हमारे इलाके में सुखचैन नहर चलती है। उसका कुछ हिस्सा बीच में पंजाब के इलाके में आ जाता है। पंजाब के लोग जो हैं उसमें से अपने इलाके में ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लेते है और हमारे यहां जो गांव टेल पर हैं उनको पूरा पानी नहीं मिलता और इसलिये वह बेहद बदहाली में हैं। पानी की कमी की वजह से वहां पर पैदावार बहुत कम होती है मगर उनको आबियाना और मामला पूरा देना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि सुखचैन नहर से पूरा पानी दिलाने का

प्रबन्ध किया जाये। पिछड़ी जातियों के लिये रिजर्वेशन नौकरियों में दो परसेंट रखी हैं जबकि पिंछडी जातियों के लोगों की आबादी 15 परसेंट बनती है। इसलिये उनकी आबादी के तनासब से रिजर्वेशन बढ़ाई जानी चाहिये। बाकी पटवारियों, मास्टरों और चौथे दर्जे के कर्मचारियों के बारे में सरकार को जल्दी फैसला कर देना चाहिये क्योंकि वे बेदिली की हालत में इस वक्त ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि स्टेट को काफी नुक्सान हो रहा है। सरकार को उनके तबादले बगैरा का जल्दी ही फैसला कर देना चाहिये। वक्त कम होने की वजह से मैं मजबूरन अपनी स्पीच बन्द करता हूं और कहता हूं कि कारवां अपनी चाल चलता रहता है चाहे जानवर इधर उधर से चिल्लाते रहें। इन अलफाज के साथ मैं कहूंगा कि जो बजट खजाना मंत्री साहिबा ने पेश किया है इसकी हमें मन्जूरी दे देनी चाहिये।

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 16th February, 1971.

6.30 p.m.

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 16th February, 1971).